R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 15
01 से 15 मई 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

ग्लोबल वार्मिंग
खतरे में पृथ्वी

जलवायु परिवर्तन के चलते इतिहास में सबसे गर्म रहे पिछले 9 साल

मौसम चक्र बिगड़ा... सूखा, बाढ़ और महामारी का खतरा बढ़ा

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

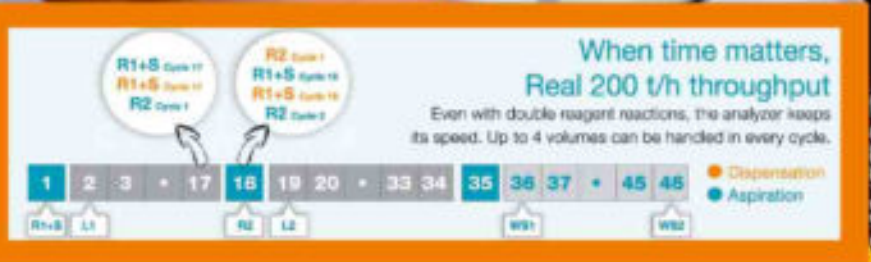

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

वल्लभगाथा

9 | आखिर मिल ही गया मुरैना को एसपी

मुरैना को लंबे समय बाद नया एसपी मिल गया है। शैलेंद्र सिंह चौहान को मुरैना का नया एसपी पदस्थ किया गया है। यह अभी तक भिंड जिले के एसपी थे। उनके स्थानांतरण आदेश जारी हो गए हैं। बता दें, कि इसी के साथ मुरैना...

राजपथ

10–11 | कमजोर सीटों पर फोकस

गुजरात की तरह मप्र में भी रिकॉर्ड जीत हासिल करने के फॉर्मूले पर काम कर रही भाजपा ने मिशन 200 पार के लिए अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत 103+57 यानी 160 सीटों को कमजोर...

योजना

15 | उज्जैन में बनेगा यूनिटी मॉल

एक जिला एक उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए केंद्र सरकार ने देश के हर राज्य में एक यूनिटी मॉल खोलने का निर्णय लिया है। इस बार के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यूनिटी मॉल स्थापित करने...

आयुष्मान

18 | आयुष्मान में 500 करोड़ का घोटाला!

गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली आयुष्मान भारत योजना को लेकर मप्र में जमकर राजनीति हो रही है। इस योजना में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रहीं हैं। कांग्रेस ने इस योजना में करीब 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

जलवायु परिवर्तन की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कहीं सूखा और कहीं बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर यह हो रहा है कि मौसम चक्र ही बिगड़ गया है। सूखा, बाढ़ और महामारी का खतरा बढ़ गया है। वहीं जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे पृथ्वी का भविष्य ही खतरे में दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का तापमान लगाता बढ़ता जा रहा है।

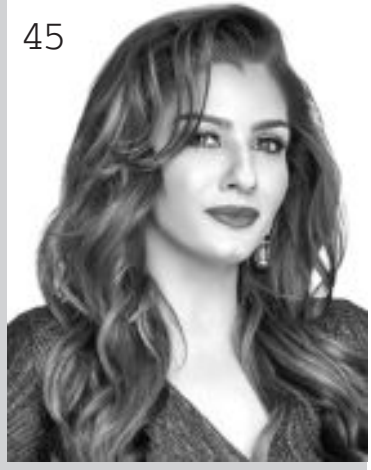

राजनीति

30–31 | कर्नाटक का असर

कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी 10 मई को राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। यह चुनाव भले ही एक राज्य में हो रहा है, लेकिन इसके परिणामों की अनुगूंज राष्ट्रीय स्तर तक सुनी जाएगी। कर्नाटक दक्षिण में भाजपा का एकमात्र दुर्ग है...

महाराष्ट्र

35 | एमवीए में रार!

लोकसभा चुनाव 2024 में भी महाविकास अघाड़ी एकजुट रहेगा, यह कहना अभी मुश्किल लग रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में महज कुछ साल पहले बने इस गठबंधन में दरारें नजर आने लगी हैं। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के नेता बेरोक-टोक बयान बाजी कर रहे हैं। अब खबरें हैं कि...

बिहार

38 | महागठबंधन में रार... ?

डीएम जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी रहे आनंद मोहन की रिहाई के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक बार फिर नए मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई से वह विपक्षी दलों के निशाने पर तो हैं ही, साथ ही जिस महागठबंधन...

6 -7 अंदर की बात
40 विदेश
41 महिला जगत
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

क्या कट्टरता की पाठशाला बन रहे मदरसे...?

किसी ने क्या खूब कहा है...

हम अनपढ़ ही सही थे, इस मोहब्बत के मदरसे में।
खामखां उलझनें बढ़ा लीं, जिहादी तालीम लेकर।।

जी हां, कभी मदरसे उर्दू तालीम की पाठशाला हुआ करते थे। हालांकि आज भी वहां उर्दू की तालीम दी जाती है, लेकिन अंधी धर्मांधता और जिहादी ताकतों ने मोहब्बत की इस पाठशाला को जिहादी तालीम का केंद्र बना दिया है। हम यह नहीं कहते कि सभी मदरसों में जिहादी तालीम दी जा रही है, लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं, जहां मासूम के मन में जहर घोला जा रहा है। इस कारण सारे मदरसे जांच के घेरे में आ गए हैं। मप्र की बात करें तो यह प्रदेश भले ही शांत है, लेकिन यह आतंकी संगठनों का स्लीपर सेल भी माना जाता है। सिमी जैसा संगठन यहीं पनपा है। इसलिए यहां के कई मदरसों पर इनका प्रभाव देखा जा सकता है। यही कारण है कि मप्र सहित देशभर के मदरसे इस समय सरकारों की नजर में हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई मदरसों में आतंकी गतिविधियां पनपने के सुराग भी मिले हैं। वैसे सरकारों की हमेशा से कोशिश रही है कि अन्य सरकारी स्कूलों की तरह मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा दी जाए। इसलिए सरकार को यह जानने का हक है कि स्कूल न जाने वाले बच्चे किस हालत में हैं और उन्हें शिक्षा प्रणाली के दायरे में शामिल करने का भी अधिकार है। वास्तव में देश में मुस्लिमों की गरीबी और पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि धर्म के नाम पर वे एक ऐसी मदरसा शिक्षा व्यवस्था के दायरे में फंस जाते हैं, जिसका लेखा-जोखा सरकारों के पास नहीं होता। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम नौजवान जो मदरसों में पढ़ते हैं, न केवल देश की मुख्यधारा की पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, बल्कि कैरियर में भी पिछड़ जाते हैं। ऐसे में सरकारों का दायित्व बनता है कि वे मुस्लिम नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखकर मदरसों को उनके समग्र मूल्यांकन के लिए बाध्य करें, ताकि वे बड़ी संख्या में नौजवान पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के मामले में जवाबदेह बनें। लेकिन वोट की राजनीति के कारण तमाम मुस्लिम नेता ही नहीं चाहते कि कोई सरकार मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाए या उन संस्थाओं को जवाबदेह बनाए, जो मुस्लिमों की शिक्षा आदि के नाम पर कई तरीकों से फंड उगाहते हैं। मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्चाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि मदरसों का सर्वे किया जाए। अब कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले अवैध मदरसों और संस्थानों का खैर नहीं होगा। प्रदेश में किसी तरह का अतिवाद और कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मदरसा बोर्ड के मुताबिक प्रदेशभर में 2689 मदरसे संचालित हैं, जबकि इनमें से कुल 1755 के पास ही डाइस कोड और मान्यता है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कार्यालय के मुताबिक भोपाल में ऐसे 479 मदरसे हैं। हालांकि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो कहीं से संबद्ध नहीं हैं। पहले मदरसों को केंद्र से ग्रांट मिलती थी, लेकिन 2014 के बाद ग्रांट मिलनी बंद हो गई, क्योंकि मदरसों के खिलाफ कई तरह की शिकायतें मिल रही थीं। मदरसों को लेकर हमेशा शिकायतें मिलती रही हैं। पिछले साल अक्टूबर में मप्र बाल आयोग ने विदिशा में मदरसा मरियम का निरीक्षण किया था। वहां 37 बच्चों में से 21 हिंदू और 5 आदिवासी थे। 5 शिक्षकों में से किसी के पास यूजी-पीजी या बीएड की डिग्री नहीं थी। इसके अलावा पिछले साल जून में भोपाल के दो मदरसों में बिहार से लाए गए बच्चे मिले थे। इससे यह शक पैदा होता है कि मदरसों में कट्टरता की पढ़ाई करवाई जा रही है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 15, पृष्ठ-48, 1 से 15 मई, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र-संपादक के नाम

मेट्रो का इंतजार

मप्र के दो बड़े शहरों में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन लोगों से अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। वे जल्द ही खुद को मेट्रो में बैठकर शहर का नजारा देखने को बेताब हो रहे हैं। इससे जहां लोगों को राहत मिलेगी, वहीं मप्र के दो शहर भी मेट्रो सिटी कहलाने लगेंगे।

● **शालिनी साहू,** इंदौर (म.प्र.)

बारिश से परेशान किसान

एक तरफ जहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। अब किसान दुविधा में है कि उसे इस नुकसान का मुआवजा कब तक मिलेगा। और कब वे फसल के कारण लिए गए कर्ज से मुक्त होगा।

● **देव राजपूत,** भोपाल (म.प्र.)

बिजली का बोझ

एक तरफ जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहीं लोगों आमदनी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। आम लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ बिजली कंपनियों ने घाटे को कम करने के लिए इसका भार एक बार फिर जनता पर डाल दिया है।

● **चंदन पांडे,** ग्वालियर (म.प्र.)

कब खत्म होगा भ्रष्टाचार?

एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को सतर्क कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कई योजनाओं में लोग गरीबों का पैसा खा रहे हैं और सरकार को चपत लगा रहे हैं। लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई थी, लेकिन कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया है। गरीबों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का देशभर में किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। आखिर ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जिससे आने वाले समय में ऐसे भ्रष्ट लोग गरीबों का हक मारने से पहले 10 बार सोचे।

● **आसिफ खान,** जबलपुर (म.प्र.)

कैसे टिकेगा गठबंधन

2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जोड़तोड़ शुरू तो हो गई है, लेकिन मुद्दा यह है कि जितनी पार्टियां साथ आने का दावा कर रही हैं, उनमें से 2024 तक कितनी पार्टियां साथ में टिक पाएंगी। क्योंकि आज हर पार्टी के प्रमुख नेता को प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे में कौन चाहेगा कि उसके गठबंधन में शामिल होने के बाद कोई और प्रधानमंत्री पद का दावेदार बने। इसलिए अब 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत रोमांचक होने वाले हैं।

● **सीमा पुरोहित,** राजगढ़ (म.प्र.)

समाज को साधने में जुटीं पार्टियां

प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां लगभग हर समाज को साधने की कोशिश कर रही हैं। मप्र की राजनीति में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग ऐसा है जिनका वोट जिस पार्टी को मिल जाता है उसकी सरकार बननी तय है। इसलिए भाजपा-कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस वोटबैंक पर नजर गड़ाए रहती है। भाजपा ने तो 2020 में सत्ता में आने के बाद से ही दलित, आदिवासी, ओबीसी को साधने की कवायद शुरू कर दी थी। कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है।

● **मयंक शिवहरे,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

एनडीए में होगी कुशवाहा की वापसी!

बिहार विधानसभा का चुनाव अभी बहुत दूर है लेकिन राज्य की सियासत अभी से सुलगने लगी है। जेडीयू से अगल होकर नई पार्टी बनाने वाले आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। कुशवाहा के साथ बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। इस सियासी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कुशवाहा की वापसी एनडीए में हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से अलग होने के बाद से ही यह कहा जाने लगा था कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का भाजपा के साथ गठबंधन हो सकता है। हालांकि न तो भाजपा और न ही कुशवाहा की तरफ से अब तक गठबंधन को लेकर स्पष्ट तौर पर कोई बात कही गई है। मगर पिछले दिनों कुशवाहा अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे तो एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों का बाजार गर्म हो गया है। गौरतलब है कि जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों बिहार के विभिन्न जिलों की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान कुशवाहा ने नीतीश सरकार की नाकामियों की जानकारी लोगों को दी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की थी।

अभिनेता से नेता बनेंगे सोनू सूद!

फिल्म अभिनेता सोनू सूद फिल्मों के अलावा अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। अगर कोई उनसे मदद मांगता है तो फिर वह उसकी मदद जरूर करते हैं। कोरोनाकाल में सोनू सूद ने सबसे ज्यादा लोगों की मदद की थी। ऐसे में अटकलें लगती रहती हैं कि सोनू सूद क्या राजनीति में भी एंट्री करेंगे, जिस पर उन्होंने इंदौर में एक बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान के बाद चर्चा जोरों पर है कि सोनू सूद अब फिल्मी दुनिया के अलावा राजनीतिक दुनिया में नजर आ सकते हैं, क्योंकि सोनू सूद ने खुद राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है। इंदौर पहुंचे सोनू ने कहा- राजनीति भी बहुत कमाल की दुनिया है, राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखता लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं कि शायद मुझे राजनीति में आना चाहिए। एक दिन के इंदौर दौरे पर पहुंचे सोनू सूद ने कहा कि इस दुनिया में वैसे तो राजनीति के बिना भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, लेकिन हालात कभी ऐसे बन जाते हैं कि आपको राजनीति में आना पड़ता है। इसलिए अगर कभी ऐसे हालात बने तो राजनीति में भी आना पड़ेगा। सोनू सूद के प्रशंसक लंबे अर्से से यह बात कहते आ रहे हैं कि उन सरीखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन खुद सोनू सूद कभी भी ऐसा कोई संकेत देने से बचते रहे हैं।

बागियों के सहारे भाजपा

जैसे-जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे राज्य की राजनीतिक आबोहवा भी बदलती जा रही है। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने नाराज लिंगायत नेताओं को मनाने में लगी है और यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद पार्टी उन तमाम लिंगायत नेताओं को मनाकर पार्टी में वापस लाएगी, जो किसी वजह से पार्टी छोड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अपने तीन दिन के कर्नाटक दौरे के पहले दिन यानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ अमित शाह ने एक बैठक भी की थी। असल में विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े लिंगायत नेता पार्टी छोड़ गए हैं। इससे भाजपा के आला नेता चिंता में हैं। उनको विधानसभा से ज्यादा चिंता अगले लोकसभा चुनाव की है। गौरतलब है कि भाजपा के बड़े लिंगायत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने पार्टी छोड़ी है। दोनों नेताओं का लिंगायत समुदाय में अच्छा असर है। कम से कम अपने जिले में दोनों नेता वोट प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन भाजपा को इन नेताओं से अब भी उम्मीद है। तभी पार्टी के नेता शेट्टार या सावदी पर हमला कर नहीं कर रहे हैं।

चाणक्य ने चिंता में डाला

राजग के खिलाफ गैर राजग दलों की एकता की कवायद दो कदम आगे बढ़ती है तो चार कदम पीछे चली जाती है। नीतीश कुमार के प्रयास से लगा था कि 2024 की चुनौती के लिए गैर राजग दल कुछ गंभीर हो रहे हैं। इस मुहिम का असली चाणक्य शरद पवार को बताया जाता है। पर, खुद पवार ही अपनी गतिविधियों के कारण एकता की मुहिम को कमजोर करते नजर आने लगते हैं। इस हफ्ते दो मुद्दों पर पवार की टिप्पणी से गैर राजग दलों का अंतर्विरोध फिर उभरा। गौतम अडाणी के स्वामित्व वाले टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में पवार ने हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी मांग को बेतुका बता दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई जांच समिति को बेहतर कहा। जबकि संसद के पिछले सत्र में तो विपक्ष का सारा हंगामा ही जेपीसी की मांग को लेकर हुआ था। इसके बाद उन्होंने गौतम अडाणी से मुलाकात भी कर ली। अडाणी पवार से उनके घर पर मिले और मुलाकात 2 घंटे चली। यह मुलाकात टीएमसी की जुझारू नेता महुआ मोइत्रा को अखरनी ही थी।

सियासत में साध्वी कहां?

उमा भारती पिछले 4 साल से सियासी वनवास पर चल रही हैं। अंदेशा था कि लोकसभा टिकट कटेगा, तो 2019 के चुनाव से पहले खुद ही ऐलान कर दिया था कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। वह भी एक दौर था जब साध्वी ने वाजपेयी सरकार से इस्तीफा देकर मप्र में भाजपा की कमान संभाली थी। उनके संघर्ष ने ही एक दशक से सूबे में सत्ता की कुर्सी पर काबिज दिग्विजय सरकार को बेदखल किया था। पर, एक अदालती मुकदमे के जाल में ऐसी उलझीं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पद वापस नहीं मिला तो बगावत कर अपनी अलग पार्टी बना डाली। नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष बने तो उमा भारती की पार्टी में सशर्त वापसी हुई। शिवराज सिंह चौहान के दबाव में मप्र की जगह उप्र को सियासी मैदान बनाने की शर्त मान 2012 में विधानसभा और 2014 में झांसी से लोकसभा सदस्य बनीं। पहली मोदी सरकार में मंत्रिपद भी पा गईं, पर अपनी अलग कार्यशैली से आलाकमान का कोपभाजन बन गईं।

हमें जो भाता है, वही चलता है...

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों कहा जा रहा है कि जिस पर माई की कृपा हो जाए, उसका भाग्य ही बदल जाता है। इसी कड़ी में 1996 बैच के राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी पर माई की कृपा इस कदर बरसी है कि उन्हें ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले की कप्तानी मिल गई है। हालांकि साहब का आईपीएस अवार्ड अगले महीने की 2 तारीख को होना है। उससे पहले ही साहब को मिली यह कृपा चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि साहब पर यह कृपा ऐसे ही नहीं बनी है, बल्कि इसके लिए उन्हें माई के एक भक्त ने जोर-आजमाइश की है। बताया जाता है कि साहब एसपी बनने से पहले जिस जिले में एएसपी थे, वहां के कलेक्टर साहब से उनकी खूब छन रही थी। कलेक्टर साहब भी माई की कृपा से चांदी काट रहे हैं। ऐसे में राज्य पुलिस सेवा के उक्त अधिकारी ने कलेक्टर साहब के माध्यम से कप्तानी के लिए जुगाड़ लगाई। जुगाड़ ने भी ऐसा काम किया कि करीब दर्जनभर वरिष्ठों के बाद भी साहब को कप्तानी मिल गई। सूत्रों का कहना है कि कप्तानी मिलने के बाद साहब ने अपने साथियों से कहा कि माई की कृपा इसी तरह बनी रहे तो मैं ऐसे ही लंबी-लंबी पारियां खेलता रहूंगा। यहां बता दें कि कलेक्टर साहब माई के समाज के ही हैं। इसलिए उनकी पहुंच माई तक आसानी से है। माई का मंत्र है कि हमें जो भाता है, वही चलता है। गौरतलब है कि साहब से ज्यादा उनकी पत्नी के माई से सामाजिक संबंध हैं।

माननीय मंत्रीजी यहां से जा सकते हैं...!

चुनावी साल में सरकार अपनों को साधने के लिए तरह-तरह के उपक्रम कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी के नेताओं को निगम मंडलों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर बैठा रही है। ऐसे ही एक नेताजी को पढ़ाई-लिखाई वाले एक निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। यही नहीं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंत्रीजी को न प्रोटोकॉल की समझ है और न ही प्रशासनिक व्यवस्था की। इस कारण कई बार मंत्रीजी को फजीहत का भी सामना करना पड़ता है। ताजा मामला मंत्रालय में सामने आया है। बताया जाता है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद माननीय पहली बार मंत्रालय गए तो उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि मंत्रालय में प्रवेश कहां से किया जाता है। इस स्थिति में उन्होंने अपने एक मातहत को यह पता लगाने के लिए भेजा कि वे मंत्रालय में कहां से प्रवेश करेंगे। जांच पड़ताल के बाद उक्त मातहत ने आकर बताया कि माननीय मंत्रीजी यहां से अंदर जा सकते हैं। जिन लोगों ने ये सुना वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने इस चुनावी साल में करीब 70 नेताओं को मंत्री का दर्जा दे दिया है। वहीं 3 दर्जन लोगों को देने की तैयारी है।

हमें तो लूट लिया...

यह कव्वाली तो आपने कई बार सुनी होगी कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने..., लेकिन 1958 की यह कव्वाली इस समय मप्र में एक बड़ी कंपनी द्वारा अलग अंदाज से गाई जा रही है- हमें तो लूट लिया मिलके ब्यूरोक्रेसी ने। इस कंपनी को राजधानी भोपाल में अरबों रुपए के कमर्शियल और रेसीडेंशियल प्रोजेक्ट का काम मिला था। शहर के हृदय स्थल पर कंपनी ने जब इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम शुरू किया तो उसे अफसरों और नेताओं ने रिकार्ड कमाई का सुनहरा सपना दिखाया। यह सपना दिखा-दिखाकर कंपनी को दुधारू गाय की तरह खूब दोहन किया गया। स्थिति यह आ गई कि कंपनी को यह प्रोजेक्ट एक दूसरी कंपनी को देकर खाली झोली लेकर लौटना पड़ा। अब स्थिति यह है कि शहर में इस प्रोजेक्ट को अब दाग की तरह देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए कई बार प्रयास भी हुए। सूत्रों का कहना है कि बड़ी उम्मीद के साथ एक बार फिर इस प्रोजेक्ट की फाइल खोली गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही बंद कर दी गई। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। उधर, सूत्रों का कहना है कि कुछ अफसर इस प्रोजेक्ट को शुरू कराने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। इनमें एक अफसर इस फिराक में लगे हैं कि उन्हें कंपनी की तरफ से अगर मोटी रकम मिल जाती है तो वे मामले को सेट कर सकते हैं। अब देखना यह है कि लुटे-पिटे इस प्रोजेक्ट को नया जीवन मिल पाता है या नहीं।

दिल लागा बंगले से

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक महिला आईएएस अधिकारी का बंगला प्रेम चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, 1992 बैच की ये मैडम वर्तमान में राजधानी में पदस्थ हैं और एक विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। लेकिन मैडम का दिल आज भी प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी में रमा हुआ है। शायद यही वजह है कि मैडम का 2 साल पहले ही भोपाल में तबादला हो गया है, लेकिन उन्होंने अपना पूर्ववर्ती बंगला नहीं छोड़ा है। सूत्रों का कहना है कि एक निगम का प्रबंध संचालक रहते मैडम को बंगले के साथ जो सुविधाएं मिली थीं, वे आज भी बरकरार हैं। यानी मैडम आज भी निगम की सारी सुविधाएं जैसे वाहन, चपरासी, सुरक्षाकर्मी आदि का सुख भोग रही हैं। हैरानी की बात यह है कि मैडम बंगले का उपयोग तो भरपूर कर रही हैं, लेकिन उसका किराया भी जमा नहीं करा रही हैं। वहीं उक्त निगम के जो नए प्रबंध संचालक हैं वे मैडम से जूनियर हैं। इस कारण वे संकोचवश मैडम से उक्त बंगला खाली करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं और मैडम हैं कि बंगला खाली करना नहीं चाहतीं।

बहना बाद में तू मत कहना

देश में अगर महिलाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए कहीं सबसे अधिक काम हुआ है और हो रहा है तो वह है देश का हृदय प्रदेश। इस प्रदेश के मुखिया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना क्रियान्वित की। जिससे प्रदेश में आज लड़कियां वरदान बन गई हैं। अब उन्होंने महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए लाड़ली बहना योजना शुरू की है। इस योजना के प्रति महिलाओं का उत्साह कितना है, इसका आंकलन इसी से किया जा सकता है कि 30 अप्रैल तक सवा करोड़ से अधिक महिलाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। दरअसल, सरकार के मुखिया चाहते हैं कि प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनें। इसलिए वे लगातार ऐसी योजनाएं बनवाते रहते हैं, जिससे प्रदेश की महिलाएं सशक्त बनें। वे तो हरदम एक ही लक्ष्य लेकर चलते हैं कि लाड़ली बहना, तुम्हें क्या चाहिए, हमें बता दो, हम वह तुम्हें दे देंगे... बाद में तुम मत कहना। वाकई सरकार का यह कदम महिलाओं के लिए क्रांतिकारी है।

मेरा लक्ष्य भाजपा को हराना है। भाजपा आज हीरो बन गई है, उसे जीरो बनाना है। इसके लिए पूरे विपक्ष को एक होना होगा। विपक्ष की एकता की राह में मेरा कोई ईगो नहीं है। अगर अपना स्वार्थ त्याग कर सब एक हुए तो भाजपा की हार तय है।

● **ममता बनर्जी**

भाजपा और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना और हमारा एजेंडा है 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना और युवाओं के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटक की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए भाजपा एक युवा टीम का निर्माण कर रही है।

● **नरेंद्र मोदी**

मैं अर्जुन तेंदुलकर से काफी ज्यादा प्रभावित हूं। एक मैच को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। उसकी नई गेंद से गेंदबाजी लाजवाब है। वह गेंद को स्विंग करा रहा है। मिडिल ओवर के हिसाब से उसकी गेंदबाजी अनुकूल है। वह अनुभव के साथ डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का मजा उठाएगा। इस आईपीएल में वह बड़ा खिलाड़ी बनेगा।

● **ब्रेट ली**

संघ किसी पर कोई वाद थोपता नहीं है। इसलिए अब संघ गैर हिंदुओं के लिए हिंदुत्व नहीं भारतीयता का एजेंडा चलाएगा। इससे लोगों में देश के प्रति जज्बा जगेगा। इससे भारत और मजबूत तथा विकसित बनेगा। यही संघ का लक्ष्य भी है।

● **मोहन भागवत**

यह सोचकर मुझे चिंता होती है कि क्या मैं अपने बच्चे और काम के साथ सही कर रही हूं। क्योंकि महिलाओं पर दोनों चीजों को अच्छे तरीके से करने का दबाव होता है। यह पुराने समय से चलता आ रहा है कि एक बार जब महिलाओं को बच्चा हो जाता है, तो उन्हें अपने कैरियर को शहीद करना पड़ता है या उन्हें एक आदर्श मां नहीं माना जाता है। नई मांओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपनी सोच को समझने के लिए समय निकालें। उन्हें क्या करना है, इसका फैसला वो खुद लें। इसके अलावा इंडस्ट्री और लोगों को भी यह समझना जरूरी है कि वो नई मांओं को समय दें।

● **आलिया भट्ट**

वाक्युद्ध

कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को देखकर केंद्र की मोदी सरकार डर गई है। जिस तरह इंदिरा गांधी को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वे उतनी ही मजबूत होकर उभरी थीं, ऐसा ही राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है। राहुल के प्रति देश में विश्वास जगा है। इससे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं।

● **प्रियंका गांधी**

राहुल गांधी भले ही 55 के हो गए हैं, उनमें अभी भी बचपना भरा पड़ा है। तभी तो वे बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देते हैं। अगर वे परिपक्व नेता होते तो आज उनकी सांसदी खत्म नहीं हुई होती। प्रियंका गांधी को अभी राहुल गांधी को भारत और भारतीयता के बारे में सिखाने की जरूरत है। तभी वे राजनीति में चल पाएंगे।

● **स्मृति ईरानी**

आखिर मिल ही गया मुरैना को एसपी

मुरैना को लंबे समय बाद नया एसपी मिल गया है। शैलेंद्र सिंह चौहान को मुरैना का नया एसपी पदस्थ किया गया है। यह अभी तक भिंड जिले के एसपी थे। उनके स्थानांतरण आदेश जारी हो गए हैं। बता दें, कि इसी के साथ मुरैना के पूर्व एसपी आशुतोष बागरी को पुलिस मुख्यालय भोपाल से वापस भिंड भेजा गया है। वे वहां 17वीं वाहनी बिसबल में बतौर कमाडेंट रहेंगे। बता दें, कि एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को भी भिंड जिले में बतौर एसपी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उनकी तेज-तर्रार छवि को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले की कमान सौंपी हैं। भिंड जिले में भी उनका कार्यकाल निष्पक्ष एवं कारगर रहा जिसको देखते हुए उन्हें मुरैना जिला दिया गया है।

बता दें, कि एसपी आशुतोष बागरी के जाने के बाद मुरैना जिले के लिए नए एसपी को भेजे जाने पर भाजपा के दोनों धड़ों शिवराज भाजपा व महाराज भाजपा के पदाधिकारियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। एक धड़ा जो जिस एसपी का नाम सुझाता तो दूसरा धड़ा उस पर अपनी नाराजगी जता देता, इस कश्मकश में लगभग आधे महाने से अधिक समय बीत गया था। जिला खाली था तथा एएसपी रायसिंह नरवरिया प्रभारी एसपी के रूप में उसे बखूबी चला रहे थे, लेकिन उनका आईपीएस अवार्ड नहीं हुआ है जिसकी वजह से राज्य शासन को दूसरा एसपी भेजना पड़ा। मुरैना के नए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान का नाम सुनकर मुरैना के पुलिस अधिकारियों में कसावट देखी जा सकती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कितनी कसावट रहेगी। फिलहाल महकमे में नए एसपी को लेकर गर्माहट फैल गई है।

● **कुमार विनोद**

रापुसे-भापुसे की डीपीसी

एसपीएस से आईपीएस अवार्ड के लिए 2 मई को दिल्ली में डीपीसी होगी। यह डीपीसी 2 साल से खाली 16 पदों के लिए हो रही है। डीपीसी के दौरान आईपीएस के 16 पदों के लिए तीन गुने यानी 48 अफसरों के नाम शामिल होंगे। इनमें राज्य पुलिस सेवा 1995 बैच के 2 अफसरों के अलावा 1996 और 1997 बैच के अफसरों के नाम शामिल होंगे। दो साल से खाली पड़े 16 पदों के लिए डीपीसी होना है। जिसमें 1996 और 1997 बैच की एक साथ डीपीसी होगी। लिस्ट में शुरूआती दो नाम 1995 बैंच के अफसरों के हैं। कोर्ट में मामला विचाराधीन होना, ओवर एज होना और विभागीय जांच के कारण 8 अफसरों के लिफाफे बंद रहने की संभावना है। इन नामों में देवेंद्र सिरोलिया 59 साल, गोपाल प्रसाद खांडेल की उम्र 60 साल से ज्यादा और मुन्नालाल चौरसिया भी 60 साल के हो चुके हैं। इसलिए उनके नामों को शामिल नहीं किया जाएगा। विभागीय जांच के कारण प्रकाश चंद्र परिहार के नाम पर विचार नहीं होगा। यही स्थिति विनोद कुमार सिंह और सीताराम ससत्या के साथ है। इनके मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। अरुण कुमार मिश्र की विभागीय जांच हुई थी। हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है। शासन उसके खिलाफ डबल बैंच में चला गया है। ऐसी स्थिति में उनके नाम पर विचार संभव नहीं है। पुरानी विभागीय जांच के कारण अवधेश प्रताप सिंह का भी लिफाफा नहीं खोला जाएगा। सबकुछ ठीक रहा तो 16 खाली पदों के लिए मनीष खत्री, राजेश कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार मेहता, वीरेंद्र जैन, देवेंद्र कुमार पाटीदार, राय सिंह नरवरिया, रामशरण प्रजापति, सुंदर सिंह कनेश, राजेश व्यास, पद्म विलोचन शुक्ला, सुधीर कुमार अग्रवाल, पंकज कुमार पांडेय, अजय पांडेय, संजय कुमार अग्रवाल, दिलीप सोनी और राजेंद्र कुमार वर्मा के नामों को शामिल किया जा सकता है। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों से आईपीएस की वर्ष 2022 में एक ही वैकेंसी निकली थी। जबकि इस वर्ष की डीपीसी में 6 अफसरों का आईपीएस अवार्ड होना है। दरअसल पिछले साल जून में आईपीएस कॉडर रिव्यू हुआ था, जिसमें राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस अवार्ड के लिए 5 पदों का इजाफा हुआ था। इसके चलते इन अफसरों को 5 पद और मिल गए।

डीएसपी से एएसपी की हो गई डीपीसी

प्रदेश के पुलिस विभाग में डीएसपी से एएसपी बनाने के लिए डीपीसी पूरी हो गई है। 36 डीएसपी को एएसपी बनाया गया है। हालांकि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। उधर, लिस्ट आते ही अफसरों को नई पोस्टिंग दी जाएगी। उधर, प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रमोशन के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में एडीजी वीके महेश्वरी सहित दो अफसरों को सदस्य बनाया गया है। एएसआई, एसआई से इंस्पेक्टर के पदों पर एडहॉक प्रमोशन मिलेगा। सरकार 15 से 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले पुलिसकर्मियों को समयमान-वेतनमान देगी। इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया है। इस समिति में पुलिस महानिदेशक (एसटीएफ एवं दूरसंचार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अध्यक्ष, चैत्रा एन पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत एवं मानव अधिकार पुलिस मुख्यालय भोपाल और हेमंत चौहान सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एससीआरबी), पुलिस मुख्यालय भोपाल को सदस्य बनाया गया है।

ईओडब्ल्यू को मिलेंगे 6 डीएसपी

आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू को काफी प्रतीक्षा के बाद अब जाकर 6 डीएसपी मिलेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश की इस महत्वपूर्ण जांच एजेंसी में अधिकारियों की लगातार कमी चल रही है। अब जाकर 6 डीएसपी विभाग को मिलने वाले हैं। उधर, प्रदेश में चुनाव में सीनियर आईपीएस अफसरों की कमी होने वाली है। क्योंकि 2023 के अंत तक 16 सीनियर आईपीएस अफसर रिटायर्ड होंगे। मप्र में वर्तमान में 38 एडीजी में से 17 अफसर डेपुटेशन पर हैं। 2023 के अंत तक 15 स्पेशल डीजी और एक एडीजी रिटायर्ड होंगे। पुलिस मुख्यालय की कई ब्रांच सीनियर आईपीएस अफसरों की कमी के चलते खाली रहेंगी। एडीजी और स्पेशल डीजी पर प्रमोशन होने वाले अफसरों की संख्या कम है। यदि इनकी जगह पर दूसरे अफसरों की पोस्टिंग नहीं की गई है, तो चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था में कमी देखने को मिल सकती है।

अबकी बार 200 पार की रणनीति पर चुनावी तैयारी में जुटी भाजपा और संघ ने मिलकर प्लान तैयार किया है कि अगर इस बार मप्र में गुजरात की तरह रिकॉर्ड जीत अर्जित करनी है तो कमजोर सीटों को जीतना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि 2018 में भाजपा जिन सीटों पर हारी थी, उन सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही पार्टी ने वर्तमान में जिन 124 सीटों पर कब्जा कर रखा है, उनमें से भी 57 सीटों को चिन्हित किया है, जिन्हें कमजोर की श्रेणी में रखा गया है। यानी भाजपा तकरीबन 160 सीटों को कमजोर मानकर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि इस रणनीति के तहत इस बार मप्र में भाजपा 200 सीटें जरूर जीतेगी।

कमजोर सीटों पर फोकस

गुजरात की तरह मप्र में भी रिकॉर्ड जीत हासिल करने के फॉर्मूले पर काम कर रही भाजपा ने मिशन 200 पार के लिए अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत 103+57 यानी 160 सीटों को कमजोर मानकर इनको जीतने का फॉर्मूला तैयार किया है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि अगर इन सीटों को जीत लिया गया तो इस बार मप्र में भाजपा जीत के सारे रिकॉर्ड बना लेगी। जानकारों का कहना है कि नई रणनीति पर भाजपा ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल, साल 2018 के आम चुनाव में नंबर गेम में पिछड़ने के बाद भाजपा ने अब इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर हारी हुई 103 सीटों को जीतने के लिए रणनीति पहले ही बना ली है। साथ ही इस अभियान में पार्टी ने 57 ऐसी अन्य सीटों को भी जोड़ लिया है जहां पार्टी अपने आप को कमजोर मान रही है। इन 160 विधानसभाओं को जीतने के लिए भाजपा ने रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इन्हीं सीटों पर हारे हुए बूथों को जीतने से लेकर प्रत्याशियों के चयन की एक्सरसाइज भी संगठन ने शुरू की है।

भाजपा संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद आए परिणामों की समीक्षा में 124 सीटें ऐसी थीं जिन्हें **आकांक्षी की श्रेणी** में चिन्हित किया गया था। लेकिन 2018 से अब तक हुए 34 सीटों के उपचुनाव ने बाजी पलट दी। भाजपा को इन 34 उपचुनावों में से 21 सीटों को जीतने में कामयाबी मिली। इन उपचुनाव में कुछ सीटें ऐसी थीं जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गए थे। इस तरह पार्टी ने कुछ 160 ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जिन्हें पार्टी हर हाल में जीतने का प्रयास करेगी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि ये वे सीटें हैं जहां भाजपा को जीतने के लिए दमदारी से किला लड़ाना पड़ेगा। यानी ये सीटें काफी टफ हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार वह 70 सीटों पर काफी मजबूत है। यानी भाजपा इन सीटों को जीता मानकर चल रही है। ये सीटें वह हैं जहां भाजपा पिछले तीन या उससे अधिक बार से चुनावों में हारी नहीं है।

जाहिर है भाजपा के रणनीतिकार इस बार मुकाबला बेहद कठिन मान रहे हैं। ऐसे में पार्टी का पूरा फोकस 160 सीटों पर रहेगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41 फीसदी और कांग्रेस को 40.9 फीसदी मत मिले थे। भाजपा केवल 4337 वोटों के कारण 7 सीटों पर हार गई थी। इस कारण उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी। पिछले चुनाव में 18 सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा 1000 के लगभग अंतर से हारी। 30 सीटें ऐसी थीं जहां पार्टी को 3000 से कम मतों से पराजय का मुंह देखना पड़ा। 45 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच 3 से 5000 वोटों का अंतर था यह सभी सीटें भाजपा हार गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर दक्षिण ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने भाजपा उम्मीदवार को मात्र 121 मतों से हराया था। इसी तरह सुवासरा सीट पर भाजपा 350 मतों से हारी थी। कुल मिलाकर 7 सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा 500 से कम मतों से हारी थी। पार्टी ने क्षेत्र के अनुसार तथा पिछले चुनाव के

नई जिम्मेदारी, अब परफॉर्मेंस की बारी

मप्र में बड़ी जीत के साथ सत्ता में कायम रखने के लिए भाजपा ने संगठन में कसावट शुरू कर दी है। इसके लिए हर एक पदाधिकारी की परफॉर्मेंस का आंकलन हो रहा है। जिसकी परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। दरअसल, संघ और संगठन की बार-बार की हिदायत के बाद भी जिन नेताओं ने अपनी परफॉर्मेंस को नहीं सुधारा है उनसे वह पद लेकर दूसरे को जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही निर्देश दिया जा रहा है कि यह नई जिम्मेदारी इसलिए दी गई है कि अब परफॉर्मेंस की बारी है। जानकारी के अनुसार चुनावी साल में संगठनात्मक कसावट के लिए अब तक की गई सर्जरी में डेढ़ दर्जन जिलाध्यक्ष बदले जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार पांचवीं बार सत्ता में आने के लिए भाजपा ने गत वर्ष जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवाई थी। जिसके आधार पर बीते चंद महीनों से भाजपा धीरे-धीरे करके चुनाव के हिसाब से सर्जरी कर रही है। अब तक 18 जिलाध्यक्ष बदले जा चुके हैं। 6 से ज्यादा जिलाध्यक्ष रडार पर हैं। 6 संभागीय प्रभारी भी खराब परफॉर्मेंस के कारण बदले गए हैं।

रिकॉर्ड के आधार पर मप्र की विधानसभा सीटों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। पार्टी उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है।

भाजपा ने 200 सीटें जीतने के लिए 51 फीसदी वोट का टारगेट रखा है। दरअसल, भाजपा 2018 की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती। इस कारण से उसने पूरा फोकस आदिवासियों, दलितों, महिलाओं और युवाओं पर कर रखा है। एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए 40 फीसदी तक मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। खासतौर पर उन विधायकों के टिकट खतरे में हैं जिनकी उम्र हो चुकी है और जो चार या पांच बार से विधायक हैं। इसके अलावा पिछली बार कम अंतर से जीते विधायकों को भी रेड जोन में रखा गया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में **एकजुटता** के साथ ही नाराज और रूठे हुए कार्यकर्ता और नेताओं को मनाने में भी लगी हुई है। इसके लिए सभी दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। पार्टी का पूरा चुनाव अभियान केंद्रीय रणनीति के हिसाब से चल रहा है। गौरतलब है कि 2020 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 2018 में हारी इन 21 सीटों जौरा, अम्बाह, मेहगांव, ग्वालियर, भांडेर, पोहरी, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुरखी, पृथ्वीपुर, बड़ामलहरा, अनूपपुर, सांची, हाटपिपल्या, मांधाता, नेपानगर, जोबट, बदनावर, सांवेर और सुवासरा को जीत लिया है। लेकिन पार्टी इन्हें भी चुनौतीपूर्ण मानकर चल रही है। एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबले के लिए भाजपा ने मप्र में कई स्तरों पर रणनीति तैयार की है। पार्टी नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करने के साथ जोर इस बात पर है कि आम लोगों के बीच पहुंचा जाए। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनावों में नए चेहरों को मौका देने के लिए 40-45 प्रतिशत विधायकों के टिकट कट सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वे विद्रोह पर उतर आए। मप्र में भाजपा इस हालत को दोहराना नहीं चाहती। यह भी सच है कि राज्य में पार्टी आंतरिक मतभेदों से त्रस्त है। इन्हें दूर करने की कोशिशें अभी से शुरू हो चुकी हैं। गुजरात में भाजपा साल 1995 से ही लगातार सत्ता में है। मप्र में भी 2003 से लेकर 2018 तक पार्टी लगातार सत्ता में रही। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन विधायकों के दलबदल के कारण 15 महीने बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि गुजरात फॉर्मूले के सहारे मप्र में भी एंटी इनकम्बेंसी से पार पाया जा सकता है।

मप्र में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल 2018 के आम चुनाव में नंबर गेम में पिछड़ने के बाद भाजपा ने अब इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर हारी हुई 103 सीटों को जीतने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इन हारी हुई 103 विधानसभाओं को जीतने के लिए भाजपा ने रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इन्हीं सीटों पर हारे हुए बूथों को जीतने से लेकर प्रत्याशियों के चयन की एक्सरसाइज भी संगठन ने शुरू की है। इन सीटों को आकांक्षी विधानसभा नाम दिया गया है। ये 103 विधानसभाएं भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई हैं। इनमें श्योपुर, सबलगढ़, सुमावली, मुरैना, दिमनी, भिंड, लहार, गोहद, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार, डबरा, सेंवड़ा, करेरा, पिछोर, चाचौड़ा, राघोगढ़, चंदेरी, देवरी, बंडा, महाराजपुर, राजनगर, छतरपुर, बिजावर, पथरिया, दमोह, गुनौर, चित्रकूट, रैगांव, सतना, सिंहावल, कोतमा, पुष्पराजगढ़, बड़वारा, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर पश्चिम, शहपुरा, डिंडोरी, बिछिया, निवास, बैहर, लांजी, वारासिवनी, कटंगी, बरघाट, लखनादौन, गोटेगांव, तेंदूखेड़ा, गाडरवारा, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर, छिंदवाड़ा, परासिया, पांढुर्णा, मुलताई, बैतूल, घोड़ाडोंगरी, भैंसदेही, उदयपुरा, विदिशा, भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण-पश्चिम, भोपाल मध्य, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, सुसनेर, आगर, शाजापुर, कालापीपल, सोनकच्छ, बुरहानपुर, भीकनगांव, बड़वाह, महेश्वर, कसरावद, खरगोन, भगवानपुरा, सेंधवा, राजपुर, पानसेमल, अलीराजपुर, झाबुआ, थांदला, पेटलावद, सरदारपुर, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी, देपालपुर, इंदौर -1, राऊ, नागदा, तराना, घट्टिया, बड़नगर, सैलाना, आलोट आदि सीटें शामिल हैं।

वहीं कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां भाजपा को जीत आसान लग रही है। इनमें ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक महज 121 वोटों से जीत पाए थे। इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाह चुनाव हार गए थे। करीब से हुई हार के बाद भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए बूथ लेवल वर्कर्स की टीम दुरुस्त करने पर फोकस कर रखा है।

● **कुमार राजेन्द्र**

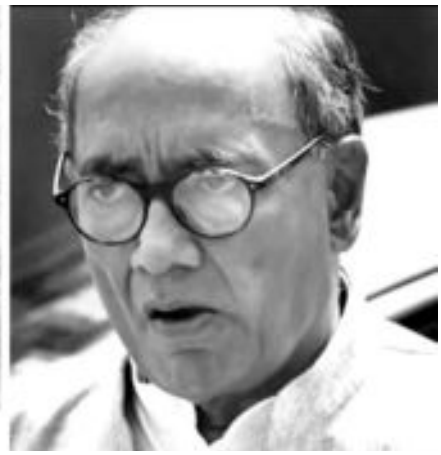

सहकारी संस्थाओं में नेता होंगे एडजस्ट

चुनावी साल में अपनों को सक्रिय करने के लिए भाजपा सरकार ने सहकारी संस्थाओं में नेताओं को प्रशासक के तौर पर नियुक्ति देने की तैयारी कर ली है। मप्र के 37 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और 4 हजार 526 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। बैंकों के चुनाव 2013 से नहीं हुए हैं। नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस वर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनाव होने की संभावना भी कम ही है। इसे देखते हुए सहकारी संस्थाओं से जुड़े नेताओं को प्रशासक बनाने की तैयारी सत्ता और संगठन के स्तर पर की जा रही है। इसके लिए जिन्हें प्रशासक बनाया जाना है, उनकी जानकारी बैंकों से बुलाई गई है। अपेक्स बैंक का प्रशासक विदिशा से सांसद रमाकांत भार्गव को बनाया जा सकता है। वे 2018 के विधानसभा चुनाव के समय भी प्रशासक थे लेकिन कांग्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग में शिकायत किए जाने पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। भार्गव दो बार राज्य सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार जब तक सभी ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति (पेक्स) का गठन नहीं होगा, तब तक प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हो सकते। प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव होने के बाद ही बैंकों के चुनाव हो सकते हैं। तब तक बैंकों के चुनाव भी संभव नहीं होंगे। मप्र में लगभग 23000 ग्राम पंचायतें हैं। अभी सहकारिता विभाग में केवल 4500 पेक्स हैं। प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव 5 वर्ष में कराने का प्रविधान है लेकिन 2018 से सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं।

हाईटेक तरीके से खनिज परिवहन की निगरानी

इस बार लक्ष्य से अधिक खनिज राजस्व प्राप्त

खनिज संपदा के अवैध परिवहन को लेकर सरकार पिछले कुछ सालों से सख्त है। इसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज विभाग को निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 101 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग के लिए राजस्व लक्ष्य 8110 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके विरुद्ध विभाग को 8201 करोड़ 50 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। विभाग को मुख्य खनिजों से 4200 करोड़ रुपए, गौण खनिजों से 3170 करोड़ और ग्रामीण अवसंरचना मद से 831 करोड़ 50 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। हमारा प्रदेश एक खनिज बहुल प्रदेश है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मुख्य खनिजों में मुख्यतः कोयला, चूना पत्थर, मैगनीज, कॉपर, आयरन, हीरा और गौण खनिज- डोलोमाइट, लेटराइट, पायरोफिलाइट, ग्रेनाइट, मार्बल, गिट्टी, रेत, फर्शी पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। मंत्री ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश को खनिज संपदा से 7122 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुई थी। इस वर्ष राजस्व प्राप्ति विगत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

मप्र खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। प्रदेश सरकार को खनिज संपदा से बड़ा राजस्व मिलता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार को जितना राजस्व मिलता है, उससे अधिक का अवैध परिवहन हो जाता है। इसलिए सरकार ने खनिज परिवहन की हाईटेक निगरानी करने की नीति बनाई है। इसके लिए प्रदेश में सरकार नई खनिज नीति का प्रारूप तैयार कर रही है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि रेत के अवैध परिवहन पर लगाम लगाई जाए। इसके लिए चैकिंग सिस्टम को हाईटेक बनाया जा रहा है। वहीं रेत खनन से पहले एनवायरमेंट क्लीयरेंस (ईसी) की दिक्कतों को दूर करने के लिए खनिज विभाग अब खुद ईसी लेने की तैयारी कर रहा है। नई रेत नीति में इसे शामिल किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार हुए 1400 रेत खदानों के टेंडर में सिर्फ 500 से ही ठेकेदार रेत निकाल पाए। 30 जून 2023 के बाद फिर टेंडर होने हैं, इसलिए इस बार सरकार कोशिश में है कि सारी खदानें एक्टिव हों।

गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाती रही है। उसके बाद भी अवैध परिवहन पर रोक नहीं लग सकी है। इसको रोकने के लिए अब शहरों के एंट्री पाइंट पर अत्याधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे। इनकी मदद से डंपर-ट्रकों में तय लिमिट से ज्यादा रेत होने पर तुरंत पता चल जाएगा। इसका मैसेज मय वाहन के नंबर के साथ तुरंत कंट्रोल रूम पहुंच जाएगा। जहां से संबंधित वाहन चालक को चालान भेजा जाएगा। इस सिस्टम का एक और फायदा यह होगा कि मैन्युअली चैकिंग में होने वाली गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।

मप्र में नई रेत नीति को बनाने से लिए सरकार ने उप्र मॉडल का अध्ययन करवाया है। दरअसल, मप्र में अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार उप्र मॉडल अपनाने जा रही है। जिसके तहत 44 जिलों के एंट्री पाइंट पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट बनाए जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक गेट के रिकार्ड में वाहन मालिक, खनिज समेत पूरा डेटा रहेगा। योजना के तहत खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों में माइनटैग लगाया जाएगा। खनिज अधिकारी को भी हंड होल्ड एमचेक मशीन प्रोवाइड कराई जाएगी। जिसकी मदद से ओवर लोडिंग करने वाले वाहन चालकों का चालान काटा जाएगा। राजधानी में यह गेट 11 मील पर बनाया जा रहा है। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों के कैमरे के सामने आते ही सारी जानकारी कंट्रोल रूप में पहुंच जाएगी। तय सीमा से अधिक खनिज परिवहन होने पर वाहन मालिक को चालान पहुंच जाएगा। चालान जमा नहीं करने पर 7 दिन में मामला कोर्ट पहुंच जाएगा।

खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट की व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। कैमरों में वाहनों का लेखा-जोखा होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर चालान जाएगा। इस गेट की मदद से ओवर लोडिंग सहित खनिज के अवैध परिवहन पर भी रोक लग सकेगी। खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए वर्तमान में जिलों में खनिज चौकियां हैं। जहां पर मौजूद अमला आने वाले वाहनों की जांच करता है। हालांकि खनिज चौकियों में वसूली के आरोप भी लगते रहे हैं। खुद रेत परिवहन करने वाले वाहन मालिकों ने इसे लेकर खनिज मंत्री से शिकायत की थी। यही कारण है कि नई खनिज नीति में इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट लगाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर विभाग ने सभी तैयारियां भी कर ली है। भोपाल की बात करें तो करीब पांच साल पहले 11 मील के पास चौकी बनाई गई थी। इसमें खनिज के साथ ही राजस्व व वन विभाग के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था। कुछ समय तक जांच चली, लेकिन दुर्घटना में एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद मामला ठंडा पड़ गया। यहां कभी कभार ही अमला नजर आता है। ऐसी ही स्थिति अन्य जगह पर भी है। इसको देखते हुए अब इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट लगाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मप्र खनिज संपदा की दृष्टि से देश का खनिज संपन्न राज्य है। प्रदेश में लगभग सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तथा उनका खनन भी किया जाता है। मप्र के सकल राजस्व में खनिज राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान है। विभाग की उद्योग मित्र नीति एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग से विभाग का खनिज राजस्व विगत 15 वर्ष में 15 गुना बढ़ चुका है, जो कि एक उपलब्धि है।

● **सुनील सिंह**

बैंस का इकबाल फिर होगा बुलंद!

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को एक बार फिर से 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसकी संभावना इसलिए बढ़ गई है कि अगले मुख्य सचिव के दावेदार अनुराग जैन को केंद्र सरकार मप्र भेजने को तैयार नहीं है। केंद्र ने मप्र कैडर के 1989 बैच के अधिकारी अनुराग जैन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे भरोसेमंद अधिकारी इकबाल सिंह बैंस को एक बार फिर से 6 माह की सेवावृद्धि मिल सकती है।

गौरतलब है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का 6 माह का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है। उधर, केंद्र सरकार ने अगले मुख्य सचिव के सबसे बड़े दावेदार अनुराग जैन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी है। अनुराग जैन का पिछले साल मप्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नाम चर्चा में रहा था क्योंकि 30 नवंबर 2022 को इकबाल सिंह बैंस रिटायर हो रहे थे। मगर बैंस के रिटायरमेंट के अंतिम दिन 30 नवंबर को उनको 6 महीने के लिए सेवावृद्धि दे दी गई और अब 30 मई को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। बैंस की सेवावृद्धि के 6 महीने पूरे होने के पहले भारत सरकार ने तबादला आदेश जारी कर एक बार फिर संकेत दे दिए हैं कि जैन को फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी नहीं दी जाएगी। ऐसे में बैंस को फिर 6 महीने की सेवावृद्धि मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रशासनिक सर्जरी के बाद संभावना बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की जोड़ी ही अगला विधानसभा चुनाव कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी चुनावी साल में अपने विश्वासपात्र इकबाल सिंह बैंस को ही चीफ सेक्रेटरी रखना चाहते हैं। इसलिए सरकार 6 महीने का फिर से एक्सटेंशन देने की तैयारी में है। बता दें कि मई में इकबाल सिंह बैंस का टेन्योर खत्म हो रहा है। एक्सटेंशन मिलने पर इकबाल सिंह नवंबर तक चीफ सेक्रेटरी के पद पर पदस्थ रहेंगे। पिछले साल नवंबर में डीओपीटी ने एक्सटेंशन दिया था। बैंस मप्र के पांचवें चीफ सेक्रेटरी होंगे जो 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। बैंस की सेवावृद्धि के 6 महीने पूरे होने के पहले भारत सरकार ने तबादला आदेश जारी कर एक बार फिर संकेत दे दिए हैं कि जैन को फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी नहीं दी जाएगी। ऐसे में बैंस को फिर 6 महीने की सेवावृद्धि मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

इनके नाम भी चर्चा में

प्रदेश में अगले मुख्य सचिव के लिए अनुराग जैन के अलावा 1988 बैच की वीरा राणा और 1989 बैच के मोहम्मद सुलेमान का नाम भी चर्चा में रहा है। लेकिन इन दोनों की दावेदारी कमजोर है। क्योंकि सुलेमान भाजपा और संघ के फ्रेम में फिट नहीं बैठते हैं। वहीं वीरा राणा की अब तक की परफॉर्मेंस मुख्य सचिव के काबिल नहीं पाई गई है। 1989 बैच के मोहम्मद सुलेमान ने कोरोना महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुलेमान रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी हैं। उन्होंने बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में लंबे समय तक विभिन्न पदों पर काम किया है और कई नवाचार करते हुए परिणाम भी दिए हैं। सेवाकाल की दृष्टि से उनका भी कार्यकाल अनुराग जैन के समान ही है। सुलेमान अनुराग जैन के 1 महीने पहले जुलाई 2025 में रिटायर होंगे। लेकिन भाजपा और संघ के नजरिए से वे फ्रेम में फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए इनका मुख्य सचिव बनना असंभव सा लग रहा है। इनके अलावा अजय तिर्की, संजय बंदोपाध्याय, आशीष उपाध्याय, जेएन कंसोटिया, राजेश राजौरा, एसएन मिश्रा का भी नाम चर्चा में है। भारत सरकार ने गत दिनों 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना आदेश जारी किए हैं, जिसमें मप्र कैडर के तीन अधिकारी शामिल हैं। 1989 बैच के अधिकारी अनुराग जैन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, भारत सरकार के आईएएस अधिकारियों के नए पदस्थापना आदेश में 1990 बैच की अलका उपाध्याय भी प्रभावित हुई हैं।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारी भी हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच अच्छा सामंजस्य है। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1985 बैच के आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह बैंस को सीएस बनाया था। इसके लिए 6 अधिकारियों की वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया था। वह मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं। बैंस जुलाई 2013 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव बनकर चले गए थे, तो उन्हें सरकार बनने के बाद अगस्त 2014 में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह करके वापस बुलाया और अपना प्रमुख सचिव बनाया था। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को सख्त प्रशासक माना जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करके उन्होंने यह साबित भी किया है। देश में पहली बार आनंद विभाग का गठन भी उनकी ही पहल पर हुआ था। वे कृषि, उद्यानिकी, ऊर्जा, विमानन, आबकारी आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य जैसे विभागों में काम कर चुके हैं। वे सीहोर, खंडवा, गुना और भोपाल कलेक्टर भी रहे हैं।

मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते थे कि इकबाल सिंह बैंस ही मुख्य सचिव रहें, ताकि जो कार्ययोजना तैयार की गई है, उस पर तेजी से अमल हो सके। ऐसे में माना जा रहा है एक बार फिर मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी कि इकबाल को एक और एक्सटेंशन दिया जाए। उधर, इस पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे 1989 बैच के अधिकारी अनुराग जैन को केंद्र सरकार नहीं छोड़ रही है।

● **जितेंद्र तिवारी**

विकास से बदलेगी भोपाल की तस्वीर

देश सहित मप्र में सड़कों का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई सड़क निर्माण में लगातार गति बनाए हुए है। इसी कड़ी में मप्र में एक बार फिर से विकास कार्य की शुरुआत हो चुकी है। एनएचएआई द्वारा कई प्रोजेक्टों का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत मिसरोद से रत्नागिरी तक 6 लेन सड़क बनाई जाएगी। करीब 32 किमी की यह सड़क सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देश पर बनेगी। इस सड़क की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए मंत्रालय ने टेंडर भी निकाल दिया है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का काम जून-जुलाई में संभवत: शुरू हो जाएगा।

वहीं रत्नागिरी से लेकर सिंधिया चौराहे तक की सड़क को एनएचएआई बनाएगा। हालांकि अभी इसका टेंडर नहीं निकाला गया है। माना जा रहा है कि दिसंबर में टेंडर निकाला जाएगा। यह काम 3 वर्ष में पूरा करना है। जानकारी के अनुसार रत्नागिरी से लेकर आसाराम तिराहा तक 20 किमी लंबे फोरलेन अयोध्या बायपास को 8 लेन किए जाने की तैयारी भी की गई है। इसके अलावा गोपालपुरा फ्लाईओवर तैयार किए जाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है जबकि अकेले अयोध्या बायपास पर 5 फ्लाईओवर तैयार किए जाने हैं।

एनएचएआई ने मुबारकपुर जोड़ से लालघाटी चौराहे तक सड़क के फ्लाईओवर निर्माण के लिए अपने प्रोजेक्ट में आसाराम बापू चौराहा तक सड़क परियोजना की तैयारी की है। हालांकि आगे क्षेत्र के रत्नागिरी तक अयोध्या बायपास 4 लेन है। भेल और अयोध्या बायपास क्षेत्र में एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की सुविधा के कारण इसका चौड़ीकरण और चौराहे पर ग्रेंड सेपरेटर फ्लाईओवर निर्माण कार्य को बेहद जरूरी माना गया है। बीते दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल में 8 लेन की जरूरत का मुद्दा उठाया और आज एनएचएआई को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले में एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर विवेक जायसवाल का कहना है कि अयोध्या बायपास को 8 लेन करने का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के सहयोग से इसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य फ्लाईओवर आदि के साथ भी इसे जोड़े जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसका फायदा पूरे क्षेत्रवासियों को होना है।

इसके अलावा रत्नागिरी पर एक नया टी-जंक्शन भी तैयार किया जाएगा। इसे आनंद नगर पिपलानी और प्रभात चौराहे से जोड़ने की तैयारी भी की गई है। साथ ही आनंद नगर पिपलानी और प्रभात चौराहे से लेकर आईएसबीटी पर बनने वाले अलग-अलग फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी से शहर के विभिन्न हिस्से में पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट में 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही आईटीआई तिराहा से लेकर जेके रोड तिराहा, अन्ना नगर से कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज, गौतम नगर होते हुए आईएसबीटी पर भी फ्लाईओवर तैयार किए जाने की तैयारी पूरी की गई है। प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग और केंद्र की **सेतुबांध परियोजना** के तहत पहले से प्रस्तावित फ्लाईओवर के साथ इसे जोड़ा जाएगा। वहीं राजधानी की शान कही जाने वाली वीआईपी रोड की रौनक अब और अधिक बढ़ने वाली है। इसे जल्द ही 8 लेन किया जाएगा। इसमें दो लेन लालघाटी चौराहे से सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। यह लालघाटी से एलीवेटेड रहेगी। इसके प्रोजेक्ट को फाइनल स्वरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्तर पर भी 28 मार्च को इसकी प्रारंभिक सहमति दे दी गई है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने भोपाल-इंदौर कॉरीडोर को लेकर नई प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके तहत इंदौर रोड से भोपाल आने के लिए बिना संत हिरदाराम नगर-लालघाटी से गुजरे सीधे भोपाल में फ्लाईओवर से एंट्री होगी। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में इसे मंजूरी भी दे दी गई है।

● **राकेश ग्रोवर**

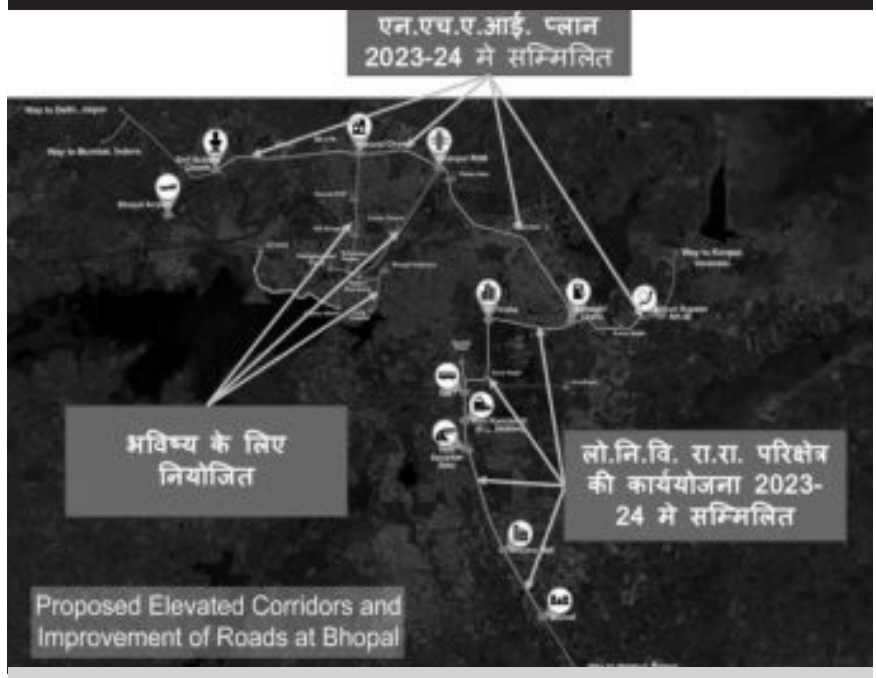

कनेक्टिव ट्रांजिट पाइंट बनेगा

कमला पार्क से शुरू 6 लेन का लालघाटी चौराहे व खानूगांव पर कनेक्टिव ट्रांजिट पाइंट बनेगा। यहां पर फ्लाईओवर पर कनेक्टिंग ट्रांजिट ऐसा रहेगा कि एक सिरा कमला पार्क उतरेगा, एक सिरा इंदौर रोड पर और एक सिरा एयरपोर्ट रोड तक पहुंचेगा। इंदौर रोड वाले सिरे के चलते बैरागढ़ जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इंदौर रोड से बैरागढ़ के पहले ही फ्लाईओवर बनेगा। यह 8 लेन वीआईपी रोड पर कनेक्ट रहेगा। खानूगांव पर इस ब्रिज की कनेक्टिविटी रहेगी। इसे लोक निर्माण विभाग बनाएगा। इस पर अनुमानित खर्च 600 करोड़ तक रहेगा। कमला पार्क से नई वीआईपी 6 लेन बनेगी। यह सीधी दिशा में रहेगी जबकि अभी वीआईपी रोड घुमावदार है। इसके लिए तालाब में 200 से 350 मीटर दूरी पर पिलर बनेगी। यह करीब 8 किलोमीटर रहेगा। यह 1200 करोड़ से बनेगा। वीआईपी रोड अभी जहां खत्म होती है वहां लालघाटी चौराहे से एलीवेटेड वीआईपी लेन एयरपोर्ट तक जाएगी। यह कमला पार्क से शुरू होने वाली नई 6 लेन में से ही 2 लेन से कनेक्टेड होगी। कमला पार्क से लालघाटी तक वीआईपी रोड के विस्तार का प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी से अब मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) के पास चला गया है। करीब 6 महीने पहले विजन-2031 के तहत पीडब्ल्यूडी अफसरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 किमी लंबी वीआईपी रोड को सिक्स लेन करने के प्रोजेक्ट पर सहमति दी थी। बाद में पर्यावरणविदों द्वारा हरियाली और तालाब को लेकर चिंता व्यक्त करने पर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा।

उज्जैन में बनेगा यूनिटी मॉल

एक जिला एक उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए केंद्र सरकार ने देश के हर राज्य में एक यूनिटी मॉल खोलने का निर्णय लिया है। इस बार के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया था। इन यूनिटी मॉल में अन्य राज्यों के उत्पाद की बिक्री भी की जा सकेगी। एक जिला एक उत्पाद योजना से राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों, बुनकरों को लाभ मिल रहा है और उन्हें राष्ट्रीय मंच पर अनेक अवसर मिल रहे हैं। मप्र में यह यूनिटी मॉल महाकाल की नगरी उज्जैन में खुलेगा।

यूनिटी मॉल खोलने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि इनमें छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों, बुनकरों आदि को अपने उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री करने का मौका मिलेगा। इससे न केवल स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे एक जिला एक उत्पाद योजना को भी बूस्ट मिलेगा। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि हर राज्य में यूनिटी मॉल खुलना है। राज्य सरकार ने मप्र का यूनिटी मॉल उज्जैन में खोलने का निर्णय लिया है।

अभी देश में गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकमात्र यूनिटी मॉल बना हुआ है। यहां भारत के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प का एक शोरूम है। यह मॉल 35 हजार वर्ग फीट में फैला है और दो मंजिला है। इसमें 20 एम्पोरियम हैं। देश का दूसरा यूनिटी मॉल उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बनने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए का फंड देने का संकेत दिया है। राज्य सरकार इसके लिए प्रारंभिक तैयारी में जुट गई है। दरअसल, गत दिनों उज्जैन जिला मुख्यालय पर हुई नगरीय आवास एवं विकास की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसका संकेत दे दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार उज्जैन में यूनिटी मॉल खोलने के लिए तैयार हो गई है। महाकाल मंदिर आने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या के कारण यह रुझान बन गया है। जिला प्रशासन इसके लिए उपयुक्त जमीन सरकार को बताएगा, ताकि मॉल का प्रस्ताव तैयार हो सके। इसके लिए 40 से 60 हजार वर्गफीट या इससे अधिक जमीन की जरूरत लग सकती है।

उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) की शिप्रा विहार योजना में 60 हजार वर्गफीट तक के कमर्शियल प्लॉट्स उपलब्ध भी हैं। यूडीए इस जगह को डेवलप भी कर रहा है। इस कारण यूनिटी मॉल स्थापित करने में दिक्कतें भी नहीं आएंगी। गत दिनों सिंहस्थ मेला कार्यालय में नगरीय आवास एवं विकास विभाग के आयुक्त ने समीक्षा बैठक ली थी। इसी दौरान अधिकारियों ने इस मुद्दे पर भी चर्चा की। वर्तमान में गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास दो मंजिला यूनिटी मॉल है, जो 35 हजार वर्गफीट जमीन पर बना है।

जानकारी के अनुसार उज्जैन में यूनिटी मॉल खोलने की बड़ी वजह यह है कि महाकाल लोक देश-विदेश के दर्शनार्थियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थल माना जाने वाला मंगलनाथ मंदिर, जहां हर मंगलवार को देशभर के श्रद्धालु आते हैं। हर बारह साल में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला शिप्रा तट पर लगता है। इस कारण विकास और अर्थव्यवस्था मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं। ग्रहों के अध्ययन के लिए जीवाजी वेधशाला और डोंगला वेधशाला के साथ कालिदास अकादमी जहां अखिल भारतीय कालिदास समारोह होता है। कालभैरव मंदिर जहां, प्रतिमा को मदिरा का भोग लगाया जाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जब यूनिट मॉल की घोषणा की, तब उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि ये मॉल ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट, जीआई टैग व हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बनाए जा रहे हैं। यानी इन मॉल से स्थानीय स्तर के ऐसे उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जो खास होने के बाद भी कुछ इलाकों तक सीमित रह गए हैं। वित्त विभाग कोशिश कर रहा है कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में जितनी भी स्कीम अनाउंस की है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जा सके। मत्स्य संपदा योजना में केंद्र ने 6 हजार करोड़ रखे हैं। चूंकि मप्र में किसी भी राज्य से ज्यादा वॉटर बाडी है, इसलिए इस बार इसका बजट भी 160 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। इकोलॉजिकल फर्टीलाइजर (गोबरधन) में केंद्र ने 10 हजार करोड़ रखे हैं, मप्र अपने बजट में इसकी योजना लॉन्च करने वाला है। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह सारी तैयारी 2026 तक मप्र की इकोनॉमी को 550 अरब डॉलर तक पहुंचाने की है। इसी कड़ी में मप्र का बजट का साइज 2023-24 में 3.20 लाख करोड़ से अधिक होने वाला है।

● **डॉ. जयसिंह सेंधव**

क्या है एक जिला एक उत्पाद योजना

एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। यह योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों के हर जिले के एक प्रोडक्ट को राष्ट्रीय पहचान देना है और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को सूक्ष्म, लघु, और मध्यम श्रेणी में रखा गया है। सरकार द्वारा इन उद्योगों को पैसा दिया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना का सबसे ज्यादा फायदा छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों, बुनकरों को हो रहा है। जिले के मुख्य उत्पाद की ब्रांडिंग में सरकार सहायता देती है। इससे उनको बड़ा एक्सपोजर मिलेगा और बिक्री में बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं इस योजना से राज्यों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई पहचान मिलेगी। मॉल में देशभर के अलग-अलग राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के साथ छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड व साउथ के राज्यों के सिग्नेचर उत्पाद रखे जाएंगे, जो उसकी ब्रांडिंग होगी। इस मॉल का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। बजट में इसके लिए बड़ी राशि का प्रावधान होने वाला है। इसके साथ ही भारत में प्राकृतिक गैस की अग्रणी कंपनी गेल इंडिया का एक प्लांट भी मप्र में खुलने वाला है। हालांकि यह ग्रीन हाइड्रोजन के तहत बनेगा। बता दें कि एक फरवरी को पेश हुए बजट में केंद्र सरकार ने देश के हर राज्य में यूनिटी मॉल खोलने की घोषणा की थी। इस बार राज्य का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर होगा। मत्स्य का बजट 160 करोड़ से ज्यादा होगा, गोबरधन की योजना भी होगी।

मप्र में विधानसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सप्ताह में करीब 5 दिन सभाएं कर रहे हैं। हर सभा में नई-नई घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। ये चुनावी घोषणाएं कब पूरी होंगी यह तो भगवान ही जाने। लेकिन दोनों पार्टियों की यही कोशिश है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए अधिक से अधिक घोषणाएं की जाएं, जिसका लाभ चुनाव में मिल सके।

घोषणाओं का मायाजाल

इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है। इसी कड़ी में सरकार प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को कई सौगातें देने जा रही है। यानी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देने, प्रोबेशन पीरियड की सौगात, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने, वाहन भत्ता बढ़ाने के साथ ही पदोन्नति का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार चुनावी साल में कर्मचारियों को खुश करके बड़ा वोट बैंक साधना चाहती है।

दरअसल, भाजपा सरकार 2018 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए सभी वर्गों को खुश करने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों का रूझान कांग्रेस की तरफ हो गया था। इसको देखते हुए भाजपा ने इस बार कर्मचारियों को पूरी तरह खुश करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले माह संवाद करेंगे। इसके लिए सभी संगठनों से दो-दो प्रतिनिधियों के नाम मांगे जा चुके हैं। वहीं, कर्मचारी आयोग ने कुछ संवर्गों की वेतन विसंगति को दूर करने संबंधी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी है। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन हो चुका है तो पेंशन नियम में संशोधन का प्रारूप तैयार है, जिसे मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद लागू कर दिया जाएगा।

चुनावी साल में सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को जो सबसे बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है, वह है पदोन्नति। बता दें कि प्रदेश में 7 साल से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। लाखों कर्मचारी अब तक बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राज्य कर्मचारियों के अधिकारी-कर्मचारी की नाराजगी दूर करने के लिए दूसरे विकल्प को तलाशा जा रहा है। ऐसे में वरिष्ठ पद का प्रभार देकर अधिकारी-कर्मचारियों की नाराजगी को दूर किया जा सकता है। इससे पहले पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों को वरिष्ठ पद का प्रभार सौंपा गया था। स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी प्रभार दिया जा रहा है। हालांकि अधिकारी-कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें प्रमोशन दिया जाए और वह उच्च प्रभार से संतुष्ट नहीं है। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दे सकती है। इसके लिए उच्च स्तर पर विचार शुरू कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई से सितंबर तक के बीच अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। दरअसल साल के अंत में मप्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य सरकार अधिकारी-कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर सकती है। उच्च स्तर पर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार बीच का रास्ता निकालकर अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति दे सकती है। जुलाई से सितंबर महीने में पदोन्नति देने की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है लेकिन पदोन्नति उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि न्यायालय द्वारा जो निर्णय रहेगा, अधिकारी-कर्मचारियों को स्वीकार करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले 7 साल से प्रदेश में 70 हजार कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। जिनमें से 39000 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें रिटायरमेंट से पहले

हर आवासहीन को पक्का मकान देगी सरकार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति आवासहीन न रहे। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्माण कराए जा रहे हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लाख 11 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराए। वहीं इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वाधिक राशि जारी की है। कुल 495 नगरीय निकायों में 5 हजार 490 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। आगामी 7 माह के अंदर निर्माण कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय ने हितग्राहियों को किश्त की एक मुश्त राशि भी जारी की है। दरअसल, चुनावी साल में सरकार का फोकस गरीबों के लिए आवास योजना पर है। नगरीय प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यह पहली और दूसरी किस्त को लेकर कुल 46 करोड़ 54 लाख रुपए राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के लिए कुल 98 निकायों को 8 करोड़ 74 लाख और 494 निकायों में 37 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि दी गई है।

प्रमोशन मिलना था। हालांकि उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं दिया गया। हर साल 5000 से अधिक कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और प्रमोशन ना मिलने से कर्मचारियों में विरोध देखा जा रहा है। मामले में मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी और मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमपी दिवेदी का कहना है कि पदोन्नति कर्मचारियों का अधिकार है। उन्हें मिलना चाहिए। वरिष्ठ प्रभार मिलने से अधिकारी-कर्मचारियों को पैसा तो मिलेगा लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों द्वारा आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। ज्ञात हो कि 2016 को जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा मप्र लोकसेवा पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद इस मामले में सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी। हालांकि अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

मप्र की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का फोकस प्रदेश के कर्मचारियों पर है। कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश के करीब 10 लाख कर्मचारियों को अपने पाले में लाया जाए। इसके लिए कांग्रेस आंदोलनरत कर्मचारी संगठनों के साथ खड़ी नजर आ रही है। वहीं इनके लिए वचन पत्र भी तैयार कर रही है। वचन पत्र में कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के वादे किए जा रहे हैं।

दरअसल, कमलनाथ मप्र के कर्मचारियों को साधने में जुटे हैं। इसके लिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े आयोजन करने की तैयारी में है, जबकि कमलनाथ ने विधानसभा कर्मचारियों के मुद्दों को कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके लिए वचन पत्र समिति के अध्यक्ष के साथ कर्मचारी संगठनों की एक बड़ी बैठक भी होगी, जिसमें कर्मचारी अपने सभी मुद्दों को रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को वचन पत्र में शामिल करवाया जा सके। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने वचन पत्र में कर्मचारियों के मुद्दों को शामिल किया था। जबकि खुद कमलनाथ ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें की थी, जिसका फायदा चुनाव के नतीजों में भी

दिखा था। ऐसे में कांग्रेस 2023 में भी उसी रणनीति पर चलने की तैयारी में हैं।

कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनते ही सभी वर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों की तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं से परामर्श कर नया पदोन्नति नियम बनाया जाएगा। इसमें ऐसे प्रविधान रखे जाएंगे, जो सभी वर्गों को मान्य हों। कर्मचारी आयोग को नया स्वरूप दिया जाएगा और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही होगी। इसे वचन पत्र में शामिल किया जाएगा।

बता दें कि प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निरस्त किए जाने के बाद से पदोन्नतियां बंद हैं। हजारों अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नत हुए बिना ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसको लेकर कर्मचारी समय-समय पर नाराजगी भी जता चुके हैं। इसे देखते हुए शिवराज सरकार ने नए पदोन्नति नियम बनाने के लिए गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में समिति भी गठित की है। इसने सभी कर्मचारी संगठनों से चर्चा करने के बाद नए नियमों का प्रारूप भी तैयार कर लिया है, पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि, विकल्प के तौर पर उच्च पदों का प्रभार देने की व्यवस्था लागू की गई है। गृह और जेल विभाग में पदोन्नति के लिए पात्र हो चुके अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार दिया गया है। सहकारिता विभाग ने भी सेवा भर्ती नियमों में संशोधन करके इसे लागू करने की तैयारी कर ली है। राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार, तहसीलदार को भी उच्च पद का प्रभार देने के लिए वरिष्ठता सूची तैयार करवा ली है लेकिन कर्मचारी स्थायी समाधान चाहते हैं। कांग्रेस कर्मचारियों से जुड़े सभी मुद्दों को भुनाना चाहती है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा सभी वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति भी तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं से नए पदोन्नति नियम तैयार कराए जाएंगे।

वचन पत्र समिति के सदस्य और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत का कहना है कि कर्मचारियों का हित शुरुआत से हमारी प्राथमिकता में रहा है। कर्मचारी आयोग का गठन कमलनाथ सरकार ने ही किया था। इसे नया स्वरूप दिया जाएगा। पुरानी पेंशन की बहाली के साथ 7 वर्ष से बंद कर्मचारियों की पदोन्नति फिर प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए सरकार बनते ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं से नए नियम बनाकर लागू किए जाएंगे।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

प्रोबेशन पीरियड की मिलेगी सौगात

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड चार से घटाकर दो साल किया जाएगा। सरकार अब यह प्रावधान करने जा रही है कि सरकारी भर्ती में ज्वाइनिंग के समय से ही कर्मचारी को 100 फीसदी वेतन मिलेगा। सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ा सकती है। प्रदेश में 2018 के पहले तक कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती होने पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को ज्वाइनिंग की तारीख से दो साल का प्रोबेशन पीरियड मिलता था। लेकिन 2019 में कांग्रेस सरकार ने प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाकर चार साल कर दिया था। इस अवधि को सीनियोरिटी में नहीं जोड़ने का भी आदेश दिया गया था। इसके तहत कर्मचारियों को पहले साल में 70 फीसदी, दूसरे में 80 फीसदी, तीसरे में 90 फीसदी और चौथे साल में 100 फीसदी वेतन दिया जाने लगा। इस नियम से अब तक 60 हजार लोग भर्ती हो चुके हैं। प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब इस नियम को बदलने जा रही है। सरकार प्रोबेशन पीरियड को चार से घटाकर दो साल करने जा रही है। सरकार प्रदेश की 1.90 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी राहत देने की तैयारी में है।

गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना मप्र में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। शासन और प्रशासन की सख्ती के बावजूद अस्पताल संचालकों ने इस योजना का जमकर दोहन किया है।

आयुष्मान में 500 करोड़ का घोटाला!

गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली आयुष्मान भारत योजना को लेकर मप्र में जमकर राजनीति हो रही है। इस योजना में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रहीं हैं। कांग्रेस ने इस योजना में करीब 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा, कांग्रेस आरटीआई विभाग के प्रभारी अमिताभ वाजपेई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि विधानसभा में भी स्वास्थ्य विभाग ने गलत जानकारी दी है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आयुष्मान पोर्टल के अनुसार प्रदेश में 627 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना में संबद्ध हैं। इनमें से अनियमितता के कारण 422 आयुष्मान अस्पतालों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि मप्र शासन ने विधानसभा में अनियमितता करने वाले मात्र 154 अस्पतालों की सूची दी है। इस योजना में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों एवं अनियमितता को संरक्षण देने वाले अधिकारियों, नेताओं पर मप्र शासन ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई ?

सरकार ने विधानसभा में दिनांक 20.12.2022 को अतारांकित प्रश्न 983 में स्वीकार किया (जिसमें डेटा स्त्रोत, इनसाईट पोर्टल, एचईएम दिनांक 06.12.2022) की स्थिति में स्वीकार किया कि आयुष्मान योजना में 506 निजी अस्पताल शामिल हैं। मप्र शासन ने इसी प्रश्न में स्वीकार किया कि आयुष्मान भारत योजना में 20 मार्च, 2020 से दिसंबर 2022 तक 51 जिलों में 5,16,589 मरीजों को इलाज में 16,10,32,40,343 रुपए (सौलह अरब दस करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार तीन सौ तिरतालीस रुपए मात्र) खर्च किए गए। इसी प्रश्न में शासन ने स्वीकार किया कि 154 आयुष्मान चिकित्सालयों में अनियमितता मिली थी जिस पर कार्यवाही की। विधानसभा में सदन में दिए गए उत्तर से सवाल यह उठता है कि मात्र 1 अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की गई है, बाकी 153 अस्पतालों पर एफआईआर क्यों नहीं की गई ?

विधायक जयवर्धन सिंह ने 22.12.2022 को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि विधानसभा में शासन ने जो जानकारी पेश की है, उसमें भोपाल जिले में पब्लिक चिकित्सालय 2, प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट 3, प्राइवेट फॉर प्रॉफिट 109, कुल 114 अस्पताल बताए हैं। जबकि आयुष्मान पोर्टल पर भोपाल जिले में पब्लिक चिकित्सालय 14, प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल 22 और प्राइवेट फॉर प्रॉफिट 177, कुल 213 अस्पताल बताए गए हैं। विधानसभा में दी गई जानकारी एवं आयुष्मान पोर्टल की जानकारी में अंतर क्यों है? विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर 22.12.2022 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि विधानसभा प्रश्न क्रमांक-983 में दी गई जानकारी अधूरी है, क्योंकि चाही गई जानकारी में चिकित्सालयों के नाम, कब और क्या कार्यवाही की, अलग-अलग मांगी गई थी। जबकि उत्तर में अस्पताल का नाम और एक लाईन में कार्यवाही लिखी है, जो अधूरी है। विधायक जयवर्धन सिंह ने लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में दिए गए उत्तर में शासन द्वारा प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट की जानकारी निरंक दी है, जबकि शासन द्वारा प्राइवेट चिकित्सालयों की जानकारी दी है, उनमें 3 चिकित्सालय ऐसे हैं, जो प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट में आयुष्मान के पोर्टल पर दिखाए गए हैं- (1) राजदीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग (2) यूनिक हॉस्पिटल (3) आयुष्मान हाईटेक चिकित्सालय। एक ही चिकित्सालय 2 कैटेगिरी में कैसे हो सकता है।

कांग्रेस ने आयुष्मान की वेबसाइट से जो जानकारी निकाली, उसमें निलंबित अस्पतालों की सूची 422 बताई गई है, जिसमें 84 अस्पताल भोपाल के, प्रॉफिट के आयुष्मान अस्पताल 545 एवं नॉन प्रॉफिट के आयुष्मान अस्पताल 82 बताए गए हैं। अर्थात् मप्र में निजी आयुष्मान अस्पताल 545 मिलाकर कुल 627 को कार्यरत बताया जा रहा है। इस मान से प्रदेश में कुल 205 आयुष्मान चिकित्सालय सक्रिय हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

आईएएस अफसरों पर हो एफआईआर

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 422 अस्पतालों में यह गड़बड़ी अनुमानित कम से कम 500 करोड़ की हो सकती है। समाचारों में छपा था कि कई आईएएस अधिकारियों के कार्यकाल में आयुष्मान अस्पतालों को करोड़ों रुपयों का भुगतान हुआ। जिन अधिकारियों के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं- पल्लवी जैन गोविल-प्रमुख सचिव, मोहम्मद सुलेमान-अपर मुख्य सचिव, प्रतीक हजेला-आयुक्त, संजय गोयल-प्रमुख सचिव, आकाश त्रिपाठी-आयुक्त, सुदाम खेड़े-आयुक्त, जे. विजय कुमार-सीईओ, अनुराग चौधरी-सीईओ, सपना लोवंशी-कार्यकारी अधिकारी। कैलाश मकवाना लोकायुक्त डीजी रहते सपना लोवंशी के खिलाफ जांच की अनुमति मांग चुके थे। आयुष्मान योजना में 9 लाख के लेन-देन की वीडियो वायरल होने पर जांच करानी पड़ी। राज्य शासन ने आयुष्मान योजना के सीईओ अनुराग चौधरी को हटाया। इसकी वजह भी 9 लाख के लेन-देन से जुड़ा वीडियो बताया जाता है।

आखिर कब रुकेंगी सड़क दुर्घटनाएं?

मप्र में दिन पर दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। सड़क हादसे रोकने के लिए शासन, प्रशासन के अलावा परिवहन और पुलिस विभाग भी लगातार कवायद कर रहा है, उसके बाद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस हादसों के पीछे शराब को सबसे बड़ा दोषी मान रही है। पुलिस मुख्यालय की 2022 की एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के अनुसार शराब पीकर और मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाने से प्रदेश में बीते वर्ष 680 लोगों की जान चली गई। इसमें दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक और सवार दोनों शामिल हैं। इसके अनुसार मोबाइल का उपयोग करने की वजह से प्रदेशभर में एक हजार 115 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 338 लोगों की जान चली गई, जबकि 1264 लोग घायल हुए। इसी तरह से शराब के नशे के कारण 1472 घटनाएं हुईं, जिनमें 342 की मौत हुई और 1788 लोग घायल हुए।

प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 1 अप्रैल से अहाते बंद कर दिए हैं। इस निर्णय की एक वजह शराब के नशे में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं, छेड़खानी और विवाद की घटनाएं भी हैं। अहाते बंद होने से हादसों में कमी आने की उम्मीद है। बीते वर्ष सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं और मौत तेज गति से वाहन चलाने की वजह से हुई हैं। इसके चलते 41 हजार 68 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 10 हजार 356 लोगों की जान चली गई, जबकि 41 हजार 574 लोग घायल हुए। यानी हादसों के शिकार हुए लोगों में 20 प्रतिशत की जान चली गई। 2021 में तेज गति से वाहन चलाने के कारण 36 हजार 895 दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 9 हजार 541 लोगों की मौत हो गई थी। 12 हजार 771 दुर्घटनाओं में वाहन चालकों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इनमें 8 हजार 66 लोग घायल हुए, जबकि 1 हजार 809 की जान चली गई। पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने वालों पर नियंत्रण के लिए इंटरसेप्टर व्हीकल सभी जिलों को दिए गए हैं। इनके माध्यम से तय सीमा से तेज वाहन चलाने वालों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं बांधने वालों पर भी अर्थदंड लगाया जा रहा है। मप्र की सड़कों की स्थिति लगातार सुधर रही है, लेकिन हादसे कम नहीं हो रहे हैं। पिछले वर्ष 2022 में प्रदेश में 54 हजार 432 सड़क दुर्घटनाओं में 13 हजार 417 लोगों की जान चली गई, जबकि 55 हजार 168 लोग घायल हुए। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक दुर्घटनाएं जबलपुर में हो रही हैं, वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी सूची में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में जबलपुर को देश मे तीसरा स्थान मिला है।

पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में प्रदेश में सबसे ज्यादा 4046 दुर्घटनाएं जबलपुर में हुई हैं। इनमें 4 हजार 181 लोग घायल हुए। 481 की जान चली गई। इंदौर में 3 हजार 317 और भोपाल में 2 हजार 788 दुर्घटनाएं हुईं। धार में 2 हजार 59 दुर्घटनाओं में 637 लोगों की मौत हो गई जो पिछले वर्ष प्रदेश में सर्वाधिक है। ऐसे ही सागर में 524 लोगों को सड़क दुर्घटना के चलते जान गंवानी पड़ी। ब्लैक स्पाट की बात करें तो सागर में सर्वाधिक 26 और खरगोन में यह 24 हैं। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में दुर्घटनाओं और मृतकों की संख्या 11 प्रतिशत अधिक रही। प्रदेश के 21 जिलों में बीते साल सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा 1 हजार से ऊपर है। चिंता की बात यह है कि दुर्घटना, घायल और मृतकों की संख्या पिछले 5 वर्ष से लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार विभागों में बैठे अधिकारियों को कोई फिक्र नहीं है। प्रदेश में 395 ब्लैक स्पाट हैं, जहां सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं। इसकी वजह सड़क की इंजीनियरिंग में खामियां भी हैं, पर इन्हें भी दूर नहीं किया जा रहा है। बता दें कि जबलपुर में 2021 में भी सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में यह देश का तीसरा महानगर है। सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं के मामले में 2021 में मप्र देश में दूसरे स्थान पर था।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के दौरान सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले महानगरों की सूची में मप्र के तीन शहर टॉप 10 में हैं। चेन्नई 5034 दुर्घटनाओं के साथ पहले व दिल्ली 4720 दुर्घटनाओं के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जबकि मप्र के जबलपुर का तीसरा स्थान था। इंदौर में 2021 में 3676 दुर्घटनाएं हुईं और सूची में चौथा स्थान रहा। भोपाल में इसी दौरान 2626 दुर्घटनाएं हुईं और इस लिस्ट में छठवें नंबर पर रहा। मृतकों की संख्या के मामले में भी प्रदेश के दो महानगर इंदौर व जबलपुर टॉप टेन में हैं। इन दुर्घटनाओं में जबलपुर में 2021 में कुल 467 लोग काल कवलित हुए। यह संख्या महानगरों में 10वें क्रम पर है। जबकि इंदौर में 484 मौतें हुईं। इंदौर का दुर्घटना में मृतकों की संख्या के मामले में देश में 8वां स्थान है। देश में हर साल होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में जबलपुर की हिस्सेदारी बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में देश की कुल सड़क दुर्घटनाओं में जबलपुर की हिस्सेदारी 3.98 प्रतिशत थी। 2020 में यह बढ़कर 5.37 और फिर 2021 में 5.73 फीसदी हो गई।

● **प्रवीण सक्सेना**

हादसों की वजह

ट्रैफिक इंजीनियरिंग व यातायात संचालन, नियंत्रण से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि जबलपुर में सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह यहां की पुरानी डिजाइन से बनी सड़कें हैं। जगह-जगह चौराहे बना दिए गए हैं। जहां यातायात का दबाव बहुत है, वहां एक साथ वाहनों के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी गई है। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता की कमी है। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस बल का अभाव है। इसके साथ ही निर्माणाधीन विकास कार्यों की वजह से जगह-जगह सड़क पर डायवर्जन और गड्ढे भी दुर्घटनाओं के बड़े कारण हैं। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडीजी जी जनार्दन का कहना है कि संबंधित विभागों से समन्वय कर ब्लैक स्पाट खत्म किए जा रहे हैं। ज्यादातर हादसे तेज गति से वाहन चलाने के कारण होते हैं, इन्हें रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जबलपुर का सड़क दुर्घटनाओं के मामले में महानगरों में तीसरा स्थान है। 2021 में यहां 3855 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। जबकि मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं में जबलपुर चौथे नंबर का महानगर था। 2020 में यहां 3226 सड़क दुर्घटनाएं हुईं थीं। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों की संख्या के मामले में 2021 में जबलपुर तीसरे नंबर पर बरकरार रहा। 2021 में यह संख्या 3756 थी। जबकि 2020 में जबलपुर में सड़क दुर्घटनाओं में 3257 लोग घायल हुए थे और इस मामले में महानगरों में जबलपुर का नंबर तीसरा ही था।

आईएएस-आईपीएस अहंकार से दूर रहें

सिविल सेवा दिवस पर प्रशासन अकादमी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सबने मिलकर प्रदेश को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि मैं आईएएस-आईपीएस हूं, 2 मिनट में सही कर दूंगा, इस अहंकार से दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि घमंडी का सिर नीचे होता है। यह आज भी 10 प्रतिशत सही है। सर्विस का घमंड आ गया कि हम आईएएस या आईपीएस हैं, तो ये आदमी को चढ़ाने वाला मामला है। हम जनता के सेवक हैं। मुख्यमंत्री हैं तो जनता की सेवा के लिए हैं। हम सबको अहंकार शून्य होना चाहिए। धूल चढ़े और पसीने की बदबू वाले आदमी को गले लगाने में मुझे आनंद आता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन में अब सुधार की जरूरत है। कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कई बार लोग परेशान करने के लिए जनप्रतिनिधियों और सरपंच की शिकायत करवा देते हैं कि जांच हो जाए। फंसेगा तो फिर उसे ब्लैकमेल करो। शिकायत बंद कराने के लिए ब्लैकमेल करने के लफड़े शुरू हो गए। हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते, लेकिन विश्लेषण कर लेना चाहिए। कलेक्टर साहब तो लाटसाब हैं, कैसे मिलें। ये हमने मप्र में खत्म कर दिया। हमारे यहां लोग बेहिचक कलेक्टर-एसपी से मिलते हैं। मप्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने जनता और प्रशासन के बीच की दूरी खत्म कर दी। कई राज्यों में तो कलेक्टर से मिलना बड़ी बात होती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- मैं टीम को बधाई देना चाहता हूं। हमने मप्र को विकसित और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई बार सोचता हूं तो यहां केवल 71 हजार किमी टूटी सड़कें हुआ करती थीं। आज मप्र का बजट 3 लाख 14 हजार करोड़ पहुंच गया है। हमारे पास संसाधन और रिसोर्स हैं। मप्र कभी बीमारू राज्य कहलाता था। पिछले दिनों बुरहानपुर में परिस्थिति बनी थी, वहां के प्रशासन ने बड़ी समस्या को ढंग से निपटा दिया। कई बार हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक नजर, मीडिया की दृष्टि अलग होती है। नए अफसर शुरुआत में बहुत उत्साह से काम करते हैं, बाद में ढीले पड़ जाते हैं। उत्साह की आग जलती रहना चाहिए। मैं 64 साल का हो गया हूं और कितना जीऊंगा 10, 12, 15 साल। दौलत कभी सुख नहीं देती। हमारे आदिवासी भाइयों को कल की चिंता नहीं रहती। वे हर दिन त्यौहार मनाते हैं। वहीं, बड़े उद्योगपति मेरे पास आते हैं। कहते हैं- सर ये छूट दे दीजिए। पहले मुझसे मिलेंगे, फिर अफसर से जाकर मिलते हैं। सबसे ज्यादा दीन-हीन यही लगते हैं।

उन्होंने कहा- मैं 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं था। झोला लेकर निकल गया। आंदोलन किए। दोबारा जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बना तो भगवान से प्रार्थना करता था। भगवान से कहता था मदद करो कोरोना कंट्रोल हो जाए। अफसरों-विधायकों के फोन आते थे- सर, ऑक्सीजन 15 मिनट की बची है। 10-12 दिन ऐसे थे, जब मैं भी विचलित हो गया था।

अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने नसीहत दी है कि सर्विस का घमंड कभी नहीं आना चाहिए। नए अधिकारी शुरुआत में अच्छा काम करते है, कुछ सालों के बाद फिर वो तेजी नहीं देखने को मिलती है। कुछ अधिकारी उत्साह की जगह निराशा भर देते हैं। उत्साह रहेगा तो बड़ा से बड़ा काम हो जाएगा। सीएम हेल्पलाइन में सुधार की जरूरत है। सीएम हेल्पलाइन का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, अधिकारी कमर्चारी को ब्लैकमेल करते है। विश्लेषण करते रहना चाहिए विसंगतियों को कैसे समाप्त कर सकें। 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहा तो मेरे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर जनता की लड़ाई लड़ी। ये लूपलाइन क्या होता मुझे समझ नहीं आता। कुछ अधिकारी कहते हैं मुझे लूपलाइन में डाल दिया, जहां काम करने का मौका मिले वहां काम करो।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि हमारे कई अधिकारी मित्र दिन-रात परिश्रम करते हैं मैं खुद साक्षी हूं। कई वर्षों से काम करते हुए देखा है। उन्हें देखकर गर्व होता है। अफसरों में अनेक ऐसे हैं जो दिन और रात जिद, जुनून और जज्बे के साथ काम करते हैं। अपने आपको पूरी तरह झोंक देते हैं। सरकार ने कोई रीति-नीति बनाई तो उसका स्वरूप निर्धारण करना और नीचे जमीन पर उतार देना। और एक है जो तत्काल परिणाम देने पर विश्वास करते हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

हमारा काम ही समाज की सेवा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सिविल सर्विस डे का अर्थ ही यह है कि हम लोग हैं जनता की सेवा के लिए। हम लोक सेवक हैं। हमारा मूल काम ही देश की सेवा और समाज की सेवा है। लोकतंत्र में हम सब जानते हैं कि जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। यानी जो कुछ है जनता के लिए ही है। हम समृद्धि की बात करें। विकास की बात करें। इंफ्रा की बात करें। सुरक्षा की बात करें। अंततः सब लोगों के लिए है, जनता के लिए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को सलाह दी कि अहंकार न करें कि हम तो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, हम जनता के सेवक हैं। हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए। यह दिमाग में रहना चाहिए कि हम जनता की बेहतरी के लिए हैं। हमें हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि हम लोगों के लिए हैं। कई चुनौतियां आती हैं। उन परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है। धैर्य नहीं खोना है। आप टीम के लीडर हैं। हमारा उत्साह अगर कम हुआ तो हम कहीं काम नहीं कर पाएंगे और नुकसान देश व प्रदेश का होगा। आज प्रदेश को अगर यहां लाकर खड़ा किया है तो हमने किया है।

बुरहानपुर पर मंडरा रहा नक्सलवाद का साया

मप्र में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के बाद अब महाराष्ट्र की सीमा से लगे बुरहानपुर पर नक्सलवाद का साया मंडराने लगा है। जिस तरह पिछले कुछ महीनों के अंदर यहां वन क्षेत्र में अतिक्रमण बढ़ा है और अतिक्रमणकारी आदिवासी आक्रामक और हिंसक हो रहे हैं उससे यह साफ लग रहा है कि इनके पीछे वामपंथी विचारधारा खड़ी है। बुरहानपुर के नेपानगर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इस क्षेत्र पर नक्सलवाद का साया मंडराने लगा है। इस बात का अंदाजा वन चौकी से बंदूकों की लूट और उसके बाद बंदूक लूटने वालों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमले से लगाया जा सकता है।

निमाड़ क्षेत्र में शामिल सभी जिले आदिवासी बहुल आबादी वाले हैं। आदिवासी भोले-भाले और शांतिप्रिय होते हैं, लेकिन अब इन आदिवासियों को नक्सलवाद की आग में झोंका जा रहा है। वर्तमान में बुरहानपुर पर नक्सलवाद का साया मंडरा रहा है।

जिस तरह नक्सली गुरिल्ला अंदाज से हमला करते हैं एक दम उसी अंदाज से बुरहानपुर में जनजाति समाज के लोगों ने पुलिस पर हमला किया है। इससे नेपानगर जन, जंगल, जमीन के लालच में नक्सलवाद की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थाने पर हमले की हुई दो घटनाएं संकेत दे रही हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब नेपानगर के नावरा क्षेत्र को लोग नक्सलवाद वाला क्षेत्र बोलेंगे। गौरतलब है कि 7-8 अप्रैल की दरमियानी रात बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाने पर 60 से अधिक अतिक्रमणकारी जनजाति समूह ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं हमलावर थाने में बंद बंदूक चोरी कर तीन आरोपियों को अपने साथ भगा ले गए। ये घटना बुरहानपुर जिले में पहली बार नहीं हुई इससे पहले भी मार्च के महीने में जंगल में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने वाले आरोपियों को रोकने गई वन विभाग की टीम पर जनजाति समूह ने तीर कमान से हमला कर दिया था। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। नवंबर महीने में ऐसे ही अतिक्रमणकारी वन चौकी पर हमला कर 17 बंदूकें और कारतूस लूट ले गए थे। इन घटनाओं से समझ आता है कि मालवा-निमाड़ के शांतिप्रिय जनजाति समाज के बीच कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो इन्हें नक्सलवाद की ओर धकेल रही है।

मप्र के आदिवासी काफी संवेदनशील होते हैं। ये जंगल के संरक्षक माने जाते हैं। लेकिन जन, जंगल, जमीन के लालच में इन्हें नक्सलवाद में ढकेला जा रहा है। प्रदेश के बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा सहित मालवा निमाड़ के जनजाति बाहुल्य जिलों में अचानक से जनजाति समूहों ने सरकारी दफ्तरों में घुसकर आंदोलन करने की परंपरा शुरू कर दी है। यही नहीं अब ऐसे आंदोलन धीरे-धीरे हिंसक भी होते जा रहे हैं, बुरहानपुर और नेपानगर की घटनाएं इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। इन सभी आंदोलनों में एक संगठन हमेशा धरना प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा जाता है। इस संगठन का नाम है जागृत आदिवासी दलित संगठन, जो कथित तौर पर इन क्षेत्रों में जनजाति हितों के किए काम करने की बात कहता है। जबकि इसकी आड़ में यह संगठन जनजातियों को बरगलाने और उन्हें हिंसक बनाने का काम कर रहा है।

नेपानगर थाने पर हमले की घटना से कुछ घंटे पहले तक इसी जागृत आदिवासी दलित संगठन की मुखिया माधुरी बेन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जनजाति समूह बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में जंगलों में चल रही अवैध कटाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिस पर बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार लोढा ने कई सवाल उठाए हैं। एसपी ने कहा- जो संगठन विरोध कर रहा है उसका नेतृत्व कर रहीं माधुरी बेन पर बड़वानी में 21 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक लोढा ने बताया कि जागृत आदिवासी दलित संगठन अवैध वन कटाई के लिए आंदोलन कर रहा है, लेकिन इसके कई सक्रिय कार्यकर्ता जंगल कटाई से लेकर लूट-डकैती, अवैध अतिक्रमण, शासकीय कार्य में बाधा, बलवा जैसी धाराओं में अपराधी हैं। संगठन खुद ऐसे कार्यकर्ताओं के बचाव में ज्ञापन दे चुका है। मप्र में इस संगठन को सक्रिय रूप में चलाने वाली इसकी मुखिया का पूरा नाम माधुरी बेन उर्फ माधुरी कृष्णास्वामी है। माधुरी कृष्णास्वामी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास की पढ़ाई करने के बाद 1993 में मप्र के खरगोन पहुंचीं, जहां रहकर वह प्रदेश के भोले-भाले जनजाति समाज के बीच वामपंथी एजेंडे को षड्यंत्र पूर्वक चलाने लगीं।

● लोकेंद्र शर्मा

किसान आंदोलन के पीछे भी यही संगठन

मालवा-निमाड़ क्षेत्र में सक्रिय इस संगठन के सोशल मीडिया अकाउंट की स्कैनिंग से पता चलता है कि इन अकाउंट्स से पूर्व में सिंधु बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन का इस संगठन के द्वारा खुलकर समर्थन किया जा रहा था। यही नहीं मप्र में किसान आंदोलन को सक्रिय करने के प्रयास संबंधी पोस्टर भी इन अकाउंट पर मौजूद हैं। खंडवा और खरगोन जिले के अधिकांश आंदोलनों में सक्रिय रहने वाली जागृत आदिवासी दलित संगठन की मुखिया माधुरी बेन के लगातार गैरकानूनी और गैर संवैधानिक कारनामों में लिप्त रहने की वजह से वर्ष 2012 में उसे प्रशासन ने आदतन अपराधी और जिला बदर घोषित कर दिया था। जिसके बाद देशभर में वामपंथी संगठनों ने एकजुट होकर तत्कालीन मप्र सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी।

मेट्रो का ट्रायल रन सितंबर में

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र में चल रही रेल परियोजनाओं के बारे में उनसे चर्चा की, साथ ही भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञों की तैनाती का आग्रह भी किया। इधर, मप्र में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन सितंबर 2023 से पहले पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री से इंदौर-मनमाड़ और इंदौर दाहोद रेल लिंक को भी शीघ्र पूरा करवाने का अनुरोध किया। साथ ही इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकार की ओर से समुचित कार्यवाही का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इन दोनों लिंक परियोजनाओं के पूरा होने से इंदौर, पीथमपुर, धार और उससे लगे औद्योगिक क्षेत्र को काफी मदद मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी से इंदौर के बीच रेल परियोजना को भी जल्द पूरा करवाने का आग्रह रेलमंत्री से किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि राज्य सरकार इस साल सितंबर से पहले इंदौर और फिर भोपाल में मेट्रो चलाना चाहती है। इसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत है। इसके लिए रेल मंत्री से विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

मप्र में इंदौर और भोपाल में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सितंबर में मेट्रो का ट्रायल रन पूरा हो जाएगा। मेट्रो रेल प्रबंधन के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने यह निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए हैं। मनीष सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि भोपाल में मेट्रो का ट्रायल रन सितंबर 2023 से शुरू कर दिया जाएगा। इस डेडलाइन में अब कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मेट्रो परियोजना के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर में सभी कार्य तेजी से चल रहे हैं। गत दिनों मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी मनीष सिंह प्रायोरिटी कॉरिडोर रूट पर पहुंचे। उन्होंने स्टेशन और रूट का काम देखा। उन्होंने कॉरिडोर में 8 स्टेशन के ओपन फाउंडेशन, पीयर, गर्डर कास्टिंग, पाइलिंग, बिजली सब स्टेशन और लोडिंग-अनलोडिंग-वे के सिविल वर्क के बारे में जानकारी ली। मेट्रो का पहला रूट एम्स से करोंद तक कुल 16.05 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 6.22 किमी एम्स से सुभाष नगर के बीच का काम प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूप में 2018 में शुरू हुआ था। इसका 85 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। सितंबर से पहले बाकी काम पूरा करने का टारगेट है। ताकि, सितंबर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन हो सके। पिलर खड़े होने और गर्डर लॉन्चिंग के बाद मेट्रो कॉर्पोरेशन का पूरा फोकस डिपो और स्टेशन बनाने में है। इनका काम भी तेजी से चल रहा है।

पटरी बिछाने का काम जल्द होगा शुरू

राजधानी भोपाल में मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर का 31 मार्च की स्थिति में शहर के 8 स्टेशनों का ओपन फाउंडेशन का काम 90 फीसदी पूरा कर लिया गया। पीयर का कार्य करीब 80 फीसदी और गर्डर कास्टिंग का कार्य करीब 50 फीसदी पूरा कर लिया गया है। मनीष सिंह ने सुभाष नगर के साथ बाकी मेट्रो स्टेशन के काम भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। साथ ही काम की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाने की बात भी कही। अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक कॉन्ट्रैक्टर एलएंडटी ने सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा पटरी की सप्लाई लगातार जारी है। अप्रैल माह में भोपाल में लगभग 900 मीट्रिक टन पटरी की डिलीवरी हो चुकी है। सिंह ने पटरी बिछाने और वेल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान निदेशक प्रोजेक्ट अजय शर्मा, निदेशक वित्त नीति कोठारी, अतिरिक्त निदेशक तकनीकी शोभित टंडन, महाप्रबंधक सिविल संजय सिंह, वाईसी शर्मा समेत कॉर्पोरेशन के अधिकारी और कॉन्ट्रेक्टर्स मौजूद थे। एमडी सिंह ने स्टेशन कॉन्ट्रेक्टर को निर्देश दिए कि अन्य स्टेशन के कार्य भी जल्द पूरे करें। ट्रैक कॉन्ट्रेक्टर ने जानकारी दी कि सर्वे का काम जारी है। इस पर एमडी ने निर्देश दिए कि रेल पटरी बिछाने और पटरी की वेल्डिंग का काम जल्द पूरा करें। ट्रैक के लिए जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड पटरी की सप्लाई कर रहा है। अप्रैल में अब तक 900 मीट्रिक टन पटरी डिलीवर हो चुकी है। एमडी ने निर्माण एजेंसी दिलीप बिल्डकॉन कॉन्ट्रेक्टर को निर्देश दिए कि डिपो एवं स्टेशन के बीच रैम्प के काम में स्पीड लाएं। इसके लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ा दें। नवंबर-22 से मार्च-23 तक स्टेशन और डिपो की डिलाइन-ड्राइंग को मंजूरी दी गई है।

अधिकारियों ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के तहत 31 मार्च तक डिपो और स्टेशन की प्रगति के बारे में जानकारी दी। सभी 8 स्टेशन के ओपन फाउंडेशन का कार्य 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। पीयर का 80 प्रतिशत, गर्डर कास्टिंग का काम 50 प्रतिशत, डिपो की प्रशासनिक बिल्डिंग का कार्य लगभग 60 प्रतिशत, पाइलिंग का कार्य लगभग 96 प्रतिशत, उप विद्युत सब स्टेशन-1 का कार्य लगभग 70 प्रतिशत और लोडिंग-अनलोडिंग-वे का सिविल का काम 50 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। भोपाल में 30.95 किमी को मेट्रो ट्रैक प्रस्तावित है। इसमें से साढ़े सात किलोमीटर का प्रायोरिटी ट्रैक बनाया जा रहा है। इसमें सुभाष नगर से एम्स तक 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें से सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस चौराहा, एमपी नगर जोन-2, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अल्कापुरी और एम्स में 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें से अगले माह तक सुभाष नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, एमपी नगर स्टेशन के सिविल कार्य पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। रेलवे स्टेशन को 6 डिब्बों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। हालांकि, शुरुआत में तीन-तीन डिब्बों के साथ ही मेट्रो दौड़ेगी।

● **राजेश बोरकर**

कांग्रेस कितनी कंट्रोल में?

16 नेताओं को सौंपी 52 जिलों की जिम्मेदारी

मप्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अलग-अलग नेताओं को तीन-तीन जिलों की जिम्मेदारी दी है। ये सभी नेता अपने क्षेत्र में अभी से चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस की इस लिस्ट में नेताओं को क्षेत्रवार और जातीय समीकरणों के आधार पर प्रभार दिया गया है। फूल सिंह बरैया को श्योपुर, मुरैना, भिंड की जिम्मेदारी दी गई है। अजय सिंह राहुल को ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण यादव को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर की जिम्मेदारी दी गई है। इस क्षेत्र में यादव वर्ग के वोटर्स निर्णायक हैं। जीतू पटवारी को सतना, पन्ना, दमोह, रायसेन की कमान दी गई है। सुरैश पचौरी को सिंगरौली, सीधी, रीवा, कटनी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी विंध्य में ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर का प्रभार दिया गया है। तरुण भनोट को डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। सज्जन सिंह वर्मा को छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम की कमान दी गई है। बाला बच्चन बुरहानपुर, खंडवा, धार की जिम्मेदारी संभालेंगे। आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को ट्राइबल बेल्ट बड़वानी, खरगौन की जिम्मेदारी दी गई है। मीनाक्षी नटराजन को अलीराजपुर, झाबुआ, आगर की जिम्मेदारी दी गई है। कमलेश्वर पटेल नीमच, मंदसौर, रतलाम की जिम्मेदारी संभालेंगे। जयवर्धन सिंह को इंदौर और उज्जैन की जिम्मेदारी दी गई है। रामनिवास रावत को राजगढ़ और शाजापुर की कमान सौंपी गई है। केपी सिंह को गुना, अशोकनगर, विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है। लाखन सिंह यादव को सीहोर और देवास की जिम्मेदारी दी गई है।

इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उन्हीं नेताओं को टिकट देगी जो कमलनाथ के द्वारा तय किए गए तमाम फॉर्मूले पर खरा उतरेंगे। कांग्रेस में इस बार भाई भतीजावाद और बड़े नेताओं के चेहते वाला फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। उधर कांग्रेस ने तय किया है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन्हें संगठन द्वारा न केवल कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उनके इलाकों में पार्टी द्वारा परिवर्तन संकल्प अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बीते रोज साफ कर दिया गया है कि चुनाव के लिए अब कांग्रेस में एक नेता के सुझाए नाम पर टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस टिकट वितरण का फॉर्मूला खुद ही सार्वजनिक किया है। उनका कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनने के लिए दावेदारों को कई पैमानों पर खरा उतरना होगा। उनका कहना है कि हर सीट पर प्रत्याशी तय करने के लिए संगठन के वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। इसकी वजह से इस बार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट वितरण का पुराना तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। कमलनाथ का कहना है कि टिकट वितरण को लेकर संगठन बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि सभी 230 सीटों पर दावेदारों को कई पैमानों पर खरा उतरना होगा। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ या कोई एक नेता क्षेत्र विशेष के टिकट को लेकर निर्णय कर ले। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंच सकें इसलिए उन्हें काफी पहले बता दिया जाएगा कि वे तैयारी शुरू कर दें। नाथ ने कहा कि कई दावेदार उन्हें बायोडाटा भेज रहे हैं। एक सीट पर तो 21 लोगों ने दावेदारी की है। दावेदार अपने बारे में जो जानकारियां भेज रहे हैं उनका आकंलन किया जा रहा है।

कांग्रेस ने भाजपा सरकार व उसके नेताओं द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को किए जा रहे प्रताड़ना के मामले में अब मोर्चा खोलने की रणनीति तैयार कर ली गई है। संगठन अब पूरी तरह से प्रताड़ित पार्टी कार्यकर्ताओं के बचाव में साथ खड़ी नजर आने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिन जिले या विधानसभा क्षेत्रों में अधिक प्रताड़ित करने की शिकायतें हैं, वहां पार्टी परिवर्तन संकल्प अभियान शुरू करेगी। इसमें गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का क्षेत्र दतिया, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का क्षेत्र खुरई और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का विधानसभा क्षेत्र बदनावर शामिल है। इन क्षेत्रों में न केवल कमलनाथ की सभाएं आयोजित की जाएंगी, बल्कि पीड़ित कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। बीते रोज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में हुई पार्टी की प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरणों में फंसाकर प्रताड़ित किए जाने के मामलों से निपटने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि दतिया, सागर के खुरई, सुरखी, रहली, धार के बदनावर क्षेत्र में प्रकरण अधिक सामने आए हैं। जिन पर कोई प्रकरण नहीं बन रहा है, उन्हें 151 धारा लगाकर सताया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी के स्तर पर जिन्हें छोड़ा जा सकता है, उन्हें भी जेल भेजा जा रहा है। खुरई में तो एक व्यक्ति ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 9 फर्जी प्रकरण लगा रखे हैं। जिसमें उसका नाम नहीं है, वहां वह गवाह बनकर खड़ा हो गया। इसी तरह से कार्यकर्ताओं को जिलाबदर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर गैरकानूनी तरीके से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने वाले अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ताओं की लड़ाई पार्टी लड़ेगी। परिवर्तन संकल्प अभियान के दौरान पार्टी ऐसे भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार करेगी, जिन पर प्रकरण होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। बैठक में कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाने की जिम्मेदारी पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर को दी गई। पार्टी का विधि प्रकोष्ठ सभी जिलों में अधिवक्ताओं की तैनाती करेगा, जो न्यायालय में कार्यकर्ताओं की पैरवी करेंगे। यह व्यवस्था पूरी तरह निशुल्क रहेगी। 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे, जिस पर सूचना मिलते ही संबंधित जिले के कार्यकर्ता को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक जिले में सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित की जा रही अवैध गतिविधियों को भी उजागर किया जाएगा।

नाथ ने कहा कि जिन आधारों पर टिकट वितरण किया जाएगा उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सर्वे में सुझाया गया नाम होना चाहिए। सुझाए गए नाम पर कांग्रेस संगठन, वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। नाथ ने बताया कि स्थानीय उम्मीदवार होने के साथ ही जीतने की योग्यता को भी परखा जाएगा। इसके साथ ही एआईसीसी के सचिव स्थानीय नेताओं से बात कर रहे हैं। स्थानीय संगठन जिस व्यक्ति के साथ होगा पार्टी में उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

● **अरविंद नारद**

ग्लोबल वार्मिंग खतरे में पृथ्वी

जलवायु परिवर्तन के चलते इतिहास में सबसे गर्म रहे पिछले 9 साल

मौसम चक्र बिगड़ा... सूखा, बाढ़ और महामारी का खतरा बढ़ा

जलवायु परिवर्तन की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कहीं सूखा और कहीं बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर यह हो रहा है कि मौसम चक्र ही बिगड़ गया है। सूखा, बाढ़ और महामारी का खतरा बढ़ गया है। वहीं जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे पृथ्वी का भविष्य ही खतरे में दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।

● राजेंद्र आगाल

पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए पृथ्वी के औसत तापमान में बदलाव भी जिम्मेदार होता है, लेकिन इस बार जिस तरह अप्रैल महीने में सावन-भादौ की तरह बारिश हुई है, उससे यह साफ हो गया है कि मौसम चक्र पूरी तरह बिगड़ गया है। दरअसल, यह ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। इस कारण सूखा, बाढ़ और महामारी का खतरा भी बढ़ा है। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी को देखकर चिंतित हैं। इस गर्मी का बढ़ना पृथ्वीवासियों के लिए एक तरह का खतरा हो गया है। इसके लिए बहुत हद तक इंसानी गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। इन गतिविधियों को नियंत्रित कर, तापमान को संतुलित रख पाना मुश्किल होता जा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले समय में इंसानों सहित अन्य जीवों के लिए भी यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के चलते पिछले 9 साल इतिहास में सबसे गर्म रहे। इन्हें लेकर पूरी मानवता को सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर अभी नहीं सुधरे तो स्थिति विकट हो जाएगी और धीरे-धीरे धरती का अस्तित्व मिट जाएगा।

मानव की विवेकहीनता के कारण तीन से पांच अरब वर्ष पुरानी पृथ्वी को अब खतरा पैदा हो गया है। लोगों को आगाह करने के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पिछले कई वर्षों से यह रस्म पूरी की जा रही है किंतु पृथ्वी पर मंडराता यह खतरा जस का तस बना हुआ है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा समाज एवं आम आदमी ही नहीं विभिन्न देशों की सरकारें भी इस समस्या के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं हैं। कथनी और करनी में फर्क के चलते हमारी पृथ्वी तेजी से अंधेरे की ओर बढ़ रही है। पृथ्वी को संकट से बचाने के लिए विकसित देश पर्यावरण संरक्षण की बढ़-चढ़कर बातें करते हैं किंतु उस पर अमल करने की बात पर टालमटोल करने लग जाते हैं। बढ़ते तापमान एवं जलवायु की बिगड़ती स्थिति से अब कोई भी देश अछूता नहीं रह गया है। जेनेवा स्थित 185 देशों के समूह विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों पर गहन विश्लेषण के बाद यह चेतावनी दी कि हमारे पास अब जरा भी मोहलत नहीं है।

पृथ्वी को लगातार बढ़ते तापमान एवं बिगड़ते वायुमंडलीय प्रभाव को बचाना है तो त्वरित एवं सख्त कदम उठाने होंगे। डब्ल्यूएमओ के मुताबिक सभी प्राकृतिक आपदाओं (बढ़ता तापमान, भारी वर्षा और भयंकर सूखा) के चलते ग्लोबल वार्मिंग ने पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तरी गोलार्द्ध से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पिछले 1000 वर्षों में किसी भी शताब्दी के मुकाबले 20वीं शताब्दी में तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ा है। पृथ्वी का तापमान आखिर निरंतर क्यों बढ़ रहा है?

धरती गरमाने के लिए ग्रीन हाउस गैसें उत्तरदायी हैं। इन गैसों में कार्बन डाईऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, नाईट्रिक ऑक्साइड व मीथेन प्रमुख हैं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो अधिकांश किरणें धरती स्वयं सोख लेती है और शेष किरणों को ग्रीन हाउस गैस सतह से कुछ ऊंचाई पर बंदी बना लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल में लगभग 15 से 25 किलोमीटर की दूरी पर समताप मंडल में इन गैसों के अणु ओजोन से ऑक्सीजन के परमाणु छीन लेते हैं और ओजोन परत में छेद कर देते हैं जिससे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें लोगों को झुलसाने लगती हैं। विश्व स्तर पर सुनिश्चित किया जा चुका है कि सीएफसी से निकलने वाला क्लोरीन का एक परमाणु शृंखला अभिक्रिया के परिणामस्वरूप ओजोन के 10000 परमाणुओं को नष्ट कर देता है। विकसित औद्योगिक देश अपने ऐश्वर्य के लिए ग्रीन हाउस गैसों में 80 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हैं जबकि विकासशील देश अभी भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 0.4 किग्रा प्रतिव्यक्ति के हिसाब से सीएफसी का इस्तेमाल हो रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अपनी जीवनशैली के चलते अकेला अमेरिका (जहां विश्व की मात्र 4 प्रतिशत जनसंख्या रहती है) 25 प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। एक अमेरिकी एक भारतीय से 18 गुना ज्यादा वायु को प्रदूषित करता है। स्रोत बताते हैं कि संपूर्ण विश्व में सीएफसी का 43 प्रतिशत हिस्सा अकेले यूरोप में इस्तेमाल होता है। जबकि दक्षिण एशिया के तमाम देश मिलकर वर्ष भर में केवल 6 प्रतिशत सीएफसी का ही इस्तेमाल करते हैं। वायुमंडल में सीएफसी की मात्रा बढ़ाने में किसी देश की साझेदारी कम या अधिक हो सकती है किंतु इससे होने वाले दुष्प्रभावों का खामियाजा सभी को समान रूप से भुगतना होता है। इससे भयावह बात और क्या हो सकती है कि सीएफसी से जितना प्रदूषण विश्व में एक वर्ष में होता है, उसके प्रभाव को नष्ट करने में 46 से 58 वर्ष लग जाते हैं।

ग्लेशियर तेजी से हो रहा गायब

एक नए अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, ग्रीनलैंड के पहले सबसे स्थिर ग्लेशियरों में से एक अब अभूतपूर्व दर से पीछे हट रहा है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि 2018 से 2021 के बीच, ग्रीनलैंड में स्टीनस्ट्रुप ग्लेशियर लगभग 5 मील पीछे हट गया है और 20 फीसदी पतला हो गया है। यह समुद्र में बहने वाली बर्फ की मात्रा में दोगुना हो गया है और गति में चौगुना हो गया है। अध्ययन के अनुसार, ग्रीनलैंड की बर्फ की संरचनाओं में इतना तेज बदलाव आम नहीं है, अब स्टीनस्ट्रुप ग्लेशियर को शीर्ष 10 फीसदी ग्लेशियरों में रखा गया है जो पूरे क्षेत्र के कुल बर्फ के बहाव में अहम भूमिका निभाता है। स्टीनस्ट्रुप ग्लेशियर द ग्रीनलैंड बर्फ की चादर का हिस्सा है, जो बर्फ का एक गोला है। यह दुनिया के सबसे बड़े द्वीप का लगभग 80 फीसदी को कवर करता है। यह क्रायोस्फीयर से दुनियाभर में समुद्र के स्तर में वृद्धि के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार भी है। यहां बताते चलें कि क्रायोस्फीयर, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का वह हिस्सा जिसमें सारा जमा हुआ पानी शामिल है। जबकि यह क्षेत्र दुनियाभर के जलवायु प्रणाली को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बर्फ का यह इलाका लगातार सिकुड़ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल इससे सैकड़ों, अरबों टन बर्फ पिघल रही है। पिछले कुछ दशकों में इस नुकसान में से अधिकांश को टाइड वाटर ग्लेशियरों, ग्लेशियरों के पिघलने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जो समुद्र में समा जाते हैं। कई ग्लेशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि बर्फ के पिघलने में इस हालिया उछाल को गर्म पानी के घुसपैठ से समझाया जा सकता है।

इंसान का रोल

ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भले ही दुनिया सतर्क होने का दावा करती हो, लेकिन अब तक इसे रोकने के दिशा में उठाए गए कदम नाकाफी ही साबित हुए हैं। यही वजह है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष लोगों को भीषण गर्मी का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2050 तक धरती का तापमान 2 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि धरती पर आग बरसेगी। लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। एसी जैसे उपकरण भी काम करना बंद कर देंगे। लोगों की त्वचा झुलसने लगेगी। उनमें त्वचा कैंसर समेत, डिहाइड्रेशन और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा।

फसलों पर जलवायु परिवर्तन का दिखेगा भारी असर

देश में बदलती जलवायु का असर कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है, जहां गेहूं तथा अन्य फसलों के पकते समय ओलावृष्टि तथा बेमौसम बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। नुकसान लगभग देश के सभी हिस्सों में हुआ है लेकिन भारत के उत्तर, पश्चिम और पूर्वी हिस्से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। वहीं पिछले कुछ दशकों में, यह स्पष्ट हो गया है कि जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामस्वरूप चरम मौसम की घटनाएं, फसल की पैदावार पर कहर बरपा सकती हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच कृषि में बड़ी असमानता है। एक नए अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने फसल की पैदावार पर जलवायु परिवर्तन के छोटी तथा लंबी अवधि में पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की पड़ताल की है। कृषि और उपभोक्ता अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मधु खन्ना ने कहा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मापने वाले अधिकांश अध्ययन साल-दर-साल बदलावों को देख रहे हैं, जो मौसम में बदलाव से संबंधित हैं। हमने 60 वर्षों के आंकड़ों का उपयोग यह जांचने के लिए किया कि लंबी अवधि के औसत से मौसम में बदलाव तीन प्रमुख फसलों- चावल, मक्का और गेहूं की पैदावार को किस तरह प्रभावित करता है। मौसम में बदलाव कुछ समय के लिए होता है, जैसे गर्म दिन के बाद अचानक गरज के साथ बौछारें पड़ना। हालांकि, इस तरह की विविधताएं लंबे समय में अलग-अलग हो सकती हैं, जो जलवायु परिवर्तन की पहचान हैं। खन्ना ने कहा, हम यह देखना चाह रहे थे कि क्या लंबे समय के औसत की तुलना में अत्यधिक तापमान और वर्षा की छोटी अवधि के दौरान होने वाला प्रभाव अहम है। यदि उनके प्रभाव लंबी अवधि तक नहीं रहते हैं, तो किसान जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले दो दशक के दौरान धरती का तापमान एक डिग्री पहले ही बढ़ चुका है। इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रतिवर्ष लोगों को भीषण गर्मी और उमस झेलनी पड़ रही है। इसके बावजूद लोग सतर्क और जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए विश्व के सभी देशों को मिलकर ठोस कदम उठाना होगा। साथ ही दुनिया के सभी नागरिकों को भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। हर किसी को अपनी छोटी-बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। पौधरोपण का दायरा बढ़ाना होगा। हर व्यक्ति को शपथ लेनी होगी कि वह प्रतिवर्ष कुछ पौधे जरूर लगाएंगे और वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। ताकि धरती का तापमान कम हो सके। यदि जलवायु परिवर्तन को होने से नहीं रोका गया तो इसके परिणाम भयावह होंगे।

वैज्ञानिक अब और ज्यादा आश्वस्त होते जा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंसानी प्रभावों के कारण ही वायुमंडल, महासागर और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हमेशा से ही यह बहस का विषय का रहा है कि जलवायु परिवर्तन में मानव की कितनी भूमिका है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक गैब वेची कहते हैं कि गर्मी बढ़ने के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों ने अपने अब तक के शोधों में पाया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें खासतौर पर कार्बन डाईऑक्साइड जिम्मेदार है। यह अधिकांश जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलती है। पिछले 30 से भी अधिक वर्षों से बहुत सारे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के कारणों पर अलग-अलग तरह से अध्ययन कर, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के क्या-क्या कारण हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग हर रिपोर्ट में इसकी एक ही वजह निकलकर सामने आई है और वह है बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान।

कार्बन डाईऑक्साइड की भूमिका

अपने अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया कि हर साल सूर्य सामान्य रूप से 1361 वाट वर्ग प्रति मीटर की ऊष्मा उत्सर्जित करता है, इससे पृथ्वी पर जीवन का बढ़िया संतुलन बना हुआ है। सूरज की रोशनी या ऊर्जा में बदलाव बहुत कम होता है। यह बदलाव सूरज विकरण के दसवें हिस्से से ज्यादा नहीं होता है। वहीं, अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार, जीवाश्म ईंधन के जलने पर बनने वाली कार्बन डाईऑक्साइड अब 2.07 वाट प्रति वर्ग मीटर ऊष्मा अवशोषित कर रही है। पृथ्वी पर कार्बन डाईऑक्साइड का अवशोषण, सूर्य के विकिरण में होने वाले बदलाव से 20 गुना ज्यादा होता है। वहीं, दूसरी ओर मीथेन 0.5 वाट प्रति वर्गमीटर की दर से अवशोषण करती है। सूर्य का एक सौर चक्र 11 साल तक चलता है, लेकिन इसका भी पृथ्वी के तापमान पर कोई खास असर दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग में सूर्य की भूमिका नहीं है। जलवायु परिवर्तन की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कहीं सूखा और कहीं बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन्हें लेकर पूरी मानवता को सतर्क होने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का तापमान लगाता बढ़ता जा रहा है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और नासा ने इसी तरह के 2022 तक के वैश्विक तापमान के आंकड़े जारी किए और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख बिल नेल्सन ने उन्हें खतरनाक बताया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया का रिकॉर्ड पांचवां सबसे गर्म साल था और इसी की तरह पिछले 9 साल रिकॉर्ड सबसे गर्म साल थे।

लक्ष्य को झटका

अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार 2015 के पेरिस समझौते के ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को यह एक गंभीर खतरे में डाल सकता है। नासा के अनुसार पिछला साल 1880 में रिकॉर्ड-कीपिंग शुरू होने के बाद से पांचवें सबसे गर्म साल के रूप में पाया गया है। इसी के चलते कई जगह जंगलों में आग तक देखने को मिली। कैलिफोर्निया के पास फेयरव्यू जंगल में तो आग पर कई दिनों बाद काबू पाया गया था। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जलवायु प्रकृति की ही गतिविधि होने के नाते उसमें परिवर्तन स्वाभाविक ही है।

अगर जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया न होती तो सूर्य से निकली यह पृथ्वी आग का गोला बनी रहती। न तो शीतलन की प्रक्रिया होती, न हिम युग आते और ना ही जीवन की उत्पत्ति होती। लेकिन जब परिवर्तन की गति अस्वाभाविक रूप से बढ़ने लगे तो वह न केवल मानव जीवन बल्कि धरती के समूचे जल, थल और नभचरों के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है, और इस गंभीर चुनौती के लिए मानवजनित क्रिया-कलाप ही प्रमुख कारक हैं। इस चुनौती से विश्वभर के योजनाकार, सरकारें तथा पर्यावरणवादी चिंतित हैं।

भारत के लिए ज्यादा समस्या

जलवायु परिवर्तन का पहले से ही पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें लगातार भीषण गर्मी या लू, सूखा, बाढ़, तूफान और समुद्र का बढ़ता स्तर शामिल है। यह जैव विविधताओं के नुकसान का कारण भी बन रही है और मानव स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधनों को भी प्रभावित कर रही है। यद्यपि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण भारत के लिए यह समस्या कुछ ज्यादा ही चिंताजनक है। भारत के संदर्भ में जलवायु का महत्व आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। आबादी के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अत्यंत घनी आबादी वाला यह देश कृषि प्रधान है, जहां दो तिहाई से अधिक लोग गांवों में निवास करते हैं तथा खेती पर निर्भर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर जलवायु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। भारत में मौसम विज्ञान संबंधी रिकॉर्ड वर्षा की मात्रा में अधिक परिवर्तन न होते हुए भी वायु तापमान में वृद्धि की ओर संकेत करते हैं। भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की समस्या इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि इसने अपने माथे पर विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय को धारण किया हुआ है, जो कि निर्माण की प्रक्रिया में होने के कारण उसका पारितंत्र बहुत संवेदनशील है। हिमालय अपने आप में संपूर्ण एशिया का वाटर टावर और जलवायु नियंत्रक है। यह हिम-आलय जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा-आलय बन रहा है।

जलवायु परिवर्तन के कारण सन् 2013 में समय से पहले 16 जून को ही मानसून हिमालय पर चढ़ जाता है और बादल वहां फटता है जहां सीधे हिमपात होता है। इसी का नतीजा केदारनाथ की आपदा थी जिसमें हजारों तीर्थ यात्री मारे गए थे, समूची केदारघाटी तबाह हो गई थी। सर्दी के मौसम में जब हिमालय में नदियां जमने लगती हैं तब फरवरी 2021 में धौलीगंगा-ऋषिगंगा की बाढ़ आ गई जिनमें सैकड़ों लोगों के मरने के साथ ही अरबों रुपए लागत के प्रोजेक्ट नष्ट हो गए।

जलवायु परिवर्तन से हुए अधिक घातक

देशभर में मच्छरों का प्रकोप दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। हाल में ही बेंगलुरू, दिल्ली-एनसीआर और उप्र में मच्छरों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे बेमौसम बारिश के साथ क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं इसकी वजह से मच्छर पहले की तुलना में अधिक घातक होते जा रहे हैं। वहीं उन पर मच्छर रोधी दवाओं का असर भी कम हुआ है। बीते कुछ दिनों में बेंगलुरू में मच्छरों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षभर बारिश के साथ-साथ अनियमित तापमान के साथ आर्द्र परिस्थितियों ने शहर और आसपास के क्षेत्रों को मच्छरों के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल में बदल दिया है। दिल्ली में भी बीते हफ्ते मच्छरों की तादाद में बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में पिछले एक पखवाड़े में मच्छरों के घनत्व में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि मच्छरों की नई फसल क्यूलेक्स जीनस की है, जिससे डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया नहीं होता है। क्यूलेक्स मच्छर ज्यादातर कम हानिकारक होते हैं। यह त्वचा में जलन पैदा करते हैं। उनकी अधिक मौजूदगी नालियों और जल निकायों में बहुत अधिक ठहराव और तैरने वाली सामग्री का संकेत देती है क्योंकि वे रुके हुए पानी में प्रजनन करते हैं। मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर साप्ताहिक रिपोर्ट में प्रजनन स्थलों का पता लगाने में वृद्धि देखी गई।

कृषि पर दुष्प्रभाव

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, भारत की अर्थव्यवस्था और खासकर इसके कृषि क्षेत्र पर नजर आने लगे हैं। कृषि क्षेत्र देश के आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है और इसके सकल घरेलू उत्पाद के एक महत्वपूर्ण हिस्से में भूमिका निभाते हैं। जलवायु में परिवर्तन से बाढ़, सूखा और लू जैसी चरम मौसमी घटनाओं के कारण फसल की पैदावार में कमी आती है। बार-बार प्राकृतिक आपदाओं के आने और उनकी तीव्रता, जैसे बाढ़ और चक्रवात, जलवायु परिवर्तन के साथ बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे बुनियादी ढांचे, फसलों और आजीविका को काफी नुकसान होता है। जलवायु पविर्तन से वर्षा के बदलते पैटर्न के कारण पानी की कमी या सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुविधाओं के अभाव में खेती वर्षा पर निर्भर रहती है। यही नहीं इस स्थिति में कीट और रोग भी फैल सकते हैं, जो फसलों को नष्ट कर देते हैं और गंभीर आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। कृषि के अलावा जलवायु परिवर्तन अन्य उद्योगों जैसे पर्यटन, मत्स्य पालन और वानिकी पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जो आगे चलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

बढ़ रही हैं आपदाएं

समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती आबादी के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर सरकार पर्यावरणीय मापदंडों की अपेक्षा कर बैठती है। इसका जीता जागता उदाहरण उच्च हिमालई संवेदनशील क्षेत्र में ऋषिगंगा और धौलीगंगा जैसे बिजली

प्रोजेक्टों को मंजूरी देना है। पारितंत्र की उपेक्षा और विकास की अंधी दौड़ का एक और उदाहरण उसी सीमांत जिला चमोली का आपदाग्रस्त जोशीमठ शहर है।

सूखे की आशंका बढ़ी

क्लाइमेट चेंज की वजह से ईस्ट अफ्रीका में सूखा पड़ने की आशंका 100 प्रतिशत बढ़ गई है। इसका खुलासा वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की रिपोर्ट में हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया कि ढाई साल से अफ्रीका में एवरेज से कम बारिश हुई और ज्यादातर वक्त मौसम गर्म रहा। इस वजह से फसलें मुरझा गईं और जल गईं। कई जानवरों की मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया- जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में से एक ईस्ट अफ्रीका (हॉर्न ऑफ अफ्रीका) को अकाल के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश बसे हैं। यहां हजारों लोग भुखमरी और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सोमालिया में सिविल वॉर चल रहा है। वहां के हालात लड़ाई के कारण पहले से ही खराब थे, लेकिन सूखे ने हालात और बिगाड़ दिए। इससे देश में अस्थिरता बढ़ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में 43 हजार से ज्यादा लोगों की मौत सूखा पड़ने के कारण हुई। इनमें ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि ईस्ट अफ्रीका में पिछले ढाई साल में कम बारिश हुई, ऐसा 70 साल में पहली बार हुआ है कि इतने लंबे समय तक बारिश न के बराबर हुई हो और गर्मी हद से ज्यादा बढ़ी हो। स्टडी के मुताबिक, हर साल ये अवधि 5 प्रतिशत बढ़ सकती है। रिपोर्ट बनाने वाली रिसर्चर्स की टीम की सदस्य और केन्या मौसम विभाग की मेट्रोलॉजिस्ट जॉयस किमुताई का कहना है कि इसका एक कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है इसके मुकाबले बारिश नहीं हो रही है। इसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में आकाल पड़ सकता है।

18 वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च की। इसमें बाढ़, हीटवेव जैसे

एक्सट्रीम वेदर चेंज की वजह जानने पर फोकस किया गया। वैज्ञानिक जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन अलग-अलग मौसम के बिगड़ने के पीछे एक ही वजह ग्लोबल वॉर्मिंग कैसे हो सकती है। इसका रोल क्या है, ये जानने के लिए रिसर्च हुई। आसान शब्दों में कहें तो ये बिलकुल स्मोकिंग और कैंसर की तरह है। सब जानते हैं कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है। लेकिन स्मोकिंग करने वाले हर शख्स को कैंसर नहीं होता और हर कैंसर मरीज स्मोकिंग करता हो, ये भी जरूरी नहीं।

रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन की वजह इंसानों को बताया गया। इसमें कहा गया कि अमीर देशों के लोग, वहां की कंपनियां फॉसल फ्यूल जला रहे हैं। इसका असर गरीब देशों पर पड़ रहा है। केन्या के थिंक टैंक-पावर शिफ्ट अफ्रीका के डायरेक्टर मोहम्मद अडोव का कहना है कि क्लाइमेट चेंज फ्यूचर की समस्या नहीं है। ये प्रेजेंट है। लोग इसे झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को मदद मिलनी चाहिए।

पिछले साल इजिप्ट में सीओपी27 क्लाइमेट समिट हुई। इसमें इकट्ठा हुए 200 देशों ने अमीर देशों को क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि अमीर देश एक फंड बनाएंगे, जिससे गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के हेड हरजीत सिंह का कहना है कि अब देखना होगा कि इस फंड का सही से इस्तेमाल किया जाए।

पिछले 7 साल में बिगड़े हालात

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि समुद्रों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिससे शहरों के डूबने का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। हालात ये हैं कि पिछले 20 साल में जितना नुकसान हुआ, उतना पिछले 7 साल में हो चुका है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।

डब्ल्यूएमओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ग्लेशियरों को बचाना होना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो समुद्रों का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे एक दिन धरती के डूबने का खतरा है। इसके पीछे ग्रीन हाउस गैस को एक बड़ा कारण बताया गया है, जिसे रोकने की जरूरत है। यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक एक साल में ग्लेशियरों की मोटाई करीब साढ़े चार फीट तक कम हो गई। जिससे समुद्रों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिससे इंडोनेशिया के जकार्ता जैसी हालत सभी कोस्टल शहरों में हो सकती है। कहा गया है कि अगर खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो ये काफी खतरनाक हो सकता है।

मीथेन बन गई है चुनौती, धरती के जीवन का भविष्य खतरे में

हमारे एकमात्र जीवनदाता ग्रह पर जलवायु परिवर्तन की मानव-जनित लीला यूं ही खिंचती रही, तो जीवन की कड़ियां जल्द ही टूटने लगेंगी। वैसे एंथ्रोपोसीन काल में जीव प्रजातियों के छठे महाविनाश की लीला भी चल रही है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस शताब्दी के अंत तक पृथ्वी से लगभग आधी जीव प्रजातियां काल के गाल में समा जाएंगी। जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंध मानव कार्यकलाप से है। इस वर्ष फरवरी माह ने पृथ्वी पर ज्ञात जलवायु इतिहास में गर्माहट की एक ऊंची छलांग लगाई, और अब आगे के महीने गर्मी की अनन्य कथाएं रचने जा रहे हैं। इसके संकेत उत्तरी अमेरिका से मिलने प्रारंभ हो गए हैं, जहां कनाडा में ओंटारियो प्रांत के पीटरबरो शहर का तापक्रम 13 अप्रैल को 30.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि यहां का ताप इन दिनों सामान्यतः शून्य से नीचे रहता था। इस बीच, वातावरण में अबाध रूप से बढ़ती कार्बन डाईऑक्साइड के अतिरिक्त जलवायु विशेषज्ञों की दृष्टि सार्वभौमिक गर्माहट के एक और जिन्न पर जमी है, वह है मीथेन। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) ने विगत दिनों बताया कि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन की 2022 में चौथी उच्चतम वार्षिक वृद्धि हुई है, जो कि ग्रीनहाउस गैसों में समग्र वृद्धि का हिस्सा है।

चुनौती बनी बढ़ती जनसंख्या

बेरोजगारी बनेगी बड़ी समस्या

शहरों के विकास में जितना भ्रष्टाचार है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सरकारी एजेंसियां जिन पर शहरों के नियोजन और विकास की जिम्मेदारी है, वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिन इंजीनियरों पर बढ़ती आबादी के चलते आधारभूत ढांचे के निर्माण की रुपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी है वे अपना काम सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और इसी कारण हमारे शहर समस्याओं से जूझ रहे हैं। बढ़ती आबादी की चुनौती के बीच ऐसी कोई योजना न तो केंद्र सरकार के पास है और न ही राज्य सरकारों के पास, जो शहरों को संवार सके और वहां उद्योग-धंधों का तेजी से विकास हो सके और वे रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। भारत की जनता नेताओं से नतीजे तो चाहती है, लेकिन वे उसे इसलिए नहीं मिलते, क्योंकि नेताओं ने लोगों को जात-पात और मजहब के आधार पर बांट रखा है। खुद भारतीय समाज जात-पात और मजहब आधारित राजनीति के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वह भारत को विकसित देश बनते हुए तो देखना चाहता है, लेकिन जाति-मजहब की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहा। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, बढ़ती आबादी से उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

यह सर्वविदित है कि संयुक्त राष्ट्र के ताजा अध्ययन ने भारत को विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश घोषित कर दिया है। भारत की वास्तविक आबादी का पता तो जनगणना के बाद ही चलेगा जो कि 2021 से लंबित है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के आंकलन ने विश्व का ध्यान भारत की बढ़ती आबादी की तरफ खींचा है। हम 1960 से 1980 के बीच के उस दौर को नहीं भूल सकते जब राजनीतिक विमर्श यह था कि भारत की विशाल आबादी संसाधनों पर बोझ है और उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। आज भी बहुत से भारतीय यह मानते हैं कि देश की अनेक समस्याओं का कारण भारत की विशाल आबादी है। ऐसे लोग उन नीति नियंताओं को कठघरे में खड़ा करते हैं, जिनकी अदूरदर्शिता के कारण आबादी पर अंकुश नहीं लगा और भारत आबादी के मामले में चीन से आगे निकल गया। भारत और चीन में अगर कोई अंतर था तो यह कि आजादी के बाद भारत ने जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई, वहीं चीन ने एक पार्टी के शासन को अपनाया। भारत के राजनीतिज्ञों ने लोकतंत्र को अपने ही निजी हित में अधिक उपयोग किया और यह बहाना गढ़ा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीजें धीरे काम करती हैं। यह सही नहीं और इसका प्रमाण यह है कि कई लोकतांत्रिक देशों ने उल्लेखनीय प्रगति कर दिखाई है।

पिछले कुछ समय से यह विमर्श सामने आया है कि देश की युवा आबादी का सही तरीके से नियोजन किया जाए तो भारत आर्थिक तौर पर एक महाशक्ति बन सकता है। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही युवा आबादी के डेमोग्रेफिक डिवीडेंड की बात करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह कहते रहे हैं कि हमारी युवा आबादी देश की आर्थिक प्रगति की गाथा लिखेगी। निसंदेह ऐसा तभी संभव है, जब उसका सही तरह नियोजन किया जाएगा। मोदी सरकार युवा आबादी के नियोजन के लिए लगातार योजनाएं भी बना रही हैं। इन योजनाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती वह शिक्षा व्यवस्था है, जो पटरी से उतरी हुई है। यह ठीक है कि मोदी सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है, पर उसके नतीजे आने में समय लगेगा। आज स्थिति यह है कि कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी सब जगह जो शिक्षा दी जा रही है, उससे हमारे युवा सक्षम नहीं बन पा रहे। वे उद्योग-व्यापार जगत की जरूरतों और उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। कौशल विकास के मामले में पिछली सरकारों की शिथिलता आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती से पार पाने में लंबा समय लग सकता है। इस चुनौती का सही तरह से सामना करने के लिए नई शिक्षा नीति को ढंग से लागू करने के साथ शिक्षा के आधारभूत ढांचे को ठीक करना होगा।

यह सही है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है, लेकिन वह भली तरह शिक्षित नहीं है। भारत की बहुत बड़ी आबादी दिशाहीन है और उसके पास रोजगार के पर्याप्त अवसर भी नहीं हैं। भारत की आबादी एक चुनौती थी और आगे भी रहेगी, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है, यदि उसका नियोजन सही तरह किया जाए। युवा आबादी के जो लाभ गिनाए जा रहे हैं, उनसे इनकार नहीं, लेकिन इस आबादी के समुचित उपयोग के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन्हें जमीन पर सही तरह उतारना एक चुनौती बना हुआ है। भले ही भारतीयों की मेधा की बात विश्व स्तर पर होती हो, लेकिन कुछ चुनिंदा मेधावी और सफल भारतीयों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे सभी युवा मेधावी हैं और उनकी मेधा का सही उपयोग हो रहा है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारत ज्ञान का केंद्र बन रहा है। देश को ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए शिक्षा और शोध की दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा और शोध की गुणवत्ता के मामले में भारत तमाम देशों से पीछे है। सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा कि नौकरियों की आस में गांवों से शहर आ रहे युवा किस तरह अपने को इतना सक्षम बनाएं कि वे आसानी से रोजगार पा सकें।

इस संदर्भ में कौशल विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वे अभी प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। कौशल विकास के मामले में अभी हम बहुत पीछे हैं। युवाओं को कौशल से लैस करने के साथ ही इसकी भी आवश्यकता है कि वे अनुशासित बनें और उस संस्कार से लैस हों, जिसके लिए भारत दुनियाभर में जाना जाता है। अनुशासन **और संस्कारों** के बिना इतनी बड़ी आबादी का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। हमारा अनुशासन और संस्कार क्यों बिगड़ रहा है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। भारत की जितनी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, वह बहुत अधिक है। इतनी अधिक आबादी की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता ठीक नहीं। चूंकि कृषि की उत्पादकता कम है, इसलिए गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इससे शहरों का ढांचा चरमरा रहा है। भारत की विशाल आबादी शहरों के लिए बोझ बन रही है। आने वाले समय में यह बोझ और अधिक बढ़ेगा। राज्य सरकारों और नगरीय निकायों की अदूरदर्शिता के कारण शहरों का ढांचा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।

● **बृजेश साहू**

कर्नाटक का असर

कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव 'करो या मरो' वाला बन गया है क्योंकि उसका प्रदर्शन ही 2024 के आम चुनाव में उसकी संभावनाओं को दिशा देगा। बेहतर प्रदर्शन करने पर ही वह विपक्षी एकता की धुरी बन सकती है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी 10 मई को राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। यह चुनाव भले ही एक राज्य में हो रहा है, लेकिन इसके परिणामों की अनुगूंज राष्ट्रीय स्तर तक सुनी जाएगी। कर्नाटक दक्षिण में भाजपा का एकमात्र दुर्ग है और यहां पराजित होने पर दक्षिण में विस्तार की उसकी संभावनाओं को पलीता लगेगा। वहीं कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव निर्णायक बन गया है। लंबे अरसे के बाद गांधी-नेहरू परिवार से इतर पार्टी की कमान संभालने वाले मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक से ही आते हैं। इसलिए पार्टी और उसके अध्यक्ष की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। राजनीतिक हाशिये पर चल रहे जद-एस के सामने भी अपनी ताकत साबित करने की चुनौती है कि वह राजनीतिक पंडितों द्वारा उसे खारिज करने के दावों को गलत सिद्ध करे।

कांग्रेस के लिए तो यह चुनाव 'करो या मरो' वाला बन गया है, क्योंकि उसका प्रदर्शन ही 2024 के आम चुनाव में उसकी संभावनाओं को दिशा देगा। बेहतर प्रदर्शन करने पर ही वह विपक्षी एकता की धुरी बन सकती है। अन्यथा राजनीतिक मोलभाव की उसकी शक्ति घट जाएगी। अभी तक के रुझानों के हिसाब से कांग्रेस के लिए कर्नाटक की राह अपेक्षाकृत आसान लग रही है। इसमें राज्य में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल की भी एक अहम भूमिका है। बासवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। वहीं, टिकट वितरण में भी असंतोष स्पष्ट दिखा। क्षुब्ध नेता पार्टी से पलायन कर रहे हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में प्रभावी **लिंगायत समुदाय से आने वाले** जगदीश शेट्टार जैसे चेहरे भी शामिल हैं।

हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भाजपा को इसका कितना नुकसान होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि उसने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देकर सत्ताविरोधी रुझान को थामने का दांव चला है। उसकी यह रणनीति अन्य राज्यों में भी फलदायी सिद्ध होती आई है। जहां तक लिंगायत समुदाय की बात है तो पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अभी भी इस तबके के सबसे बड़े और व्यापक स्वीकार्यता वाले नेता माने जाते हैं। कांग्रेस में सतही तौर पर तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी की प्रदेश इकाई के मुखिया डीके शिवकुमार के बीच खटपट किसी से छिपी नहीं है। पिछले चुनावों में किंगमेकर बनकर उभरे जद-एस में भी टिकट वितरण को लेकर आक्रोश है। देवेगौड़ा परिवार में ही खींचतान जारी है। उन पर हद से ज्यादा परिवार केंद्रित होने के आरोप लग रहे हैं। देखा जाए तो तीनों ही दल किसी न किसी तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं।

कर्नाटक के चुनाव में हाल के महीनों में स्थानीय मुद्दे काफी तेजी से उभरे हैं। भाजपा वहां राष्ट्रीय मुद्दे उभारने की कोशिश में है, ताकि कांग्रेस को बढ़ने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी चुनावी दौरे भाजपा ने रखे हैं। उसका भरोदा मोदी पर ही टिका है। यह माना जाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और उनकी सरकार भी कई बार विवादों में घिरी है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। इसे ही कांग्रेस सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाए हुए है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव इसलिए भी इज्जत का चुनाव है, क्योंकि उसके नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक से हैं। खरगे ने राहुल गांधी से मिलकर कर्नाटक के टिकट तय किए हैं। वैसे भी कांग्रेस जब 166 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी, तब जाकर भाजपा ने उम्मीदवार घोषित करने शुरू किए। कांग्रेस की इस पहल का लाभ प्रचार के रूप में उन उम्मीदवारों को मिला, जिनके नाम घोषित हो चुके थे। कर्नाटक का चुनाव राहुल गांधी के लिए भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अहम है। उनकी 'भारत जोड़ो यात्रा' काफी दिन तक कर्नाटक में रही थी और उसे जनता का खासा समर्थन भी मिला था। यह पहला ऐसा चुनावी राज्य होगा, जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है। जाहिर है जीत की स्थिति में कांग्रेस इसका श्रेय राहुल गांधी को देगी। कांग्रेस ने दिसंबर में हिमाचल विधानसभा चुनाव भी जीता था; लेकिन राहुल तब तक यात्रा के लिए वहां नहीं गए थे। राहुल गांधी अब कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की जनसभाएं भी कांग्रेस ने वहां रखी हैं। प्रियंका गांधी का कांग्रेस में रोल धीरे-धीरे विस्तार ले रहा है, इसमें कोई दो-राय नहीं है। हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी को बड़े रोल के रूप में जनता के सामने करे। फिलहाल तो राहुल गांधी ही पार्टी के प्रधानमंत्री का चेहरा हैं। प्रधानमंत्री

क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे

कर्नाटक में क्षेत्रीय मुद्दे चलेंगे या राष्ट्रीय? कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर अभियान चला रही है, जबकि भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों पर उतर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के कर्नाटक दौरों में उनके भाषण देखें, तो वह राष्ट्रीय मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। इसका कारण भाजपा का यह डर भी है कि उसकी सरकार की कारगुजारी उतनी अच्छी नहीं रही है कि वह उसके सहारे वोट ले सके। इसके अलावा भाजपा हिंदुत्व का एजेंडा छूने से भी नहीं हिचक रही। हाल के महीनों में कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा चलाने की काफी कोशिश की गई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कर्नाटक की राजनीति में क्षेत्र बड़े कारक हैं। चिकमंगलूर में वोक्कालिगा और लिंगायत बहुलता है, जबकि उडुपी इलाके में हिंदू क्षत्रिय प्रभावी भूमिका में हैं। मैसूर में जहां जेडीएस प्रमुख पार्टी रही है, वहीं चिकमंगलूर और उडुपी में भाजपा-कांग्रेस में टक्कर है। कर्नाटक में इस बार मुस्लिम वोटर भी एक बड़ा कारक होगा।

सत्ता के लक्ष्य पर निशाना लगाना आसान नहीं

कर्नाटक की विखंडित राजनीति को देखते हुए यहां सत्ता के लक्ष्य पर निशाना लगाना आसान नहीं है। राज्य की राजनीति में यह विखंडन न केवल क्षेत्रीय आधार पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी दिखता है। उत्तरी कन्नड़ और तटीय इलाकों में जहां भाजपा की बढ़िया पैठ है तो आंध्र से लगते मध्यवर्ती हिस्सों में कांग्रेस का अच्छा-खासा प्रभाव है और मैसुरु वाले दक्षिणी हिस्से में जद-एस या यूं कहें कि देवेगौड़ा परिवार की ठीक-ठाक पकड़ है। इस बिखराव का असर जनादेश में भी दिखता है। यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों में कर्नाटक में किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार सिर्फ एक बार बनी है। 2013 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के पीछे का एक बड़ा कारण यह भी था कि तब येदियुरप्पा ने भाजपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था। अब देखना होगा कि क्या ये तीनों दल अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में अपना आधार बरकरार रखते हुए दूसरे क्षेत्रों में भी पैठ बनाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। राज्य के प्रभावी लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों को साधने में भी सभी दल अपनी कोशिश में लगे हैं। राज्य में करीब 16 से 18 प्रतिशत संख्या लिंगायतों की है और ये पिछले कुछ समय से भाजपा के पारंपरिक मतदाता माने जाते हैं।

मोदी के साथ-साथ गृहमंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में भाजपा की चुनावी कमान संभाले हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रणनीति के अलावा संगठन की जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं।

इस साल अब तक उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें त्रिपुरा में भाजपा ने बहुमत हासिल किया था और अन्य दो मेघालय और नागालैंड में उसे क्रमश: 3 और 12 सीटें ही मिलीं थीं। अब कर्नाटक की चुनौती उसके सामने है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस उसे वहां कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। भाजपा कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत दक्षिण भारत के इस राज्य में झोंक रही है। कर्नाटक उन 6 बड़े राज्यों में शामिल है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में लोकसभा के 543 सदस्यों में से 28 (कुल सदस्यों का 5.35 फीसदी) चुने जाते हैं। देखा जाए, तो कर्नाटक देश के सबसे कम सांसदों वाले राज्यों की सूची में सातवें नंबर पर है। इतिहास पर नजर दौड़ाएं, तो जाहिर होता है कि राज्य में कांग्रेस के दबदबे को भाजपा ने अपने गठन के समय ही सन् 1980 में चुनौती दी और 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 पर जीत हासिल की। पांच साल बाद सन् 1985 में भाजपा लड़ी, तो 116 सीटों पर लेकिन उसे 2 ही सीटें नसीब हुईं। इसका कारण था रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में जनता पार्टी का 139 सीटें जीतना, जिसने कांग्रेस भी ठिकाने लगा दिया। सन् 1989 में भी भाजपा को 4 ही सीटें मिलीं। हालांकि राममंदिर आंदोलन के बाद नब्बे के दशक में भाजपा का प्रभाव बढ़ा। सन् 1994 के चुनाव में उसे 40 और सन् 1999 में 44 सीटें मिलीं। सन् 2004 में वह 79 सीटों पर पहुंच गई और आखिर सन् 2007 में पार्टी को बीएस येदियुरप्पा के रूप में अपना पहला मुख्यमंत्री भी मिल गया। लेकिन एक हफ्ते में ही सहयोगी जेडीएस ने हाथ खींच लिए और येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा।

सन् 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए और भाजपा को इस बार 110 सीटें हासिल हुईं। पार्टी ने दोबारा येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। वह अगस्त, 2011 तक मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि उनकी जगह पार्टी ने सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया, जो एक साल से पहले ही चलते बने और भाजपा ने इस बार जगदीश शेट्टार को सौंपा। लेकिन सन् 2013 के चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर 40 पर आ गईं और कांग्रेस ने सरकार बनाई। येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के मामलों में उलझे, जिससे उन्हें और पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। सन् 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इसके बाद सन् 2018 में हुए चुनाव में भाजपा को 104 सीटें मिलीं, लेकिन उसका बहुमत नहीं हुआ। लिहाजा कांग्रेस और जेडीएस ने गुपचुप समझौता करके सरकार बना ली। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के लोगों को फोड़कर सरकार गिरा दी और येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक साल पहले पार्टी ने उनकी जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया। कर्नाटक में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जिसने कभी भी 26 फीसदी से कम मत हासिल नहीं किए। अब तक के आखिरी चुनाव में उसे सन् 2018 में 38.09 फीसदी वोट हासिल हुए थे, जो भाजपा के मुकाबले दो फीसदी ज्यादा थे। सन् 1983 में पहली बार कर्नाटक में गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री बना था।

एक जमाना वह भी था जब कई सीटों पर कांग्रेस के विधायक निर्विरोध ही चुन लिए जाते थे। जेडीएस के उभार से भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उनका वोट बैंक कई जगह एक-सा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भले भाजपा ने राज्य में 25 सीटें जीत ली थीं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत दिख रही है। कर्नाटक की राजनीति को गहराई से देखने पर जाहिर होता है कि भाजपा कभी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट शेयर को पार नहीं कर पाई। कांग्रेस इस बार कर्नाटक में खास जोर लगा रही है। उसे उम्मीद है कि भाजपा सरकार के प्रति जनता में गुस्सा है और इसका कारण भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष बीएन चंद्रप्पा ने बताया कि जनता कांग्रेस को सत्ता में ला रही है। कमीशन वाली सरकार जा रही है। हमारे मुद्दे साफ हैं और कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है।

कांग्रेस इस बार पूरी तरह अपने दम पर चुनावी मैदान में डटी है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक एक मजबूत गढ़ रहा है। हालांकि हाल के दशकों में कांग्रेस का राज्य में आधार खिसका है। सन् 1952 से सन् 1983 तक राज्य, जिसे पहले मैसूर कहा जाता है, में कांग्रेस लगातार सत्ता में रही। हालांकि सन् 1983 के चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा जब जनता दल ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन सन् 1989 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। वह भी रिकॉर्ड सीटों के साथ। सन् 1989 में कांग्रेस की जीती 178 सीटों का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। कांग्रेस ने न सिर्फ यह चुनाव जीता, बल्कि पांच साल बाद सन् 1999 में 132 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई। लेकिन उसका जादू सन् 2004 में टूट गया और उठापटक के दौर के बाद सन् 2006 में हुए चुनाव में उसने जेडीएस के साथ सरकार में हिस्सेदारी की, जिसका नेतृत्व उसके हाथ में नहीं था।

● **विपिन कंधारी**

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी एक साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता अभी से बढ़ गई है। विपक्ष को एकजुट करने के कई प्रयास हो चुके हैं। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता में लगे हुए हैं। अभी तक की उनकी कोशिशों से तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष एक हो जाएगा, लेकिन इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हर पार्टी का नेता अपने आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखता है।

विपक्षी एकता की कवायद तेज

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के नतीजों से फिलहाल यह तय हो गया है कि व्यापक विपक्षी एकता की पहल आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी। बेशक विपक्षी एकता के ठोस स्वरूप की तस्वीर इन नेताओं की बैठक में अभी साफ नहीं हुई, मगर तृणमूल कांग्रेस और सपा दोनों दलों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि कांग्रेस के विपक्षी एकजुटता की धुरी बनने से उन्हें कोई परहेज नहीं होगा। साथ ही विपक्षी खेमे के लिए एक सकारात्मक संकेत यह भी है कि फिलहाल विपक्षी एकता की गाड़ी नेतृत्व विवाद के गतिरोध में भी नहीं फंसेगी। विपक्षी सियासत को एक मंच पर लाने के लिए कोलकाता और लखनऊ में शुरू हुई कसरत इस बार नीतीश कुमार के मैदान में उतरने की वजह से ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हुई चर्चाओं के बाद नीतीश ने ममता, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को विपक्षी एकता की छतरी में लाने का जिम्मा संभाला है। इन चारों क्षेत्रीय क्षत्रपों की कांग्रेस के साथ सियासी रस्साकसी चल रही है। पिछले महीने मानहानि के मुकदमे में सजा के आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के बाद सपा, टीएमसी, आप और बीआरएस संसद में विपक्षी एकता का हिस्सा बने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के यहां तब 19 पार्टियों की बैठक में संसद में हुई विपक्षी एकता को 2024 के चुनाव के लिहाज से जमीन पर उतारने की पहल शुरू करने पर सहमति बनी।

अखिलेश और ममता की नीतीश के साथ हुई मुलाकातों को विपक्षी एकता की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा की शुरूआत बताते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि बेशक भाजपा से लड़ने वाली सभी पार्टियों के लिए सबसे अहम यह है कि साथ आकर मजबूत चुनौती पेश करने का संदेश दिया जाए। इसमें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, यह सवाल अभी कहीं नहीं आता और ममता-अखिलेश समेत सभी क्षेत्रीय क्षत्रपों को मालूम है कि विपक्षी एकता की पहल आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मुद्दों में उलझने की जरूरत नहीं, जिनकी अभी प्रासंगिकता नहीं है। वैसे कांग्रेस ने रायपुर महाधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर भाजपा के खिलाफ 2024 में व्यापक विपक्षी एकता के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होने की घोषणा कर विपक्षी नेतृत्व के सवाल को खुला छोड़े रखने का संदेश पहले ही दे दिया था। कांग्रेस सूत्रों ने यह संकेत दिया कि नीतीश की इस पहल के साथ ही खरगे भी कर्नाटक चुनाव के बाद अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे और ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश से लेकर केसीआर तक से संवाद करेंगे। विपक्ष के शीर्षस्थ नेताओं की बैठक कर्नाटक चुनाव के बाद बुलाए जाने की कोशिश होगी ताकि विपक्षी एकता की पहल ठोस दिशा में आगे बढ़ाई जा सके।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए करीब 19 दलों के शीर्ष विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी दी। इन नेताओं को पहले अप्रैल के अंत तक मिलना था। सूत्रों ने कहा कि 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण बैठक में देरी हुई है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के

शिवसेना ने भी विपक्षी एकता का किया समर्थन

सावरकर मुद्दे पर नाराजगी के चलते बैठक से दूर रही शिवसेना उद्धव गुट ने भी 20वें दल के रूप में अगले दिन इसका समर्थन कर दिया था। खरगे ने इसके बाद ही नीतीश कुमार, एमके स्टालिन और उद्धव ठाकरे को फोन कर विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने की कसरत शुरू की। खरगे और राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पिछले दिनों हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कांग्रेस से असहज रिश्ते रखने वाले विपक्षी खेमे के दलों को साथ लाने की पहल को बिहार के मुख्यमंत्री आगे बढाएंगे। नीतीश ने कांग्रेस नेतृत्व से चर्चा के तत्काल बाद ही केजरीवाल से मुलाकात कर विपक्ष के एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने की रणनीति पर बातचीत की थी। केजरीवाल ने भी इस पर सकारात्मक रूख दिखाया और कांग्रेस को लेकर उनके रुख में हाल के दिनों में आई नरमी इसी ओर इशारा करती है। नीतीश से हुई चर्चाओं के बाद ममता और अखिलेश ने जिस तरह भाजपा के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत खुले तौर पर स्वीकार की उससे साफ है कि इस दिशा में कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका से दोनों को परहेज नहीं है। खास बात यह है कि इन दोनों क्षेत्रीय क्षत्रपों ने विपक्षी नेतृत्व का सवाल नहीं उठाया है। इसका संकेत साफ है कि कांग्रेस और नीतीश कुमार की संयुक्त रणनीति से विपक्ष को एकजुट करने की शुरू हुई कवायद में विपक्षी नेतृत्व की कमान के सवाल को अभी किनारे रखा जाएगा।

अगले महीने किसी समय बैठक की मेजबानी करने की संभावना है और इस संबंध में वह पहले ही कई अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर चुके हैं।

इस समय कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी में **क्षेत्रीय दलों** का वर्चस्व है। इनमें से ज्यादातर ने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन हथियाकर ही अपने को सशक्त किया है। चूंकि वे यह जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उनकी आवश्यकता अधिक है, इसलिए वे उसके समक्ष यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि उसे कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ विपक्षी नेता तो यह चाहते हैं कि कांग्रेस को 250 सीटों तक ही सीमित रहना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्षी एकता के नाम पर उसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ सकता है।

क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर अपनी शर्त इसलिए थोप रहे हैं, क्योंकि वे यह देख रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम प्रयासों के बाद भी वह करिश्मा नहीं दिखा पा रहे, जो कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस कर सके। कांग्रेस की कठिनाई यह है कि यदि वह 250 सीटों पर ही लड़ती है तो और अधिक कमजोर हो सकती है। 2014 और 2019 के आम चुनावों में वह इतनी भी सीटें नहीं जीत सकी थी कि विपक्षी दल का आधिकारिक दर्जा हासिल कर सके। यदि वह आगामी आम चुनाव में विपक्षी दलों के साथ अपने पक्ष में माहौल नहीं बना सकी तो उसके लिए 50-60 सीटों से आगे निकल पाना मुश्किल हो सकता है।

कांग्रेस भले ही यह मानकर चल रही हो कि भारत जोड़ो यात्रा ने उसके पक्ष में माहौल बनाया है, लेकिन सच यह है कि अब उस यात्रा का असर नहीं दिख रहा है। शायद इसी कारण कांग्रेस अडानी मामले को तूल दे रही है। उसे लग रहा है कि इस मुद्दे को वह आम चुनाव तक खींचकर मोदी सरकार को घेर सकती है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए सक्रिय शरद पवार ऐसा नहीं मानते। वह अडानी मामले को तूल देने के खिलाफ हैं। इसके बाद भी कांग्रेस अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने पर जोर दे रही है। पता नहीं कांग्रेस अडानी मामले को अगले आम चुनाव तक गर्म रख पाएगी या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने ऐसी ही कोशिश पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर की थी। तब उसने राफेल विमान सौदे को तूल दिया था, लेकिन इससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। जनता ने यह मानने से इनकार किया कि राफेल सौदे में कोई धांधली हुई है।

कांग्रेस की एक मुश्किल यह भी है कि जो विपक्षी दल उसका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें से कोई यह कहने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदारे होंगे। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि जो नेता विपक्षी एकता की पैरवी कर रहे हैं, वे खुद भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। कई विपक्षी नेता और खासकर ममता और केसीआर तो राहुल को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। भले ही आम आदमी पार्टी भी विपक्षी एकता के प्रयासों में शामिल हो, लेकिन इसके आसार नहीं कि वह दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस संग मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेगी। वह जिन राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है, वहां कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगा रही है। गुजरात में उसने यही किया।

विपक्षी दलों की समस्या यह है कि वह मोदी हटाओ का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस वैकल्पिक एजेंडा या न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है। चूंकि जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस को साथ लेकर विपक्ष को एक करने में जुटे हैं, उनका प्रभाव केवल उनके राज्य तक ही सीमित है, इसलिए वे अन्य राज्यों में कांग्रेस के लिए मददगार नहीं बन सकते।

विपक्षी दल जिस एक मसले पर एकजुट होते दिख रहे हैं, वह है सीबीआई और ईडी की कार्रवाई। इसे लेकर वे धरना-प्रदर्शन करने के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। विपक्षी दल सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर चाहे जितनी आपत्ति जताएं, वे यह नहीं कह सकते कि राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है। वे इस तथ्य को ओझल नहीं कर सकते कि जो नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उन्हें अदालतों से राहत नहीं मिल रही है। इनमें आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी हैं। तृणमूल कांग्रेस के भी कई नेता ऐसे हैं, जिन्हें अदालत से राहत नहीं मिल रही है। कुछ नेता तो लंबे समय से जेल में हैं। कई नेता ऐसे हैं, जिनके खिलाफ ऐसे प्रमाण मिले हैं, जो यह बताते हैं कि घपले-घोटाले में उनकी भागीदारी रही है। चूंकि प्रधानमंत्री यह समझ रहे हैं कि देश की जनता नेताओं के भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है, इसलिए वह विपक्षी नेताओं की शिकायत की परवाह न करते हुए बार-बार यह कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई ढिलाई न बरतें। कांग्रेस सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर कितना ही शोर मचाए, भाजपा बेपरवाह दिख रही है। हाल में उसने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का कच्चा-चिट्ठा सामने रखते हुए जनता को यह याद दिलाया कि उसके समय में किस तरह बड़े-बड़े घोटाले हुए।

● **इन्द्र कुमार**

विपक्षी एकता की हवा निकालते पवार

कभी अपने साथियों को तो कभी अपने विरोधियों को चौंकाना शरद पवार की फितरत है। अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के जिस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उसकी एक तरह से शरद पवार ने हवा निकाल दी। उन्होंने अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी नियुक्त करने की विपक्षी दलों की मांग को एक तरह से खारिज कर दिया। चूंकि इस मांग को लेकर जारी संसदीय गतिरोध में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) भी शामिल रही, इसीलिए उनका यह बयान चौंकाने वाला है। सवाल है कि क्या शरद पवार ने इसके जरिए 2024 के आम चुनाव में संयुक्त विपक्ष की अपने-आप अगुवाई करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस और राहुल गांधी को कोई संकेत दिया है या फिर वह आगामी आम चुनाव के लिए नए गठबंधन बनाने की तैयारी में हैं? क्या शरद पवार इस बयान के जरिए विपक्षी दलों को भी नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? यह संयोग नहीं है कि जिस समय शरद पवार ने अडानी मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी की मांग खारिज की, ठीक उसी वक्त उनके भतीजे अजित पवार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का गुणगान किया। आज के दौर में राजनीति यदि किसी की प्रशंसा भी करती है तो उसके राजनीतिक संकेत होते हैं। अजित पवार द्वारा मोदी की प्रशंसा करने का एक संकेत यही है कि पवार परिवार भाजपा के साथ राजनीति की कोई नई राह देख रहा है।

चुनावी साल में नक्सली आक्रामक

छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी वर्ष का इतिहास रक्तरंजित रहा है। 26 अप्रैल को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों के वाहन को निशाना बनाकर आईईडी धमाका किया, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। मार्च से लेकर मई तक गर्मियों के मौसम में जंगल में दृश्यता बढ़ जाती है और नक्सली टीसीओसी चलाकर बड़े हमले करते हैं। बीजापुर जिले के गंगालूर में जयभारत सत्याग्रह अभियान में नुक्कड़ सभा से लौटते समय नक्सलियों ने बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के काफिले की वाहन को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस समय नक्सली निशाने पर राजनीतिक दल के नेता हैं। इस हमले के कुछ देर पहले ही बीजापुर विधायक की गाड़ी वहां से निकली थी, पर काफिले में पीछे आ रही नेलसनार जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप की वाहन के पहिए पर गोली लगी। समय के कुछ अंतराल से बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारों का कहना है कि चुनाव आते ही नक्सली आक्रामक हो जाते हैं। 2022 में नक्सली कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे, लेकिन 2023 में नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर-समेली के बीच हुआ। सूत्रों के मुताबिक यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी दौरान नक्सलियों ने वाहन पर बम भी फेंका। नक्सली हमले में शहीद होने वालों में प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, मुन्ना राम कड़ती, संतोष तामो, नव आरक्षक दुल्गो मंडावी, लखमू मरकाम, नव आरक्षक जोगा कवासी, नव आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम करटम, जयराम पोड़ियाम जगदीश कवासी और गाड़ी के ड्राइवर धनीराम यादव शामिल हैं। राज्य में यह पहली बार नहीं है, जब नक्सलियों ने राजनीतिक दल के नेताओं पर हमले किए हैं। 25 मई 2013 को चुनाव के कुछ माह पहले कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर झीरम घाटी में हुए हमले में कांग्रेस की पूरी पीढ़ी ही लगभग खत्म हो गई। नंदकुमार पटेल, उदय मुदलियार, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा सहित 31 लोग इस हमले में मारे गए थे।

बस्तर में नक्सलियों का टीसीओसी (टैक्टिकल काउंटर अफेंसिव कैंपेन) चल रहा है। नक्सली इस दौरान अक्सर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। टीसीओसी को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। बस्तर के सभी जिलों में जवानों को सर्चिंग के लिए भेजा जा रहा है। 5 दिन पहले सुकमा जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया था। भारी मात्रा में विस्फोटक समेत नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि इस कैंप में करीब 25 से 30 की संख्या में नक्सली मौजूद थे। जवानों के आने की खबर मिलते ही सभी नक्सली भाग गए। नक्सलियों का डिविजनल कमेटी मेंबर जगदीश पिछले 4 दिन से ककाड़ी, नहाड़ी, गोंडेरास के जंगलों में माओवादियों की बैठक ले रहा था। जगदीश के साथ करीब 30 से 35 की संख्या में कई हथियारबंद माओवादी भी मौजूद थे। जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रणनीति बना रहे थे। दंतेवाड़ा पुलिस के अफसर बड़े अधिकारियों से जवानों को ऑपरेशन पर भेजने की इजाजत मांग रहे थे। हालांकि, मंजूरी मिलने में 2 दिन का वक्त लग गया था। फिर जवानों को ऑपरेशन पर भेजने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। जिसके बाद 25 अप्रैल को दंतेवाड़ा डीआरजी की पूरी 6 टीमों को नक्सल ऑपरेशन पर भेजा गया था। इसमें करीब 300 से ज्यादा जवान शामिल थे। 25 अप्रैल की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच जवानों को बड़ी गाड़ियों से अलग-अलग लोकेशन में ड्रॉप किया गया था, ताकि चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा जा सके। इनमें डीआरजी की प्लाटून नंबर 1 को अरनपुर के जंगल में छोड़ा गया था। यहीं से जवान नक्सली कमांडर जगदीश को घेरने के लिए रात में ही जंगल में घुसे थे। जवानों को बड़ी गाड़ी के जरिए जंगल में छोड़े जाने की खबर नक्सलियों को मिल गई थी। नक्सली पहले से ही अलर्ट थे। जैसे ही जवान 26 अप्रैल की सुबह नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे तो दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी। हालांकि, नक्सली कमांडर जगदीश को पुलिस घेर नहीं पाई और वह भाग निकला। अफसरों के निर्देश के बाद सभी जवान जंगल से जिला मुख्यालय लौटने निकल गए थे। इनमें डीआरजी की प्लाटून नंबर 1 अरनपुर पहुंची। जवानों को लेने कई गाड़ियां गई हैं, यह खबर नक्सलियों को मिल गई थी। नक्सलियों को मालूम था कि जवान बड़ी गाड़ी से आए हैं, तो जाएंगे भी उसी में, इसलिए जवानों से भरी गाड़ी को निशाना बनाने की रणनीति बनाई गई। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम को वारदात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

सूत्रों के मुताबिक, नक्सलियों ने अरनपुर-समेली कैंप के बीच जब सड़क निर्माण का काम चल रहा था, उसी समय कमांड आईईडी प्लांट कर रखी हुई थी। सड़क से करीब 70 से 80 मीटर लंबा तार जंगल की तरफ बिछा रखा था। ऐसा बताया जा रहा है, जवानों से भरी एक गाड़ी पहले उसी इलाके से गुजर गई। हालांकि, नक्सली उसे निशाना नहीं बना सके। कुछ देर बाद माओवादियों ने दूसरी गाड़ी को अपना निशाना बनाया। इस गाड़ी में 10 जवान सवार थे। यह गाड़ी किसी सिविलियन की थी, जो बुकिंग के तौर पर जवानों को लेने गई हुई थी। दोपहर करीब 1.30 से 2 बजे के बीच जैसे ही गाड़ी आईईडी के ऊपर आई वैसे ही नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया। गाड़ी में सवार 10 जवान और एक वाहन चालक के शरीर के चिथड़े उड़ गए। करीब 60 से 70 मीटर दूर तक गाड़ी के पार्ट्स और जवानों के शरीर के अंग बिखर गए। सड़क पर करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया।

● रायपुर से टीपी सिंह

सिलसिलेवार तरीके से तीन भाजपा नेताओं की हत्या

इसी वर्ष फरवरी माह में नक्सलियों ने सिलसिलेवार तरीके से तीन भाजपा नेताओं की हत्या की थी। 5 फरवरी को बीजापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम, 10 फरवरी को नारायणपुर भाजपा उपाध्यक्ष सागर साहू और 11 फरवरी को इंद्रावती नदी के पार दंतेवाड़ा-नारायणपुर जिले की सरहद पर भाजपा नेता रामधर अलामी की हत्या की गई। इन हमलों के बाद भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बस्तर में परिस्थितियां बदली हुई हैं। आईजीपी बस्तर सुंदरराज पी ने बताया कि इस तरह के हमले को रोकने सुरक्षा बल को अतिरिक्त सुरक्षा बरतने निर्देशित किया है। इसके लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया गया है। सुरक्षा बल लगातार क्षेत्र की सर्चिंग कर नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आईईडी विस्फोटक बरामद कर प्रायोजित हमले को नाकाम कर रहे हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। आने वाले दिनों में नक्सल विरोधी अभियान को और भी तेज किया जाएगा।

एमवीए में रार!

लोकसभा चुनाव 2024 में भी महाविकास अघाड़ी एकजुट रहेगा, यह कहना अभी मुश्किल लग रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में महज कुछ साल पहले बने इस गठबंधन में दरारें नजर आने लगी हैं। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के नेता बेरोक-टोक बयान बाजी कर रहे हैं। अब खबरें हैं कि भाजपा भी इस दरार का फायदा उठाने के लिए तैयार हो गई है। भाजपा के नेता लगातार राज्य में महाविकास अघाड़ी के बीच चल रही रस्साकशी पर सवाल उठा रहे हैं। उधर, एकनाथ शिंदे सरकार को अस्तित्व में आए अभी एक साल भी नहीं हुआ है, और इसके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एक ओर जहां सबकी नजर शिंदे सरकार के भविष्य पर टिकी है तो वहीं महाविकास अघाड़ी में टूट को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। टूट की बात इसलिए भी अहम हो गई है, क्योंकि एक दिन पहले ही एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने कहा कि आज हम अघाड़ी में हैं। आगे अघाड़ी रहेगी या नहीं, इस पर बोलना ठीक नहीं है। राज्य में इस समय शिवसेना-भाजपा की सरकार है। ये शिवसेना उद्धव वाली नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे वाली है। 30 अप्रैल को 10 महीने इस सरकार के पूरे हो रहे हैं। लेकिन, अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच चीजें उतनी तेजी से नहीं चल रही हैं, जैसा कि पार्टी नेता सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाते हैं। हालांकि, भाजपा अभी साइलेंट मोड में है।

वहीं, इस गठबंधन में एक और बाधा सामने आ रही है। वह बाधा सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका है। इस याचिका में उद्धव ने शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस पर कोर्ट 5 मई को अपना फैसला सुना दे सकता है। उप्र के बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक 48 लोकसभा सीटें हैं। वहीं, यहां पर 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है। यह राज्य का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल के दिनों में कई परिदृश्य उभरकर सामने आए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की याचिका को नकार देता है, तो एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की कुर्सी बच जाएगी। वह अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस स्थिति में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगला विधानसभा चुनाव भी शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की याचिका के समर्थन में अपना फैसला सुना देता है तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि, ऐसी कम संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट शिंदे और अन्य 15 विधायकों को अयोग्य करार देगा।

मान लें कि सुप्रीम कोर्ट शिंदे को पद छोड़ने का आदेश जारी भी कर देता है, फिर भी सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत में ही रहेगा। क्योंकि इनके समर्थन में 165 विधायक हैं, यह आंकड़ा साधारण बहुमत के लिए आवश्यक से 20 अधिक है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। हालांकि, इस स्थिति में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकते हैं। वहीं, शिंदे के किसी खास को उपमुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। ऐसा हो कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार सत्तारूढ़ शिवसेना-भाजपा गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, ऐसे में शिंदे के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर एक असहज करने वाली स्थिति बन सकती है। शरद पवार एनसीपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। उनका महाराष्ट्र की राजनीति में गहरा प्रभाव भी है। देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर शिंदे की दावेदारी थोड़ी कमजोर हो जाएगी।

अगर एमवीए 2024 के आम चुनावों तक बरकरार रहता है तो ये भाजपा के लिए संकट बन सकता है। पार्टी के इंटरनल सर्वे ने ऐसे संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। 10 सीटें जीतने के लिए भी भाजपा नेताओं को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी भी अटकलें हैं कि कांग्रेस एमवीए से बाहर हो सकती है। एनसीपी और शिवसेना का उद्धव गुट फिर साथ होकर चुनाव लड़ सकता है। इस स्थिति में आगामी चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को मिलेगा।

महाराष्ट्र की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले मानते हैं कि वहां पर्दे के पीछे काफी कुछ घटित हो रहा है। अब इस बीच एक नया घटनाक्रम घटित हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के धाराशिव में अजित पवार को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर-बैनर जगह-जगह लगे हैं। धाराशिव में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर उनके उस बयान के बाद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। दरअसल मीडिया से बातचीत में अजित पवार से सवाल किया गया कि क्या एनसीपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश करेगी? इस पर पवार ने कहा कि 2024 क्यों, हम अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा करने को तैयार हैं। अजित पवार ने ये भी कहा कि वह 100 फीसदी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। अजित पवार ने अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर चल रही अफवाहों के बीच एक बार फिर एनसीपी में ही रहने की बात दोहराई है। गत दिनों उन्होंने दोहराया कि वह अपने अंतिम क्षण तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में बने रहेंगे। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी के एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कई तरह की अटकलें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन किसी भी अफवाह का शिकार हुए बिना मैं अपना काम जारी रख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं अपने अंतिम समय तक एनसीपी में काम करता रहूंगा।

● **बिन्दु माथुर**

भाजपा के साथ जाने की थी अटकलें

बीते दिनों अजित पवार के भाजपा के साथ जाने की भी अटकलें चल रहीं थी। ये अटकलें इतनी ज्यादा थीं कि शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी इस पर सफाई देनी पड़ी थी। एनसीपी के कुछ विधायक भी खुलकर अजित पवार के समर्थन में खड़े दिखे। हालांकि बाद में अजित पवार ने ही इन अटकलों को खारिज कर दिया था। अजित पवार ने कहा था कि जब तक जान में जान है, तब तक वे एनसीपी से जुड़े रहेंगे। इससे पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने से पहले अजित पवार ने नाटकीय तौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। हालांकि गाहे-बगाहे अजित पवार के भाजपा के साथ जाने की खबरें राजनीतिक गलियारों में आती रहती हैं।

गुटबाजी पड़ न जाए भारी

राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने में सिर्फ सात महीने का समय रह गया है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत बनाकर चुनावी व्यूह रचना बनाने में लग गए हैं। जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि उनकी लोक हितकारी योजनाओं से इस बार के चुनाव में हर बार सत्ता बदलने का रिवाज बदल जाएगा। वहीं भाजपा सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं का मानना है कि प्रदेश की जनता गहलोत सरकार को हटाकर राज बदलने को तैयार बैठी है। वोट पड़ेंगे तब राज बदल जाएगा।

कांग्रेस की चुनावी कमान पूरी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाल रखी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी संगठन के काम में लगे हैं। उन्हें अध्यक्ष बने तीन साल होने वाले हैं। ऐसे में चर्चा चल रही है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसी अन्य नेता को नियुक्त किया जा सकता है। यदि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा प्रयास रहेगा कि उनके समर्थक महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, नरेंद्र बुडानिया, लालचंद कटारिया, रघु शर्मा में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। ताकि चुनाव में उनके मन मुताबिक टिकटों का वितरण हो सके। कांग्रेस के 400 में से 367 ब्लॉक अध्यक्षों की तो नियुक्तियां हो चुकी है। मगर अधिकांश जिला अध्यक्षों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इस कारण नीचे के स्तर पर संगठन पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में 3 विधायकों अमित चाचान, इंद्राज सिंह गुर्जर, प्रशांत बैरवा सहित कुल 8 लोगों को पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया है। वहीं सात लोगों को मीडिया पैनलिस्ट और तीन लोगों को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।

कांग्रेस में 25 सितंबर 2022 की घटना में दोषी नेताओं पर अभी तक कार्यवाही नहीं होने से भी सचिन पायलट खासे नाराज बताए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने जयपुर में एक दिन का उपवास रखकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर मिलीभगत का खेल खेलने का आरोप लगाया है। पायलट के अनशन को रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने बहुत दबाव बनाया था मगर पायलट अनशन करके ही माने। हालांकि कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि घोषित कर दिया था। मगर पायलट के खिलाफ अभी तक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई है। अंदरखाने पायलट को हनुमान बेनीवाल सहित आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस आलाकमान को पता है कि यदि पायलट के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे तो राजस्थान की स्थिति भी पंजाब की तरह हो सकती है।

कुल मिलाकर चुनावी दौर में कांग्रेस पार्टी आपसी गुटबाजी की शिकार हो गई है जिसका खामियाजा उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। राजस्थान में सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कोटा के नवीन पालीवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। आप ने विधानसभा चुनाव का प्रभारी राज्यसभा सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉ. संदीप पाठक को पहले ही नियुक्त कर रखा है। दिल्ली के द्वारका से विधायक विनय मिश्रा को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और गुजरात के 7 विधायकों अमनदीप सिंह गोल्डी, नरेश यादव, चेतर वसावा, नरेंद्र पाल सिंह सवाना, हेमंत खावा, शिवचरण गोयल और मुकेश अहलावत को सह प्रभारी बनाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जयपुर में रोड शो करके एक जनसभा को भी संबोधित कर चुके हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे रामपाल जाट को 628 वोट ही मिल पाए थे। यही हाल अन्य प्रत्याशियों का रहा था। 2018 के चुनाव में आप को प्रदेश में 0.38 प्रतिशत वोट मिले थे। हालांकि अब पार्टी के नेता प्रदेश में अगली सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 1.22 प्रतिशत यानी 1 लाख 77 हजार 699 वोट अधिक प्राप्त कर 79 सीट अधिक जीत ली थी। वहीं इतने वोटों के अंतर पर भाजपा की 90 सीटें कम हो गई थीं। जिससे भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। अपनी पिछले विधानसभा चुनावों की कमी को दूर करने के लिए भाजपा अभी से जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रदेश की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण समाज के चंद्रप्रकाश जोशी (सीपी जोशी) को नियुक्त किया गया है। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से दूसरी बार लोकसभा सदस्य हैं। जयपुर में कुछ दिनों पूर्व ही ब्राह्मण समाज ने लाखों लागों को एकत्रित कर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया था। जिसमें ब्राह्मण समाज ने प्रदेश की सभी पार्टियों से उनके समाज को सत्ता में अधिक भागीदारी देने की मांग की थी। उस सम्मेलन के कुछ दिनों बाद ही भाजपा ने सीपी जोशी की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी कर दी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

जातिगत संतुलन बनाने की चुनौती

भाजपा ने राजपूत समाज के सातवीं बार विधायक बने राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। जबकि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए डॉ. सतीश पूनिया को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर जाट समाज को भी साधने का काम किया है। सतीश पूनिया पहली बार आमेर से विधायक बने हैं। इसलिए उन्हें उपनेता का पद ही मिल पाया है। चर्चा है कि मीणा समाज के राज्यसभा सदस्य डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। राजपूत समाज के गजेंद्र सिंह शेखावत, यादव (अहीर) समाज के डॉ. भूपेंद्र यादव, ब्राह्मण समाज के अश्विनी वैष्णव केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जाट समाज के कैलाश चौधरी, अनुसूचित जाति के अर्जुनराम मेघवाल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। बनिया समाज के ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं।

योगी की 80:20 की राजनीति

जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाने में भले ही कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ आ गई है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में उप्र में राजनीति के मंडल ब्रांड की वापसी की संभावना नहीं है। क्षेत्रीय दलों, अर्थात् समाजवादी पार्टी, जो उप्र में मुख्य विपक्षी दल हैं, को यह आभास हो गया है कि 2024 में भाजपा को सेंध लगाना लगभग असंभव कार्य होगा, क्योंकि तब तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा और भाजपा का हिंदू कार्ड पहले की भांति मजबूत बना रहेगा। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही 2024 के चुनावी मुद्दों पर एक नजर डाल दी है, जब उन्होंने कहा कि चुनाव 80 बनाम 20 होगा। 80 हिंदू और 20 अल्पसंख्यक होंगे। समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना कार्ड के अंकगणित को 85 बनाम 15 में बदलने के लिए उठाया। 85 ओबीसी और दलित हैं और 15 उच्च जातियां हैं।

भाजपा ने महसूस किया कि इस तरह की कोई भी कवायद जाति आधारित सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं को भड़काएगी और हिंदुत्व-राष्ट्रवादी परियोजना को नुकसान पहुंचाएगी। गौरतलब है कि जाति हमेशा भारतीय लोकतंत्र का एक आंतरिक घटक रही है। जैसा कि भाजपा के एक अनुभवी पदाधिकारी कहते हैं, किसी की जाति राजनीतिक शक्ति, भूमि, और पुलिस या न्यायिक सहायता तक पहुंच को नियंत्रित कर सकती है। जातियां कुछ क्षेत्रों में स्थानीय होने के कारण स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित करती हैं। जातिगत जनगणना कुछ लोगों में जाति की भावनाओं को बढ़ा सकती है। इससे झड़पें हो सकती हैं, खासकर उन गांवों में जहां गुमनामी बनाए रखना मुश्किल है। तब राजनीतिक दल विशिष्ट जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे और नीति-निर्माण की समावेशिता खो जाएगी।

समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना में ओबीसी की गणना से विभिन्न राज्यों में उनकी संख्या के बारे में ठोस आंकड़े उपलब्ध होंगे। इन नंबरों का उपयोग विभिन्न राज्य संस्थानों में ओबीसी की हिस्सेदारी की जांच के लिए किया जाएगा। एक सपा नेता ने कहा, यह स्पष्ट है कि सत्ता के अधिकांश क्षेत्र, जैसे कि न्यायपालिका, शैक्षणिक संस्थान और मीडिया, सामाजिक अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित और एकाधिकार हैं, दलित-बहुजन समूहों को केवल एक मामूली उपस्थिति देते हैं। एक जाति जनगणना यह दिखाएगा कि विभिन्न संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार है या नहीं है। इस तरह के एक अनिश्चित सामाजिक तथ्य की स्वीकृति के साथ, सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच एक नई राजनीतिक चेतना उभरेगी। जो उन्हें सामाजिक न्याय के लिए एक नया आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर करेगी।

दिलचस्प बात यह है कि उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जातिगत जनगणना की विपक्ष की मांग का समर्थन कर पिछड़ी राजनीति को हवा दी। मौर्य ने कहा, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। उन्होंने कहा, न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इस विषय पर बंटी हैं। हालांकि, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उप्र ने अभी तक बिहार के उदाहरण का अनुसरण क्यों नहीं किया है, जहां जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है। इसकी योजना क्षेत्रीय दलों की इच्छा के अनुसार सामने आ रही थी, लेकिन अब सांप्रदायिक कार्ड ने इसे पीछे धकेल दिया है। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या और उसके बेटे असद की मुठभेड़ में हुई मौत ने उप्र में माहौल को सांप्रदायिक आधार पर अत्यधिक प्रभावित कर दिया है। भाजपा माफिया के अंत को न्यायोचित ठहराकर बदले की भावना से हिंदू कार्ड खेल रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां अपने रुख को लेकर असमंजस में हैं। उन्होंने अब तक केवल मुठभेड़ों को फर्जी करार दिया है। जाहिर तौर पर क्षेत्रीय पार्टियां हिंदू समर्थन से हाथ धोना नहीं चाहतीं। जातिगत जनगणना का मुद्दा अब उप्र में एक और समय, एक और मौसम की प्रतीक्षा कर सकता है।

विपक्ष की जात राजनीति का जवाब भाजपा ज्यादा बड़ी जात राजनीति से देगी या उसका जवाब ज्यादा उग्र और आक्रामक हिंदुत्व से दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब से आगे की राजनीति की दिशा, दशा और केंद्रीय चेहरे तय होंगे। विपक्ष ने जाति को अपना हथियार बनाया है। उनका मुद्दा सामाजिक न्याय है। बिहार से शुरू हुई मंडल दो की राजनीति पूरे देश में फैलेगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उस रास्ते पर चल पड़े हैं। उनका मानना है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना जरूरी है ताकि हर जाति को उसकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जा सके। आबादी के हिसाब से उसे देश के संसाधनों में हिस्सेदारी दी जाए। अगर सरकारी नौकरियां नहीं हैं या सरकारी स्कूल-कॉलेज पढ़ने लायक नहीं हैं तो निजी कंपनियों में भी आरक्षण लागू हो और निजी क्षेत्र के स्कूल-कॉलेजों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो। यही विपक्ष की अगले चरण की राजनीति का मुख्य मुद्दा बनने वाला है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

जाति की सीमा मिटाने वाला नैरेटिव तैयार करना होगा

जात राजनीति की काट में भाजपा जाति की राजनीति करके कामयाब नहीं हो सकती है। उसे ज्यादा उग्र हिंदुत्व की राजनीति करनी होगी। जाति की सीमा मिटाने वाला नैरेटिव तैयार करना होगा। और वह नैरेटिव तैयार होगा योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके काम से। प्रधानमंत्री मोदी हिंदू सम्राट हैं लेकिन उनकी छवि एक बड़े राजनेता और विकास पुरुष की भी बनाई गई है। गुजरात दंगों के बाद जो छवि थी वह काफी हद तक बदल गई है, जबकि योगी आदित्यनाथ की वैसी छवि बन रही है, जैसी 2002 के बाद मोदी की बनी थी। योगी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बन रहे हैं। मीडिया में उनका जिस तरह से महिमामंडन हो रहा है वह अपनी जगह है लेकिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद सोशल मीडिया में जो माहौल बना वह अभूतपूर्व है। सामान्य लोगों ने, महिलाओं और युवाओं ने और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीरें बदलीं और मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए योगी की तस्वीर लगाई।

महागठबंधन में रार... ?

डीएम जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी रहे आनंद मोहन की रिहाई के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक बार फिर नए मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई से वह विपक्षी दलों के निशाने पर तो हैं ही, साथ ही जिस महागठबंधन के सहारे वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, उसमें भी यह मामला विवादित हुआ जा रहा है। ताजा मामला भाकपा माले से जुड़ा हुआ है, जिसने 6 टाडा बंदियों को रिहा किए जाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है।

राज्य सरकार ने इसी साल 10 अप्रैल को जेल नियमावली में एक संशोधन किया और उस खंड को हटा दिया, जिसमें अच्छा व्यवहार होने के बावजूद सरकारी अफसरों के कातिलों को रिहाई देने पर रोक थी। राज्य गृह विभाग ने बिहार जेल नियमावली, 2012 के नियम 481 (1)ए में संशोधन की जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी करके दी थी। आरोप है कि राज्य **सरकार ने ये बदलाव किया** ही इसलिए है ताकि कुख्यात आनंद मोहन की रिहाई हो सके। क्योंकि इससे पहले तक सरकारी अफसरों के कत्ल के दोषियों को रिहा नहीं किया जा सकता था।

इस मामले के सामने आने के बाद से ही भाकपा माले ने 6 टाडा बंदियों की रिहाई की मांग तेज कर दी है। हालांकि भाकपा माले की ये मांग काफी पुरानी है। बात सिर्फ, आनंद मोहन की नहीं है, इस संशोधन से डीएम के कत्ल के दोषी मोहन के अलावा 26 और बंदियों को रिहा किया गया है। दोषियों की रिहाई की ये बड़ी संख्या ही मुख्यमंत्री नीतीश के गले की फांस बन सकती है, क्योंकि विरोधियों को तो वह चुप कराने के लिए कोई पैंतरा इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन क्या अपने ही सहयोगी दल का मुंह बंद रखने के लिए उनकी मांग मानी जाएगी? अगर ऐसा होता है तो निकट भविष्य में 6 टाडा बंदियों की रिहाई की भी खबरें सुर्खियां बन सकती हैं, लेकिन ये सब आनंद मोहन की रिहाई की आड़ में ही किया जाएगा।

गिरिराज सिंह ने इस रिहाई पर तंज कसते हुए आनंद मोहन को बेचारा कह दिया। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन बेचारे काफी समय तक जेल में रहे, वह तो बलि के बकरे बन गए थे, आनंद मोहन की रिहाई हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया है वह समाज पूछ रहा है। उसे समाज कभी नहीं माफ करेगा। विपक्षी एकता मुहिम पर निकले नीतीश कुमार को गिरिराज सिंह ने कहा, मुंगेरीलाल के हसीन सपने को देखने के लिए किसी को मना ही नहीं है। यहां साफ जाहिर हो रहा है कि गिरिराज सिंह भी सीधे आनंद मोहन की रिहाई पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो अन्य लोगों को छोड़ा गया है, उस पर सवाल उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं।

वहीं, आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद वह अपना राजनीतिक कैरियर नए सिरे से शुरू करेंगे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए हैं। हालांकि अभी यह नहीं बताया कि जेल से निकलने के बाद किस पार्टी में शामिल होंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा भी आपकी रिहाई की मांग करती रही है, तो ऐसे में किस पार्टी से राजनीतिक कैरियर का पार्ट-2 शुरू करेंगे। इस पर आनंद मोहन ने कहा कि बेटे की शादी के बाद फिर से जेल जाना है। फिर जब रिहाई पर ठप्पा लगेगा, तो लोगों को बुलाकर तय करेंगे कि क्या करना है। आनंद मोहन ने कहा कि मैं मरा नहीं हूं, जेल में ही था इसलिए राजनीतिक सफर का अंत नहीं हुआ है।

आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन की राजनीति में एंट्री 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दौरान हुई थी। आनंद मोहन राजनीति में महज 17 साल की उम्र में आ गए थे। जिसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। इमरजेंसी के दौरान पहली बार 2 साल जेल में रहे। आनंद मोहन का नाम उन नेताओं में शामिल है जिनकी बिहार की राजनीति में 1990 के दशक में तूती बोला करती थी। जेपी आंदोलन के जरिए ही आनंद मोहन बिहार की सियासत में आए और 1990 में सहरसा जिले की महिषी सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते। तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। सवर्णों के हक के लिए उन्होंने 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी बना ली। लालू यादव का विरोध कर ही आनंद मोहन राजनीति में निखरे थे।

बिहार की राजनीति में जब भी कद्दावर और दमखम रखने वाले बाहुबली नेताओं की बात की जाती है आनंद मोहन सिंह का नाम लोग जरूर लेते हैं। बिहार की राजनीति जब से शुरू हुई, तबसे जाति के नाम पर चुनाव हुए और लड़े गए। एक दौर बिहार की राजनीति में 90 के दशक में आया जब ऐसा सामाजिक ताना-बाना बुना गया था कि जात की लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी और अपनी-अपनी जातियों के लिए राजनेता भी खुलकर बोलते दिखते थे। चुनाव के समय जात के नाम पर आए दिन मर्डर की खबरें आती थीं। उस वक्त लालू यादव का दौर चल रहा था। उस दौर में आनंद मोहन लालू के घोर विरोधी के रूप में उभरे। 90 के दशक में आनंद मोहन की तूती बोलती थी। उन पर हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, दबंगई समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वे पिछले 15 वर्षों से बिहार की सहरसा जेल में सजा काट रहे थे। वह उन 27 कैदियों में शामिल थे, जिन्हें जेल नियमों में संशोधन के बाद बिहार की जेल से रिहा किया गया। नियमों में बदलाव और आनंद मोहन सिंह की रिहाई से राजनीतिक गलियारे में बवाल मचा हुआ है।

● **विनोद बक्सरी**

क्यों उठाया जा रहा 6 टाडा बंदियों की रिहाई का मुद्दा?

भाकपा माले, पहले से ही टाडा बंदियों की रिहाई की मांग का झंडा बुलंद किए हुए है। इसके लिए कई बार अनशन आदि भी हो चुके हैं। माले ने नीतीश सरकार से पूछा है कि अरवल को भदासी कांड के टाडाबंदियों की रिहाई पर सरकार चुप क्यों है? माले ने आरोप लगाया कि 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके बंदियों की रिहाई के मामले में सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण है। इसलिए यह मांग की गई है कि टाडा के तहत गलत तरीके से फंसाए गए भदासी कांड के शेष बचे बंदियों को भी जल्द रिहा किया जाए। दल का कहना है कि शेष बचे 6 टाडा बंदी दलित-अतिपिछड़े-पिछड़े समुदाय के हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं और सभी के सभी बूढ़े हो चुके हैं। पार्टी का कहना है कि सभी ने कुल मिलाकर 22 साल की सजा काट ली है। इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।

युआन बनेगा डॉलर का विकल्प?

आर्थिक प्रतिबंध लगाना असंभव हो जाएगा

युआन अंतरराष्ट्रीय साख वाली उन मुद्राओं में भी शामिल है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिजर्व संपत्ति रखी जाती है। युआन के व्यापार की मुद्रा बनने से चीन को असली लाभ यह होगा कि उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना लगभग असंभव हो जाएगा। यानी भविष्य में यदि चीन ने ताइवान पर हमला करने या भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की तो परमाणु और वीटो शक्ति होने के कारण उस पर न कूटनीति चलेगी, न सैन्य शक्ति और न ही आर्थिक प्रतिबंध कारगर होंगे। गनीमत है कि युआन को डॉलर और यूरो जैसी साख हासिल करने में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज तक चीन जैसी किसी अपारदर्शी, कड़े पूंजी नियंत्रण वाली तानाशाही अर्थव्यवस्था की मुद्रा की साख डॉलर और यूरो जैसी नहीं बन पाई है। चीन में बड़े-बड़े पूंजीपति और उनकी पूंजी रातोंरात गायब हो जाना आम बात है, जिसके चलते युआन का डॉलर का विकल्प बनना अभी तो संभव नहीं लगता, लेकिन यदि संभव हो जाता है तो वह भारत के हित में नहीं होगा।

कूटनीति में जितना महत्व बात का होता है, उतना ही उस स्थान और प्रसंग का भी, जहां वह कही जाती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हालिया चीन यात्रा से लौटते समय यूरोपीय अखबारों को दिए इंटरव्यू में कहा, 'यूरोप को स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या ताइवान के संकट का गहराना हमारे हित में है? नहीं। सबसे बुरा यह सोचना होगा कि हम यूरोप वाले इस मुद्दे पर पिछलग्गू बन जाएं और अमेरिका के एजेंडे और चीन की अनावश्यक प्रतिक्रिया के इशारों पर चलें।'

सैद्धांतिक रूप से देखें तो मैक्रों ने कुछ गलत नहीं कहा। भारत भी सदैव गुटनिरपेक्षता की राह का अनुगामी रहा है। हाल के वर्षों में चीन, रूस और अब खाड़ी के देश भी बहुध्रुवीय दुनिया की बात करने लगे हैं। फ्रांस लंबे समय से यूरोप की एक स्वायत्त विदेश नीति की बात करता रहा है। पिछली सदी के सातवें दशक में शीतयुद्ध के दौरान शार्ल डेगाल ने अमेरिकी खेमे की परवाह न करते हुए माओ के चीन को मान्यता दे दी थी।

हालांकि, शी जिनपिंग का चीन माओ का चीन नहीं है। वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। उसे वह संहारक शस्त्रों से लैस कर शक्तिशाली बनाने और चारों तरफ पांव पसारने की योजनाओं में लगा है। उसने भारत से अक्साई चिन पठार छीन रखा है और पाकिस्तान से कराकोरम पट्टी ले रखी है, जिस पर कराकोरम हाईवे बना लिया है। अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत बताकर उस पर अपना हक जताता रहता है। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक सीमा के अतिक्रमण और असैन्य बफर क्षेत्र को हड़पने की ताक में रहता है। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित म्यांमार के कोको द्वीप पर चीन का टोही अड्डा बनने की भी खबरें हैं। संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण के फैसले को ताक पर रखते हुए उसने दक्षिण चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह को फिलीपींस और वियतनाम से छीनकर वहां अपने अड्डे बना लिए हैं। पिछले 75 वर्षों से उसने ताइवान की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को रोक रखा है और उसे अपना प्रांत बताकर हड़पने को बेताब है।

ऐसी घड़ी में जब ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग-वेन और अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर केविन मकार्थी की भेंट से नाराज होकर चीन ताइवान की समुद्री नाकेबंदी का युद्धाभ्यास कर रहा था, तब मैक्रों का यह कहना कि 'ऐसे संकटों में उलझना, जो हमारे नहीं हैं, यूरोप के लिए फंदे में फंसने जैसा होगा,' उनके ही मित्र देशों को कतई रास नहीं आया। पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविएत्स्की ने चुटकी लेते हुए कहा, 'कुछ पश्चिमी नेता हर किसी के साथ सहयोग के सपने देखते हैं, रूस हो या सुदूरपूर्व की ताकतें! जबकि हकीकत यह है कि यूरोपीय सुरक्षा की असली आधारशिला उसका अमेरिका के साथ गठबंधन है।'

यह भी एक तथ्य है कि तानाशाहों के इरादे बदलने के लिए उनकी मांगें मान लेने की गलती करते हुए यूरोप के नेताओं को 95 साल बीत चुके हैं। 1938 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैंबरलिन ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के जर्मन आबादी वाले इलाके देकर उसके इरादे बदलने की कोशिश की। हाल में जार्जिया और यूक्रेन के प्रांतों पर रूसी कब्जे के बाद यूरोपीय देशों ने 2008 और 2015 के शांति समझौतों से पुतिन के इरादे बदलने के प्रयास किए। अब मैक्रों अपनी सामरिक स्वायत्तता के जरिए जिनपिंग को संकेत देना चाहते हैं कि ताइवान के संकट को वह यूरोप का संकट नहीं मानते और इसमें वे अमेरिका के साथ नहीं हैं। उन्हें लगता है कि शायद इससे आश्वस्त होकर जिनपिंग पुतिन पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे और ताइवान को घेरना बंद कर देंगे। वहीं, इतिहास का अनुभव बताता है कि विस्तारवादी इरादों को समवेत स्वर में बोले बिना नहीं रोका जा सकता। उधर, मैक्रों के सामरिक स्वायत्तता के बयानों पर अमेरिका ने आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह ताइवान की प्रभुसत्ता का संकट मैक्रों और उनके यूरोप को 'दूर की लड़ाई' लगता है, जिसमें अमेरिका का साथ देना उसका पिछलग्गू बनना है, तो यदि अमेरिका को भी यूक्रेन के अस्तित्व का संकट या यूरोप के किसी और देश का संकट दूर की लड़ाई लगने लगे तो क्या होगा?

पुतिन के रूस की तरह बेलगाम हुए परमाणु और वीटो शक्ति संपन्न देश पर अंकुश लगाने का दुनिया के पास आर्थिक प्रतिबंध के रूप में ही एक हथियार बचा था। यह रूस के विरुद्ध पूरी तरह कारगर नहीं रहा, क्योंकि रूस के पास ऊर्जा और अनाज जैसी कुछ ऐसी चीजें थीं, जिनके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता था। साथ ही चीन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस के साथ मिलकर अपना गठजोड़ मजबूत किया, जिससे अमेरिकी खेमे का मुकाबला किया जा सके। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों को भी इस खेमे में शामिल किया जा रहा है। वैसे, चीन का तुरूप का पत्ता अपनी मुद्रा युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में खड़ा करना है। उसने रूस, खाड़ी देशों और ब्राजील को युआन में व्यापार करने के लिए राजी कर लिया है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

दोस्ती में बदल गई दुश्मनी

ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने गत दिनों बीजिंग में मुलाकात की। रमजान के महीने में सालों की दुश्मनी को भूलकर दो मुस्लिम देशों ने हाथ मिलाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों को सुधारने का फैसला मार्च में ही कर लिया था। अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने चीन के कैपिटल बीजिंग में मीटिंग की है। बताया जा रहा है कि 7 साल बाद दोनों देशों के नेताओं की यह पहली औपचारिक मुलाकात है। सऊदी अरब के चैनल अल अखबारिया ने दोनों नेताओं के बीजिंग में मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। अल अखबारिया द्वारा साझा की गई तस्वीर में सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों की मुलाकात के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं ईरान की एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच दूतावास को लेकर चर्चा हुई है।

अब सवाल यह है कि इन दोनों देशों की दोस्ती की कोशिश आखिर चीन कर क्यों रहा था? एक्सपर्ट्स की मानें तो चीन को लगता है कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से उसे फायदा हो सकता है। मालूम हो कि दोनों देश तेल के बड़े उत्पादक हैं। चीन को लगता है कि इन देशों के संबंध बेहतर होने से उसे तेल की अच्छी आपूर्ति हो सकती है। रिपोर्ट की मानें तो अमेरिका की पैठ कमजोर करने की भी चीन कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स की मानें तो दोनों देशों के बीच दोस्ती में चीन ने इसलिए दखल दिया ताकि अमेरिका की पकड़ कमजोर हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने तीसरे कार्यकाल में **शी जिनपिंग** ने ग्लोबल इनिशिएटिव की बात कही थी। उन्होंने एक दूसरे ग्लोबल ऑर्डर की भी बात कही थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से अब खाड़ी देशों में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है।

मध्य पूर्व के दो देश ईरान और सऊदी अरब लंबे समय से एक-दूसरे के दुश्मन रहे हैं लेकिन अब इनके बीच संबंध बेहतर होते दिख रहे हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब के किंग को देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले सऊदी अरब के किंग ईरान के राष्ट्रपति को रियाद की यात्रा के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच वर्षों के खराब संबंधों ने मध्य पूर्व में छद्म संघर्षों को बढ़ावा दिया, जहां तेहरान और रियाद ने यमन से लेकर सीरिया तक विपरीत पक्षों का समर्थन किया। लेकिन पिछले दिनों यह दोनों देश समझौते की टेबल तक पहुंच गए। 10 मार्च को, ईरान और सऊदी अरब ने राजनयिक रिश्ते तोड़ने के सात साल बाद संबंधों को बहाल करने की घोषणा की। दोनों देशों के करीब लाने में चीन ने अहम भूमिका निभाई। यह समझौता चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी की मध्यस्थता में हुआ। इसे मध्य पूर्व में चीन की बढ़ती भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने एक टेलीवाइज्ड न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने सऊदी की ओर से आमंत्रण मिलने के बाद बदले में सऊदी राजा को आमंत्रण भेजा है। ईरान और सऊदी अरब का आपस में राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने का फैसला एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और इस डील को कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई चीन ने जिसका एक और दूरगामी संदेश है। आइए जानते हैं ईरान-सऊदी अरब समझौते के इन दोनों अहम पहलुओं को।

सऊदी अरब एक सुन्नी बहुलता वाला देश है और ईरान शिया बहुलता वाला। इन दोनों के बीच जारी दुश्मनी का असर पूरे मध्य पूर्व में नजर आता है। जैसे कि यमन में हौथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिलता रहा है तो वहां की सरकार का साथ देने वाले सैन्य गठबंधन को सऊदी अरब का। इतना ही नहीं, लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देशों के भीतर जारी लड़ाई में ईरान एक गुट के साथ रहा है तो सऊदी अरब दूसरे गुट के साथ। ईरान और सऊदी अरब के संबंध तब और बिगड़ गए जब 2016 में सुन्नी बहुलता वाले सऊदी अरब ने 46 अन्य लोगों के साथ एक शिया मौलाना को फांसी दे दी। नतीजा ये हुआ कि तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास पर शिया प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। सऊदी अरब ने तेहरान से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। इस तरह ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध टूट गए। 7 साल बाद दोनों देशों ने इसकी बहाली का समझौता किया है। इसके दूरगामी नतीजों की उम्मीद की जा रही है। दोनों देश दो महीने के भीतर अपने अपने दूतावास खोलेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी तय हुई है। दोनों देशों ने एक-दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देने और एक-दूसरे की संप्रभुता के सम्मान का भरोसा दिया है। मिडिल ईस्ट में दोनों देशों की आपसी खींचतान खत्म होने से सुरक्षा का बेहतर माहौल बन सकेगा। इससे यमन, सीरिया, लेबनान इराक जैसे देशों की अंदरूनी लड़ाई पर भी एक हद तक नियंत्रण लग सकेगा।

● **कुमार विनोद**

मिशनों को खोलने की प्रक्रिया में जुटे दोनों देश

ईरान की अर्ध-आधिकारिक तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया कि दोनों देशों के तकनीकी प्रतिनिधिमंडल अपने मिशनों को आधिकारिक तौर पर फिर से खोलने की तैयारी कर रहे हैं और तेहरान ने कहा है कि ये मिशन 9 मई तक अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू कर देंगे। बता दें 2016 में सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने के बाद ईरानी प्रदर्शनकारी सऊदी अरब के दूतावास में घुस आए थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ संबंध तोड़ लिए थे। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर सऊदी अरब उसके साथ किसी बड़े व्यापारिक सहयोग की तरफ बढ़ेगा इस पर अभी शक जताया जा रहा है लेकिन ईरान के साथ समझौते के पीछे सऊदी अरब का यूएई के साथ प्रतिस्पर्धा को भी माना जा रहा है। सऊदी अरब को लगता है कि यूएई उससे सुन्नी प्रधानता की धुरी होने का ताज छीन सकता है। यूएई ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताकर सामान खरीदने-बेचने में मदद करता है जिससे उसे भारी मुनाफा होता है। इसलिए भी सऊदी अरब ने ईरान से रिश्ते सुधारने की तरफ कदम बढ़ाया ताकि ईरान से यूएई को मिल रहा मुनाफा उसके हिस्से भी आए।

मुस्लिम महिलाओं के अधिकार में सेंध

‘खुला का शाब्दिक अर्थ है ‘कोई चीज निकालना या दूर धकेलना।’ पति को कुछ मुआवजा देकर पत्नी द्वारा शादी खत्म करना खुला है। कुरान में खुला द्वारा विवाह को भंग करने का अधिकार केवल पत्नी को प्राप्त है पति को नहीं।’

हाल में विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले। उन्होंने उनसे कई विषयों पर बात की, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े किसी विषय पर चर्चा की? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं से जुड़े प्रश्नों पर वैसी चर्चा नहीं हो रही, जैसी होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप कुछ समय पहले मद्रास हाईकोर्ट ने जब ‘खुला’ (पत्नी द्वारा तलाक की पहल) पर फैसला दिया, तब उसे लेकर मुस्लिम समाज के बीच वैसी बहस नहीं हुई, जैसी होनी चाहिए थी।

ज्ञात हो कि मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सी. सरवनन ने वर्ष 2017 के एक मामले में तमिलनाडु तौहीद जमात की शरीयत काउंसिल द्वारा जारी खुला प्रमाण-पत्र को रद्द करते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाएं खुला के जरिए शादी खत्म करने के अधिकार का इस्तेमाल फैमिली कोर्ट में कर सकती हैं, शरीयत काउंसिल जैसी निजी संस्थाओं में नहीं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि खुला के मामले में इस तरह की निजी संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अवैध हैं। यह एक अति महत्वपूर्ण फैसला है। अब जरूरी है कि तीन तलाक की तरह ही खुला पर भी बहस अपने अंजाम तक पहुंचे। यहां यह जानना जरूरी है कि खुला क्या है? खुला का शाब्दिक अर्थ है ‘कोई चीज निकालना या दूर धकेलना।’ पति को कुछ मुआवजा देकर पत्नी द्वारा शादी खत्म करना खुला है। कुरान में खुला द्वारा **विवाह को भंग** करने का अधिकार केवल पत्नी को प्राप्त है, पति को नहीं। इसके लिए उसे न तो पति की सहमति लेने की जरूरत है और न ही किसी काजी-मौलवी के पास जाने तथा उनकी रजामंदी लेने की। पत्नी स्वयं अपने पति को खुला भेज सकती है और शादी को भंग कर सकती है। यह विशेषाधिकार उसे प्राप्त है। इस प्रकार तलाक और खुला का असर एक ही है, वह है शादी को बर्खास्त करना।

खुला की वैधता के संबंध में कई ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। जैसे-कुरान (2:229), हदीस बुखारी (68:11), मुंशी बुजलुल रहीम बनाम लतीफुन्निसां वाद (1861) तथा 1945 में उप्र के सीतापुर जिले में शफीकुन पुत्री करीम बख्श द्वारा अपने पति मोहम्मद इस्हाक को आठ आने के स्टाम्प पेपर पर खुलानामा भेजकर अपनी शादी को बर्खास्त करना। ये चार तथ्य यह साबित करते हैं कि महिलाएं खुला बहुत आसानी से लेती रही हैं। उनके लिए पति की सहमति की जरूरत नहीं थी।

समय के साथ पितृसत्ता की मजबूत जड़ों और मौलवियों के वर्चस्व ने महिलाओं के उस अधिकार में सेंध लगा दी, जिसका प्रयोग कर वे पति से छुटकारा पा सकती थीं। इस अधिकार में मजहबी संस्थाएं रोड़ा बन चुकी हैं। पिछले दो-तीन दशकों में मजहबी संगठन बहुत तेजी से उभरे हैं। उनके द्वारा तैयार दस्तावेजों में लिखा गया कि खुला के लिए पति की सहमति जरूरी है। ये दस्तावेज कुरान में महिलाओं को दिए अधिकारों से मेल नहीं खाते, परंतु वे अदालतों तक भी पहुंच गए। इसी का परिणाम हुआ कि महिलाएं खुला पाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हो गईं।

कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं ने जब भी अपने पतियों से खुला पर सहमति मांगी तो उन्होंने प्रतिशोधवश सहमति देने से इनकार किया। धार्मिक संगठनों ने महिलाओं को उसी घर में भेज दिया, जहां उन पर हिंसा हो रही थी। ऐसी स्वनिर्मित अदालतों को समाप्त किया जाना महिलाओं के हक में एक बेहतर कदम तो होगा ही, साथ ही समाज में गैर-बराबरी की जड़ों पर भी चोट करेगा। पितृसत्ता के इन पहरेदारों ने अपनी अलग विधि ही ‘कवानीने इस्लामी’ के नाम से बना डाली, जो पूर्णत: अमानवीय है। हमने तीन तलाक के संबंध में महिलाओं के संघर्ष के दौरान भी ऐसा ही देखा कि तीन तलाक को सही साबित करते हुए मौलवी सड़कों पर उतर आए थे, परंतु न्यायालय ने कुरान के संदर्भ को ही सही मानते हुए तीन तलाक पर पाबंदी का ऐलान किया।

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला इस मायने में अहम है कि शरीयत के नाम पर गली-गली फैली अदालतें **नाइंसाफी** पर टिकी हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को खुला, तीन तलाक, तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-एहसन, फस्ख निकाह कराने के लिए बैठी हैं। ऐसी उम्मीद जगी है कि अब उन पर देशभर में रोक लग सकेगी। जब ऐसी शरई अदालतों के प्रमाण-पत्र कहीं मान्य ही नहीं होंगे तो महिलाएं वहां जाएंगी ही क्यों? भारत में आज जो मुस्लिम विधि लागू है वह हनफी विधि है, जो 1937 में मौलवियों द्वारा होशियारी से न्यायालयों में स्थापित करा दी गई। इस विधि के अंतर्गत भी खुला के लिए पति की सहमति अनिवार्य मानी जाती है। नशे की हालत में भी यह सहमति वैध है। ऐसा एक वाद रशीद अहमद बनाम अनीसा खातून में भी देखा गया।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई

मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। बात सहमति की है ही नहीं। बात यह है कि कुरान में पति की सहमति-असहमति का उल्लेख ही नहीं है। यहां स्वेच्छा से पति की सहमति का पेंच लगाकर खुला का अधिकार भी पति को ही दे दिया गया है। इस तरह फैमिली कोर्ट से भी मुस्लिम महिला को खुला का प्रमाण-पत्र हासिल करना आसान नहीं होता। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए, नहीं तो कोर्ट में भी इस कमजोर कानून का लाभ पितृसत्ता के पहरेदारों को ही मिलेगा और मुस्लिम महिलाएं वहां भी इंसाफ पाने से वंचित रह जाएंगी। हां, इस परिदृश्य में समान नागरिक संहिता का प्रश्न वैकल्पिक रूप में बना रहे तो कोई हर्ज नहीं।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

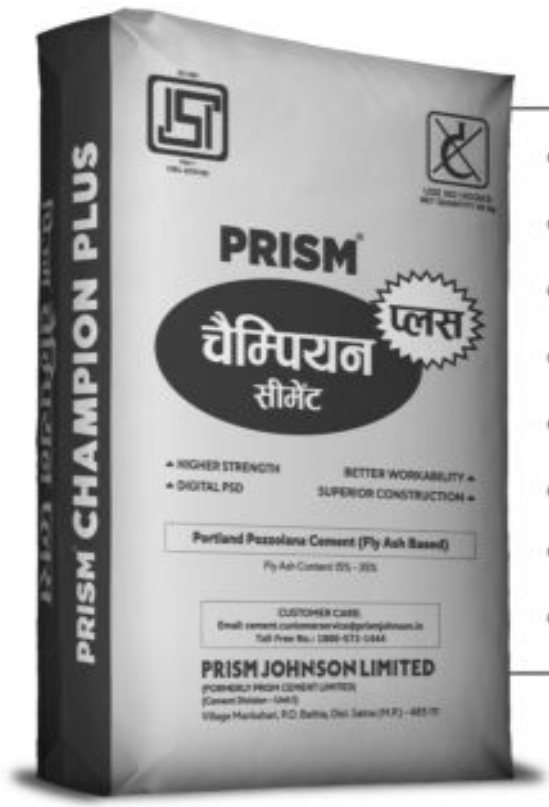

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

वृद्धाश्रम

आज वृद्धावस्था आश्रम में कुछ खास दिन है सब लोग तैयारी कर रहे है। रेवती जी रसोई में खीर बना रही हैं आज सावित्री जी का जन्मदिन है।

शाम को सब बुजुर्ग हाल में एकत्रित हुए और सभी हाथ जोड़कर उनके स्वस्थ होने की प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे।

उनकी आठ दिन से तबियत ठीक नहीं है, सब लोगों ने उनसे केक कटवाया। और सबने मिलकर खाया सावित्री जी की खुशी से आंखे भर आईं और वे बोली- आज तक मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया लेकिन आज तुम सबने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी।

यह कहकर वो मुस्कराने लगीं और सोचने लगी अपनों ने साथ छोड़ दिया लेकिन वृद्धावस्था में आकर मैंने अपनों का साथ पाया।

बड़े बुजुर्गों को बोझ न समझे उनको भी आपके साथ खुशी मनाने का अवसर दें और उनका सम्मान करें उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत फलदायी होता है।

- पूनम गुप्ता

मुहूर्त

संगीत लहरियां पूरे हाल में गूंज रही थीं, विद्युत सज्जा से हाल जगमगा रहा था। फूलों से सज्जित मंच पर दूल्हा-दुल्हन सभी से बधाइयां, आशीर्वाद, तोहफे प्राप्त कर रहे थे।

आज रामजी की बेटी सलौनी के शादी का स्वागत समारोह था।

रामजी को याद आ रहा था 6 माह पूर्व जब सलौनी की शादी सुकुमार जी के बेटे आदित्य से तय हुई थी तथा शादी का मुहूर्त निकला था 6, 7 या 8 दिसंबर। रामजी तत्परता से भागे शादी हाल बुक कराने। हर जगह सारे हाल पहले से बुक हो चुके थे। सभी ने सलाह दी कि शादी की तारीख अगले साल तक के लिए बढ़ा दें। वो फौरन सुकुमार जी के पास दौड़े विवाह की तिथि बढ़ाने के लिए, मगर सुकुमार जी नहीं माने क्योंकि उनके बेटे को दिसंबर के अंत में कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जाना था।

रामजी निढाल से घर लौटे। घर में बेटी ने समस्या सुना फिर वो भी सोच में डूब गई। शाम को बेटी को कुछ सूझा। उसने पिता को बताया, पिता ने सुकुमार जी से पूछा तो उन्होंने हामी भर दी। सभी रिश्तेदारों को तदानुसार खबर कर दिया गया।

बेटी ने कहा था- ठीक है पिताजी विवाह मुहूर्त में ही समीप के मंदिर में कर दीजिए और मुहूर्त के बाद किसी शानदार होटल में स्वागत समारोह।

- महेंद्र कुमार वर्मा

मानस में सवेद नहीं...

देश-वेश परिवेश धर्म का,
मन में कुछ भी भेद नहीं।
देख लिए पतझड़-बसंत,
अब जाने का है खेद नहीं।।
सर्दी की ठंडक में ठिठुरा,
गर्मी की लू झेली हैं,
बरसातों की रिम-झिम से,
जी भरकर होली खेली है,
चप्पू अब भी सही-सलामत,
नौका में है छेद कहीं।
देख लिए पतझड़-बसंत,
अब जाने का है खेद नहीं।।
सुख में जी भरकर मुस्काया,
दुख में कभी नहीं रोया,
जीवन की नाजुक घड़ियों में,
धीरज कभी नहीं खोया,
दुनिया भर की पोथी पढ़ लीं,
नजर न आया वेद कहीं।
देख लिए पतझड़-बसंत,
अब जाने का है खेद नहीं।।
आशा और निराशा का,
संगम जीवन परिभाषा है,
कभी गरल है, कभी सरल है,
जीवन एक पिपासा है,
गलियों-गलियों में मक्कारी,
दिखा कहीं श्रम-स्वेद नहीं।
देख लिए पतझड़-बसंत,
अब जाने का है खेद नहीं।।
दुनियाभर में हिंसा का,
परिवेश नजर आता है,
'रूप' आदमी का लोगों को,
अब तो बहुत डराता है,
मानव-दानव बन बैठा है,
मानस में संवेद नहीं।
देख लिए पतझड़-बसंत,
अब जाने का है खेद नहीं।।

- (डॉ. रूपचंद्र शास्त्री 'मयंक')

इतिहास रचने से एक कदम दूर

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब इंग्लैंड के ओवल में आमने-सामने होंगी, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंचने वाली इन टीमों का मैच 7 से 11 जून के बीच खेला जाएगा। यह लगातार दूसरी बार हुआ है, जब टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंची है जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए यह पहला मौका है। टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप समेत कई आईसीसी इवेंट्स में लगातार हार चुकी है। ऐसे में अब उसके पास मौका है कि वह आईसीसी ट्रॉफी के 10 साल के सूखे को खत्म करे। इस खिताबी जंग के लिए दोनों देशों ने अपनी-अपनी टीमों का ऐलान भी कर दिया है। भारत की ओर से अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी हुई है। उन्हें पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद बाहर कर दिया गया था। रहाणे के अलावा टीम में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की भी वापसी हुई है। वहीं रोहित शर्मा टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। उनके साथ टीम में शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रहाणे और केएल राहुल हैं। विकेटकीपर के तौर पर केएस भरत का चयन हुआ है। तेज गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जयदेव उनादकट हैं। वहीं, स्पिन विभाग की जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा के ऊपर होगी।

दूसरी तरफ बीते कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया की ओर से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए टीम का ऐलान किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। टीम में ऑलराउंडर मिचेल मार्श और बल्लेबाज मार्कस हैरिस को शामिल किया गया है। दोनों ही खिलाड़ी लंबे वक्त से टेस्ट टीम से बाहर थे। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। इंग्लिस ने अब तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, ऐसे में वह अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। वहीं कप्तान पैट कमिस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड के रूप में चार तेज गेंदबाज शामिल किए गए हैं, जबकि कैमरून ग्रीन और मिचेल मार्श के रूप में दो ऑलराउंडर टीम का हिस्सा हैं।

खास बात यह है कि कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2023 में 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। भारतीय टीम ने इस सीरीज को जीतने के साथ इतिहास रचा है, क्योंकि टीम इंडिया लगातार चौथी बार ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में पटखनी देने वाली टीम बन गई है। पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड देखें तो टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में दबदबा देखने को मिला है। विराट कोहली की अगुवाई में जो मिशन शुरू हुआ था, अब रोहित शर्मा की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। टीम इंडिया विराट कोहली की अगुवाई में लगातार 4 साल टेस्ट क्रिकेट में नंबर-1 रही थी, साथ ही वह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पहले संस्करण में फाइनल में पहुंची थी। अब रोहित शर्मा की अगुवाई में भी टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंची है।

ऐसा कम ही देखने को मिला है कि टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया पर इस तरह का दबदबा देखने को मिला है, सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं बल्कि किसी भी टीम का ऑस्ट्रेलिया पर इतना बेहतरीन दबदबा बेहद कम देखने को मिलता है। गौरतलब है कि पिछली बार भारत टेस्ट चैम्पियनशिप के खिताबी मुकाबले में हार गया था लेकिन इस बार उसके मौजूदा प्रदर्शन को लेकर उम्मीद की जा रही है कि वह खिताबी मुकाबला जीतकर इतिहास रच सकता है। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंची है। उसे पिछली बार 2021 में खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया ने टेस्ट चैम्पियनशिप के 2021-23 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। वह ऑस्ट्रेलिया के बाद अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही।

मुकाबले में टीम इंडिया का दबदबा ऑस्ट्रेलिया पर देखने को मिलेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल का टिकट जरूर पक्का किया था लेकिन भारत ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से अपने नाम की थी। भारत के इस बेहतर प्रदर्शन को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार टीम इंडिया के पास खिताब जीतने का ज्यादा अच्छा मौका होगा। क्योंकि उनकी टीम काफी मजबूत है, जो हाल में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी देखने को मिली थी। जिस तरह से वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बना सकते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी काफी अच्छी टीम है, लेकिन इंग्लैंड की परिस्थितियां अलग होती हैं। मगर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कोहली के बल्ले से जिस तरह काफी समय बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट शतक निकला था, उससे वे फॉर्म में लौट चुके हैं जो विरोधी टीम के लिए खतरे की बात है। वह वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, जो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रन बना सकते हैं।

● आशीष नेमा

भारत-ऑस्ट्रेलिया का आमना-सामना

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 106 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 44 और भारत ने 32 जीते हैं। 29 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। एक मैच टाई रहा है। भारत में खेले गए टेस्ट मैचों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच यहां 54 मैच खेले जा चुके हैं। भारत ने 23 और ऑस्ट्रेलिया ने 14 जीते हैं। 16 मैच ड्रॉ रहे हैं और एक टाई हुआ है। **ऑस्ट्रेलिआई टीम-** पैट कमिस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, मार्कस हैरिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल मार्श, टाड मर्फी, मैथ्यू रेनशा, स्टीव स्मिथ (उपकप्तान), मिशेल स्टार्क और डेविड वार्नर। **भारतीय टीम-** रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, केएस भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकट।

एक्टर ने रवीना टंडन को दिया था ऑफर... एक्टिंग छोड़ दो, शादी कर लूंगा

रवीना टंडन अपने जमाने की टॉप अभिनेत्रियों में से रही हैं। एक समय पर हर तरफ बस उन्हीं के चर्चे होते थे। अपनी जबरदस्त एक्टिंग के दम पर वह कभी फिल्मी दुनिया पर राज करती थीं। इस दौरान रवीना एक सीरियस रिलेशनशिप में भी रहीं। ये एक्टर थे अक्षय कुमार, जिनके साथ बात शादी तक पहुंच चुकी थी। लेकिन, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया।

बाद में अभिनेत्री ने अनिल थडानी से शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। इस बीच रवीना टंडन का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में है, जिसमें वह एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करती नजर आ रही हैं, जिसने उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने और शादी का ऑफर दिया था। रवीना टंडन को मोहरा से इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। अपनी फिल्म के साथ ही वह टिप टिप बरसा पानी के लिए भी वह खूब मशहूर हुईं। इसके अलावा वह अपने रिलेशशिप के चलते भी खूब चर्चा में रहीं।

रवीना टंडन ने एक चैट शो में अपने अफेयर और शादी को लेकर बात की थी। उन्होंने शो में बताया था कि कैसे एक शख्स ने उन्हें ये कहते हुए शादी का ऑफर दिया था कि वह एक्टिंग छोड़ दें। रवीना इसमें किसी के बारे में बात कर रही हैं और बता रही हैं कैसे उस शख्स ने उन्हें अपना कैरियर छोड़ने की बात कही थी। इंटरव्यू में रवीना ने कहा था- उस एक्टर ने कहा था कि जब तुम्हारी शूटिंग का आखिरी दिन होगा, हम शादी कर लेंगे।

जब फिरोज खान ने बंदूक दिखाकर पूछा-फिल्म करोगे, उड़ गए थे अभिनेता के होश

फिरोज खान अपने दौर के हैंडसम एक्टर्स में शुमार थे। उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में काफी फेम कमाई, साथ ही हमेशा अपने हिसाब से काम किया। बेटे फरदीन खान को लॉन्च करने लिए फिरोज खान ने प्रेम अगन बनाई थी। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के पिता के किरदार के लिए वे अनुपम खेर को लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनुपम को एक दफा घर बुलाया। जब अनुपम वहां पहुंचे तो फिरोज ने ग्रीन लुंगी और कुर्ता पहना हुआ था। अनुपम को देखकर उन्होंने बैठने के लिए कहा और पूछा क्या पीओगे। इसी दरमियान फिरोज ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और टेबल पर रख दी। यह देखकर अनुपम को कुछ अजीब लगा। इसके बाद फिरोज ने बताया कि मैं तुम्हें हीरोइन के पिता का रोल देना चाहता हूं क्या तुम करोगे? अनुपम को लगा बंदूक दिखाकर फिरोज डराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा, हां, बिल्कुल करूंगा। फिरोज ने जब अनुपम को देखा तो वह बार-बार सिर्फ रिवॉल्वर की तरफ ही देख रहे थे, यह देखकर फिरोज, अनुपम की स्थिति समझ गए। उन्होंने तुरंत रिवॉल्वर हटाकार सॉरी कहा और फिर पूछा अब बताओ फिल्म करोगे? इस बार भी अनुपम ने हां ही कहा क्योंकि वे फिरोज के साथ काम करना चाहते थे। बाद में अनुपम को पता चला कि फिरोज ने रिवॉल्वर एक सीन को समझाने के लिए निकाली थी।

जब काम मांगने गए थे मिथुन चक्रवर्ती, डायरेक्टर ने दरवाजे से भगाया था

बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती आज भले ही फिल्मों में ज्यादा काम नहीं कर रहे हों लेकिन आज भी फिल्मी दुनिया में उनके दीवाने कम नहीं हैं। आज भी लोगों के दिलों में वह बसते हैं और उनकी डांसिंग स्टाइल कॉपी करने का मजा लूटते हैं। लेकिन आज सफलता के शिखर पर पहुंच चुके मिथुन की जिंदगी हमेशा से इतनी सफल नहीं थी। कड़े संघर्ष के बाद उनकी किस्मत का सितारा चमका था। मुंबई फिल्मों में हीरो बनने के लिए आए मिथुन को एक डायरेक्टर ने चुनौती तक दे दी थी कि अगर तुम हीरो बन गए तो मैं खुद तुम्हें अपनी फिल्म में साइन करूंगा। दरअसल, मनमोहन

देसाई ने पहली नजर में ही मिथुन को रिजेक्ट कर दिया था। निर्देशक उन दिनों अपनी फिल्मों में ज्यादातर अमिताब बच्चन को लिया करते थे। उस दौर में धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे हीरो का बोलबाला था। ये वो वक्त था जब मिथुन कुछ फिल्में कर चुके थे लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली थी, जिसके वह हकदार थे। एक दिन वह मनमोहन देसाई के पास काम मांगने पहुंचे, उन्होंने मिथुन को देखते ही कहा कि फिल्म में छोटा-मोटा रोल दे दूंगा। लेकिन मिथुन ने उनसे कहा कि वो हीरो बनने आए हैं। उस दिन उन्होंने मिथुन से कहा कि फिल्में बनाई ही नहीं बेची भी जाती हैं। काले-कलूटे हीरो को कौन देखना पसंद करेगा भाई। उसी दौरान मिथुन रंगभेद का भी शिकार हुए थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम हीरो बन गए तो मैं खुद तुम्हें अपनी फिल्म में साइन करूंगा। अपमान सहते हुए वहां से चुपचाप निकल गए। खैर आज मिथुन सुपरस्टार हैं।

कालोनी में इकलौता हमारा ही दरवाजा रह गया है, जहां पर पुलिसिया चरण-रज नहीं पड़ी। एक बार तो उनके पांव छापेमारी के बहाने डलवा ही लीजिए। अब तो मुझे शर्म आने लग गई है। वर्माइन चिढ़ाती हैं। शर्माइन अपना मुंह फेर लेती हैं। मिसेज कुलकर्णी ऐंठी घूमती हैं।

सूखे सन्नाटे में जीने का दुख

इन दिनों श्रीमती जी रोज ही ताने मारती रहती हैं। वह कहती हैं, आपको अपने खानदान की इज्जत का डालर बराबर भी खयाल नहीं। कभी तो ऐसा कुछ कीजिए कि हमारे दरवाजे पर भी दो-चार पुलिस वाले दर्शन दें। मोहल्ले में कभी हमारी नाक भी ऊंची हो। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपने पड़ोसी वर्मा भाई साहब के यहां छापा पड़ चुका। शर्मा जी के यहां से जमाखोरी का जखीरा बरामद हो चुका। चार मकान आगे वाले कुलकर्णी को तो भ्रष्टाचार की शिकायत पर सीबीआई वाले दिन दहाड़े उठा ले गए थे। कोने वाले खन्ना जी ने तो सुनती हूं, ऐसी घोटालेबाजी कर रखी है कि ईडी की गिरफ्त में एक बार आए तो आज तक वहीं पर सवालों के जवाब दे रहे हैं।

अब कालोनी में इकलौता हमारा ही दरवाजा रह गया है, जहां पर पुलिसिया चरण-रज नहीं पड़ी। एक बार तो उनके पांव छापेमारी के बहाने डलवा ही लीजिए। अब तो मुझे शर्म आने लग गई है। वर्माइन चिढ़ाती हैं। शर्माइन अपना मुंह फेर लेती हैं। मिसेज कुलकर्णी ऐंठी घूमती हैं। खन्ना की घरवाली ठीक से बात तक नहीं करती। आपको अपनी प्रतिष्ठा का तो खयाल है नहीं, मेरी इज्जत का तो कचरा मत कीजिए।

सच कहती हैं श्रीमती जी। पत्नी का सम्मान रखना प्रत्येक पति का धर्म होता है तो मुझे भी ऐसा कुछ करना ही चाहिए कि घर-परिवार में शांति कायम रहे। मेरे मित्र मिश्राजी से मैंने इस बाबत चर्चा की। वह बोला, यार, परसों तक मैं भी इसी प्रकार की प्रतिष्ठा के सवाल में उलझा हुआ था। भला हुआ कि कल दो पुलिस वाले घर आ गए। अपनी तो नाक कटने से बच गई। मैंने कहा, भाई मिश्रा, तुम तो शरीफ बंदे हो। तुम्हारे घर पुलिस वाले काहे को आए थे? मिश्रा हंसता हुआ बोला, प्यारे भाई, मैंने अपने बेटे के रिवाल्वर के लिए आवेदन किया था। वे दोनों उसी के वेरीफिकेशन के लिए आए हुए थे। गली वालों को क्या पता, खुसर-फुसर करने लग गए।

एक-दो ने पूछा तो मैंने भी जानबूझकर गोलमोल जवाब दे दिया। उनको भरोसा हो गया, यह मिश्रा पक्का किसी जालसाजी में फंस गया है। अब मैं मोहल्ले में चौड़ा होकर निकलता हूं। हर दूसरा आदमी सलाम मारता है। पड़ोसियों के बदमाश छोरे पांव छूकर आशीर्वाद मांगते हैं। पड़ोसिन सम्मान की दृष्टि से देखती हैं। रिश्तेदारों को भी खबर हो ली है। बधाइयां मिल रही हैं। तो पांडेजी, तुम भी ऐसा करो कि येन-केन या फिर लेन-देन प्रकारेण अपने दरवाजे पर पुलिस के पांव पड़वा ही डालो। तभी घर वालों की ही नहीं, समाज की निगाह में सिर उठाकर जीने के लायक हो सकोगे।

सच बात है। आज के धिक्कारग्रस्त समय में वही व्यक्ति सीना चौड़ा करके रह सकता है, जिस पर दो-चार मुकदमे चल रहे हों, जो हवालात के सवालात पर अग्रिम रहे या फिर अग्रिम जमानत पर रहे, जिसका अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर नाम छपे, जिसके चेहरे पर कैमरे की फ्लैश लाइट चमके, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हो और आगे मीडिया वाले। वरना सूखे सन्नाटे में जीना भी कोई जीना है लल्लू! तो मुझे क्या करना चाहिए?

मैंने अपनी अंतरात्मा से पूछा। वह अभी पूरी तरह से सोई नहीं थी। सो उसने तत्काल उत्तर दिया, अबे अहमक, समय के साथ चलना सीख। चौराहे का रुख कर। किसी ड्यूटी के पैबंद सिपाही को सौ-पचास का नोट पकड़ा। उसको अपने घर बुला ला। कहना, वर्दी में आए। दो-चार पड़ोसियों की काल बेल बजाए। उनसे तुम्हारे बारे में पूछताछ करे। यह न बताए कि किस वास्ते आया है? फिर देखना, तू रातोंरात किस तरह से सम्माननीयों की श्रेणी में सूचीबद्ध हो लेता है!

जागृत इंसान वही है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। इसी अंतरात्मा की आवाज पर सैकड़ों नेताओं ने दल बदल किए। निष्ठाएं बदल लीं। घोटाले किए। कर रहे हैं। मैं भी अपनी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने के नाम पर दो पुलिस कर्मियों को पेशगी दे आया हूं। जल्द ही हमारे यहां भी पुलिस वाले आएंगे। हो सकता है, घर से दो आलुओं को सोना समझकर उनकी बरामदगी भी कर लें। अपनी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखता हूं, बचती है कि लुटती है।

● **सूर्यकुमार पांडेय**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

इस संकल्प ने हमारे
मन-मानस में गहरी जड़ पकड़ ली है।

कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की वृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company

प्रकृति के अस्तित्व में ही
हमारा अस्तित्व है